हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

16 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 16 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(3)20
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(3)25
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं	(3)29
मुख्य संसदीय सचिव श्री श्याम सिंह राणा को उनकी सद्भावना(हारमोनी) पदयात्रा के लिए बधाई।	(3)30
आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र जिला हिसार के गांवों में हाल ही में हुई वर्षा और ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मामला उठाना	(3)32

मूल्य :

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

कैंसर तथा हैपेटाईटिस-बी और सी संबंधी (3)33

वक्तव्य-

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (3)34

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव (3)46

एस.वाई.एल. नहर के संबंध में श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा दिये गये वक्तव्य का मामला उठाना। (3)47

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ (3)48

बैठक का समय बढ़ाना (3)76

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) (3)77

बैठक का समय बढ़ाना (3)79

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) (3)79

बैठक का समय बढ़ाना (3)81

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) (3)81

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 16 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल होगा।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Lay Sewerage and Drinking Water System

***1123. Shri Jai Parkash :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under condideration of the Government to lay sewerage and drinking water supply system in Municipal Area of Rajond Town of Kalayat Assembly constituency; if so, details thereof togetherwith the time by which the proposal is likely to be materialized?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : श्रीमान, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

वर्तमान में, शहरी क्षेत्रों के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त जल मात्रा उत्पादन करने हेतु जलघर निर्माण के लिए तथा मलशोधन संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि उपलब्ध होते ही शीघ्र प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं राजौंद में इन दोनों कामों के लिए जमीन मिल सकती है। बीर बांगड़ एक ऐसा गांव है जहां आई.टी.आई. बनी हुई है और वहां स्टेडियम भी बनेगा। उसके साथ लगती जितनी जमीन इस काम के लिए चाहिए सरकार उतनी जमीन देने के लिए तैयार है। इसके अलावा थोड़ी दूरी पर असंध रोड पर म्युनिसिपल कमेटी की एक दूसरी जमीन भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी प्रपोजल को स्वीकार किया है। अध्यक्ष महोदय, राजौंद कस्बे की आबादी 30 हजार के लगभग है और यह कस्बा अब टाऊनशिप में बदल चुका है। यहां वाटर सप्लाई की प्रोब्लम है और सीवरेज के सेफ्टी टैंक भी गलियों में हैं और गलियां बहुत ही संकीर्ण हैं। पूरे गांव में सीपेज की प्रोब्लम है क्योंकि ये गांव बहुत पुराना है और घर बहुत पुराने बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, सीपेज की वजह से कभी भी कोई बिल्डिंग गिर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इन कामों के लिए हमारे यहां जमीन उपलब्ध है और यदि जमीन उपलब्ध नहीं भी है तो मैं निवेदन करूंगा कि जमीन एक्वायर करके इस काम को करवाया जाए क्योंकि यह काम अतिआवश्यक है।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि राजौंद में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। वहां दो नहरी पानी आधारित जलघर हैं, दो नलकूप हैं और एक बुस्टिंग स्टेशन है। राजौंद के 60 प्रतिशत क्षेत्र में

[श्री घनश्याम सर्राफ]

जल की आपूर्ति पूरी है। शहर में सीवरेज प्रणाली नहीं है। विभाग द्वारा जैसे ही जमीन आइडैंटीफाई होती है निश्चित रूप से हम इनकी दोनों मांगें पूरी कर देंगे। वहां जलघर का भी निर्माण कर दिया जाएगा और एस.टी.पी. भी बना दिया जाएगा।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी दोनो मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि इनके यहां बस अड्डे के पास जो जमीन पड़ी है उसका प्रस्ताव बनवाकर नगर पालिका से पास करवा कर भिजवा दें, उस पर जलघर बनवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि दोनों कामों के लिए जमीनें एक दूसरे से दूरी पर होनी जरूरी हैं।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के आदमपुर में लाईन पार जवाहर नगर है जहां थोड़ी सी बरसात होने के बाद लोग घर के बाहर पैर नहीं रख सकते क्योंकि वहां की सीवरेज व्यवस्था बहुत खराब है और यही हालत हांसी तथा हिसार की है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जवाहर नगर, हांसी और हिसार शहर की सीवरेज व्यवस्था ठीक करवाई जाये। मैंने पिछली सरकार के समय में और उससे पिछली सरकार के समय में वहां की सीवरेज व्यवस्था ठीक करवाने की कोशिश की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिसार शहर का सीवरेज सिस्टम 1996 में चौधरी भजन लाल जी के मुख्यमंत्री काल में बना था। अब वहां का सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आदमपुर मण्डी, हिसार शहर, जवाहर नगर, हांसी शहर की सीवरेज व्यवस्था ठीक करने के बारे में मैंने कई पत्र मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को एक साल में लिखे हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से प्रार्थना है कि मेरे पत्रों को रद्दी की टोकरी मे न डालकर उन पर कार्रवाई की जाये।

श्री घनश्याम सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जब भी माननीय साथी का कोई पत्र मेरे पास या मुख्यमंत्री जी के पास आया है तो उस पर हमने कार्रवाई करते हुए सीवरेज सिस्टम की सफाई करवाई है। यदि वहां पर ड्रेनेज की समस्या है तो उसको भी चैक करवाकर हम कार्रवाई करेंगे।

श्री कुलदीप बिश्नौई : अध्यक्ष महोदय, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

To Metal the Passages

***1213. Shri Randhir Sinng Kapriwas :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that 5 Karam, 4 Karam, 3 Karam and 2 Karam passages in Rewari area connecting one village to another village are not being metalled by the PW (B&R) department due to the breadth less than 33 feet; and

(b) if so, whether the Government will take any steps to solve the above said problem?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) समान्यत वहाँ सड़क बनाता है, जहाँ पर भूमि की चौड़ाई 6 करम या उससे ज्यादा उपलब्ध हो। यदि पर्याप्त भूमि न हो तो अतिरिक्त भूमि अधिग्रहीत की जाती है या इच्छुक व्यक्तियों से अनुदान द्वारा प्राप्त होती है।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन यह है कि दक्षिणी हरियाणा स्पेशली नारनौल, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी में लोगों के पास लैंड होल्डिंग कम है और वहां पर छोटे किसान हैं। चकबंदी में लैंड होल्डिंग कम होने के कारण वहां 6 करम और 7 करम के रास्ते बहुत कम हैं। वहां पर ज्यादातर 4 या 5 करम के रास्ते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन एरियाज के लिए पॉलिसी में ढ़ील देकर इन रास्तों को पक्का किया जाए या सरकार जमीन एक्वायर करके इन 4 या 5 करम के रास्तों को चौड़ा करके वहां सड़क बनाई जाए।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जो सड़क से जुड़ा हुआ न हो। जहां पर ज्यादा जरूरत होती हैं वहां पर 6 करम से छोटे रास्तों को मार्केटिंग बोर्ड बनाता है। यदि माननीय सदस्य के हल्के में कोई ऐसा गांव है जो सड़क से जुडा हुआ नहीं है तो उस बारे में हमें बता दें, वहां पर सड़क बनाने के लिए हम सोच विचार कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई गांव है तो वहां पर मार्केटिंग बोर्ड या पी.डब्ल्यू.डी. सड़क बना देगा।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे हल्के में कालवन से कमालवाला सड़क है। वहां पर 6 कर्म का कच्चा रास्ता है। वह रास्ता आज तक कच्चा ही है और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है इसलिए वह रास्ता जल्द बनवाया जाये।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि यदि उस गांव की आबादी 500 से ज्यादा है और 6 करम का रास्ता है तथा वह गांव सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर सड़क बना दी जायेगी।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह बहुत बड़ा गांव है और सुभाष बराला जी भी इस बारे में जानते हैं।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पहले से ही मंत्री जी को लिखकर दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। इससे बड़ी और क्या बात होगी ?

ØAOÆü
¤ü»ÖÖ»Ö]

Widening of Road

***1153. Shri Ravinder Baliala :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state :-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen and strengthen the road from village Rattangarh to Mofar (Punjab Border); and

(b) if so, the time by which the above said road is likely to be widened and strengthened ?

लोक निर्माण विभाग मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) इसलिए, यह प्रश्न ही नहीं उठता ? अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह सड़क पंजाब को जोड़ती है और तकरीबन 17.13 कि.मी. लम्बी है। 16 कि.मी. पी.डब्ल्यू.डी. की है और 1.13 कि.मी. मार्केटिंग बोर्ड की है और 12 फीट चौड़ी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस सड़क को हम 2016-17 के बजट में बनवा देंगे और इसकी चौड़ाई 18 फीट कर देंगे।

श्री रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे रतिया हल्के में बहुत से ऐसे गांव हैं जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं उनकी लिस्ट मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा कृपा करके उन गांवों को भी सड़क से जुड़वाया जाये। क्योंकि पिछले प्रश्न के जवाब में मंत्री जी कह रहे थे कि जो गांव सड़क से नहीं जुड़े हुए वहां सड़क बनवा दी जायेगी।

श्री नरबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी उनकी लिस्ट मेरे पास भिजवा दें हम जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे।

Building of CHC Chaurmastpur

***1266. Shri Aseem Goel :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that the building of CHC Chaurmastpur (Ambala) is in dilapidated condition; if so, the time by which the new building of CHC Chaurmastpur (Ambala) will be constructed togetherwith the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हाँ श्रीमान जी। आवश्यक स्वीकृतियों उपरान्त तुरंत नए भवन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि यह इमारत वर्ष 2009 में कण्डम घोषित की जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी आज सात साल बाद भी उसी जीर्ण-शीर्ण बिल्डिंग में अस्पताल को चलाया जा रहा है। आज वहां पर यह आलम है कि कमरों के बजाय वहां पर गैलरी में मरीज़ों को एडमिट किया

जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां पर सारे के सारे कमरे टूट चुके हैं। इससे पहले कि वहां पर कोई जान माल का नुक्सान हो वहां पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाये ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जो असीम गोयल जी कह रहे हैं यह बिल्कुल सत्य बात है। यह सी.एच.सी. सन् 1977 में बनी थी और अब यह बिल्कुल कण्डम हो चुकी है। यहां तक कि जो रिहायशी मकान हैं वे भी अब कण्डम हो चुके हैं। हमने इसके नक्शे और एस्टीमेट्स बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की हुई है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वर्ष में हम इसके ऊपर ज़रूर कार्य आरम्भ कर देंगे।

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि यह सी.एच.सी. बहुत ही लो-लाईन एरिया में है। मैंने स्वयं इसका फोलो-अप लिया था। यह मामला डेढ़ साल से चला आ रहा है। मेरे विचार में यह पी.डब्ल्यू.डी. और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच में डेढ़ साल से फुटबॉल का एक फ्रैंडली मैच चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हम इसको कण्डम कैसे घोषित करें और पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अधिकारी कह देते हैं कि जब तक हमारे पास इसके कण्डम होने की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक हम इसके एस्टीमेट्स नहीं बना सकते। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे कृपया इन दोनों विभागों के अधिकारियों का को-आर्डीनेशन करवाकर इस काम को तुरंत शुरू करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं असीम गोयल जी से कहना चाहूंगा कि विधान सभा का यह सैशन खत्म होते ही मैं सभी कंसर्ड अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर उस एक ही मीटिंग में ही सारे के सारे फैसले करवा दूंगा।

श्री हरविन्द्र कल्याण : स्पीकर सर, इसी प्रकार की एक समस्या मेरे घरौंडा विधान सभा क्षेत्र की भी है। वह पी.एच.सी. सन् 2002 में मंजूर हुई थी। कई सरकारें आई और चली गई लेकिन वहां पर आज भी 13-14 वर्ष के बावजूद भी उस पी.एच.सी. की बिल्डिंग नहीं बनी है। वहां पर पी.एच.सी. चल रही है। मैं बरसत और चौरा दो गांवों की बात कर रहा हूं ये दोनों गांव ही हमारे बहुत बड़े सैंटर हैं और ये दोनों गांव हमारे इंटीरियर में यमुना के साथ पड़ते हैं। इन दोनों गांवों में लोगों को स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। इस कारण से वहां पर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं मुहैया करवाई जानी चाहिएं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पी.एच.सी. का निर्माण भी जल्दी से जल्दी करवाया जाये।

श्री कुलदीप बिश्नोई : स्पीकर सर, मेरी कोई डिमाण्ड नहीं है मेरा तो माननीय मंत्री जी से केवल मात्र एक सुझाव है कि मैं कई बार कालका हल्के में गया हूं कालका हल्के के रायपुर रानी और बरवाला ब्लॉक्स में मक्खियों का बहुत ही ज्यादा प्रकोप है जिससे वहां के लोग ही नहीं लोगों के पालतू पशुओं का जीवन भी दूभर हो गया है। इन इलाकों में पोल्ट्री फार्म्ज की बहुत ज्यादा हैफ-हैजर्ड डिवैल्पमैंट हो गई है। वहां की मक्खियां इतनी ढ़ीठ भी हो गई हैं कि वे पंखा चलाने पर भी नहीं हटती उनको हाथ से हटाना पड़ता है। इस समस्या के कारण इन इलाकों के

[श्री कुलदीप बिश्नोई]

निवासियों का जीवन बहुत ज्यादा मुश्किलों से भर गया है। मक्खियों से ऐसी ही परेशानी नहीं होती बल्कि इनसे बहुत सी बिमारियां भी फैलती है। मेरी आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से प्रार्थना है कि इन इलाकों की मक्खियों की इस समस्या का भी जल्दी से जल्दी कोई न कोई कारगर उपाय किया जाये ताकि वे लोग चैन से और स्वस्थ जीवन जी सकें।

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे लाडवा हल्के में भी बहुत सारी ऐसी पी.एच.सीज़. और सी.एच.सीज़ हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा जर्जर है। एक तो सैंटर ऐसा है वह खुद ही बीमार है। उस सैंटर में जो कोई भी स्टॉफ नर्स आती है वह भी किसी व्यक्ति की बैठक में जाकर मरीज़ों को दवाई देती है। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे प्रत्येक जिले के सी.एम.ओ. से समस्त जिलों के इस प्रकार के सैंटर्ज़ की जांच पड़ताल करवायें और जहां-जहां पर ज़रूरत हो वहां-वहां पर पी.एच.सीज़. और सी.एच.सीज़ की प्रॉपर बिल्डिंग्स का निर्माण करवाया जाये।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : स्पीकर सर, फतेहाबाद में वर्ष 1983 से 50 बैड का सरकारी हॉस्पिटल है। वहां के लोगों की पिछले काफी लम्बे समय से यह डिमाण्ड है कि इस हॉस्पिटल के बैड की संख्या बढ़ाई जाये। इसके लिए उनको पिछले 10 सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। वहां पर हुडा ने सैक्टर 9 में 15 एकड़ ज़मीन हॉस्पिटल के लिए एक्वायर कर दी और जो पुराना हॉस्पिटल है वह भी उसको लेना है लेकिन अभी तक बिल्डिंग के निर्माण की प्रोग्रैस बहुत ज्यादा पुअर है। एक साल से उस बिल्डिंग का नक्शा हैड ऑफिस में आया हुआ है। क्या इसके प्रोग्रैस के बारे में माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे?

श्री तेज़ पाल तंवर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि हमारे तावडू के आस-पास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। हमारे तावडू के सरकारी अस्पताल की इतनी बुरी हालत है कि उसकी बिल्डिंग की तोड़-फोड़ हो चुकी है और डॉक्टर्ज़ खुले में बैठे हैं। मेरी माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारे तावडू के हॉस्पिटल की बिल्डिंग का तुरंत निर्माण करवाया जाये। वहां पर पूरे डॉक्टर भी नहीं हैं। इसलिए मेरी आपसे पुन: प्रार्थना है कि हमारे इस काम को अविलम्ब करवाया जाये। धन्यवाद।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों की भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूँ। स्वास्थ्य संबंधी जो पी.एच.सीज, सी.एच.सीज. और हॉस्पिटल्स की बात आ रही हैं इसके बारे में सरकार संजीदा है। मैंने आदेश जारी कर दिये हैं कि हरियाणा के सभी पी.एच.सीज, सी.एच.सीज., डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब-डिविजनल हॉस्पिटल्स को स्टडी करके उनको अपग्रेड किया जाये। सर, अब हमारी ओ.पी.डी. भी बढ़ रही है। जब से हमारी सरकार आई है और जब से सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा मुझे सौंपा है तब से हमारी ओ.पी.डी. में 13.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। लोगों का रूख सरकारी हॉस्पिटल्स की तरफ बढ़ा है। इसी तरह से हमारे इन्डोर पेशैन्ट की संख्या में भी 15.67 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसका मतलब यह है कि लोगों का रूख सरकारी हॉस्पिटल्स की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। उसको देखते हुये

और पिछले काफी लम्बे समय से हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन न होने की वजह से हमारे पास हॉस्पिटल्स में बैड्स की संख्या बहुत कम है। इस समय हमारे पास 13784 बैड हैं। कई बार तो हमें एक-एक बैड पर दो-दो मरीजों को लिटाना पड़ता है और वह बात समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो जाती है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में एक-एक बैड पर दो-दो मरीजों को लिटा रखा है। सर, 100 बैड का हॉस्पिटल्स है और अगर 200 मरीज आ गये तो एक-एक बैड पर दो-दो मरीज लिटाये जायेंगे। इसमें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 100 मरीजों की कैपेस्टी होते हुये भी हम 200 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति ज्यादा लम्बे समय तक नहीं चल सकती है। इसलिए मैने सभी हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के आदेश पारित किये हैं और 84 हॉस्पिटल्स को मैंने एन.ए.बी.एच. की एक्रिडिशन कराने का आदेश दिया है। सर, हिन्दुस्तान में हरियाणा पहला स्टेट होगा जिसमें इस स्तर पर एन.ए.बी.एच. की एक्रिडिशन करवाई जा रही है। उसके लिए सारे काम पूरे हो चुके हैं और यह सब करके हम सारे का सारा ढांचा बदलना चाहते हैं। हम टूटी हुई बिल्डिग्स को ठीक करना चाहते हैं और एन.ए.बी.एच. एक्रिडिशन यानि कि जो विश्व स्तर के पैमाने यानि कितने डॉक्टर होने चाहिएं, किस साईज की लैबोरेट्री होनी चाहिए, ब्लड बैंक किस साईज का होना चाहिए तथा एक बैड के लिए कितनी जगह होनी चाहिए इत्यादि। हम वे सारी चीजें पूरी करना चाहते हैं और यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और ये सभी बातें हमारे माननीय सदस्यों को पता होनी चाहिएं। सर, गुजरी सरकारें अब वह गुजर गई हैं इसलिए मैं उनको गुजरी सरकारें कहता हूँ जोकि स्वास्थ्य पर केवल 2 प्रतिशत बजट खर्च करती आई हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम हरियाणा प्रदेश का आंकलन करें तो हम नीचे से दूसरे या तीसरे नम्बर पर आते हैं इसलिए हमें अधिक फंड की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री महोदय और यह सदन इस बार स्वास्थ्य विभाग को ज्यादा पैसा देगा ताकि यह सब काम पूरे हो सकें और इसके अलावा भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने योजना बनाई हैं वे पूरी हो जायें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार तो स्वास्थ्य विभाग का बजट कम किया गया था।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कम नहीं किया गया था लेकिन पिछली बार स्वास्थ्य विभाग का बजट केवल 3-4 पैसे ज्यादा दिया गया था। सर, इसके अलावा भी हमें इसके लिए चाहे वर्ल्ड बैंक से, चाहे केन्द्र से चाहे कहीं से भी धन की व्यवस्था करके दी जाए। मैं नहीं चाहता कि आने वाली पीढ़ियां इन्हीं टूटे-फूटे अस्पतालों में ईलाज करवाने के लिए मजबूर हों। मैं इन सारे अस्पतालों को सुधारना चाहता हूं। हमने सरकार में आने के बाद अस्पतालों में बहुत सुधार किये हैं। हमने हर जिले में एम.आर.आई. मशीन लगाने का काम शुरू कर दिया है। हम 8 जिलों में एम.आर.आई. मशीनें लगा चुके हैं। इसके साथ-साथ हरियाणा के हर जिले में डायलिसिज के इलाज के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसका काम आरम्भ हो गया है। इसके साथ ही हम 4 जिलों में पाईलेट प्रोजैक्ट कैथ लैब लगाने जा रहे हैं। सर, हम हरियाणा के अस्पतालों का पूरा नक्शा बदलने जा रहे हैं। मैं मैम्बरों की बात से बिल्कुल सहमत हूं जो इन्होंने अलग-अलग अस्पतालों की बात कही है वह हमने नोट भी कर ली हैं उनके ऊपर हम प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देंगे और WHO के जो पैमाने हैं, जो गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया के पैमाने हैं उसके मुताबिक ही हमने काम किया है। आज की तारीख में हमारे पास 2630 सब सैंटर हैं, 485 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[श्री अनिल विज]

हैं, 119 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और 58 अस्पताल हैं। हम इनको भी दुरूस्त करना चाहते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि नये अस्पताल खोलने की बजाए पहले हम इन पुराने अस्पतालों को तो ठीक कर लें और उसमें सबसे बड़ी अड़चन जो हमारे सामने आ रही है वह है डॉक्टरों की उपलब्धता और आने वाले दिनों में मुझे मालूम है कि जो सप्लीमैंट्रीज आएंगे उनमें डॉक्टरों की बात आएगी। हमें जितने डॉक्टर चाहिए उतनी उपलब्धता हमें नहीं हो पा रही है क्योंकि डॉक्टर पैदा नहीं हो रहे हैं। WHO की गाईड लाईन के मुताबिक 1000 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर होना चाहिए लेकिन हिन्दुस्तान में 1800 की पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर है तो मैं मानता हूं कि डॉक्टरों की कमी है। उसके लिए भी हमने सोचा है। उसके लिए हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना शुरू की है। आज हमारे पास आठ जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं जो 4 जिलों में सरकारी और 4 जिलों में प्राईवेट मेडिकल कॉलेज हैं। भिवानी और पंचकूला में जो 300 बैड के जिला अस्पताल हैं उनको अपग्रेड करने का काम हमारा पूरी तरह से चल रहा है वह हम अपग्रेड करेंगे। आठ मेडिकल कॉलेज पहले थे और दो भिवानी और पंचकूला में हो गये तो टोटल दस मेडिकल कॉलेज हो गये। जीन्द में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके लिए 20 एकड़ जमीन को आईडैंटिफाई कर लिया गया है उस पर भी हमारा काम जारी है। बाकी भी और संस्थाओं को जिसमें से एक शाहबाद में पिछले 15 सालों से एक मेडिकल कॉलेज अधूरा पड़ा था जो एस.जी.पी.सी. बना रही थी, पिछली सरकार ने राजनैतिक कारणों से उसमें रूकावट पैदा की हुई थी। उनकी 100-200 करोड़ रूपये की इन्वेस्टमैंट उस मेडिकल कॉलेज पर हो चुकी थी लेकिन वह किसी के काम नहीं आ रहा था। सर, इसके लिए मैं खुद अमृतसर गया वहां मैंने एस.जी.पी.सी. के प्रधान के साथ बात करके उनसे कहा कि इसकी जो अड़चने हैं हम उनको दूर करेंगे। उसको हमने पिछले सप्ताह एल.ए. जारी कर दिया है और इसी हफ्ते के अन्दर-अन्दर हम सी.एल.यू. भी जारी कर देंगे वह कॉलेज भी बनकर तैयार हो जाएगा। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि जो मैंने नहीं बोला उसको आप लिख कर दे देना It is open to all 24 by 7 सर, डेरा सच्चा सौदा में भी एक मेडिकल अस्पताल बना हुआ है। जब मुझे पता लगा तो मैंने वहां भी जाकर कहा कि आप इस अस्पताल का अपग्रेडेशन करें इसको मेडिकल कॉलेज बनाएं तो उन्होंने भी वहां मेडिकल कॉलेज बनाने के दस्तावेज हमारे डिपार्टमैंट में भेज दिये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें ज्यादा डॉक्टर चाहिए तो उसके लिए ज्यादा मेडिकल कॉलेज होने चाहिएं और उसके लिए हमने ज्यादा मेडिकल कॉलेज सब्मिट किये है। इसके बावजूद भी कुछ कॉलेजिज बनाने के लिए ऑफर्स आई हैं। रादर जो त्रेह्न मैडिसिटी है उन्होंने भी कहा है कि वह भी एक कॉलेज बनाना चाहते हैं। सर, अगर ज्यादा कॉलेज बनेंगे तो ज्यादा डॉक्टर होंगे और डॉक्टरों को जो इन्सैंटिव मिलते हैं अगर उनकी बात की जाए तो आज डाक्टर्ज को प्राईवेट अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों के मुकाबले बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। यहीं कारण है कि डाक्टर्ज सरकारी अस्पतालों को छोड़कर प्राईवेट अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं। इस दिशा में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। यहीं कारण है कि मैंने प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते किस-किस प्रदेश में डॉक्टर्ज को क्या-क्या वेतन व अन्य सुविधायें दी जा रही है, इन सबकी जानकारी प्राप्त करने के आदेश दिये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जो भी कमियां हमें मिलेगी हम उनको दूर करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो सरकारी डॉक्टर्ज के वेतन व अन्य दूसरी सुविधाओं को

बढ़ाने से हम गुरेज नहीं करेंगे। वास्तव में अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार का एक ही मकसद है कि affordable medical care to all.

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात जानना चाहूँगा कि आपकी सरकार मेडिकल कॉलेज बनाने की तो इच्छुक है और आपकी सरकार ने पहले दिन ही यह बात कही भी थी कि हरियाणा प्रदेश के सभी 21 जिलों में मेडिकल कॉलेजिज बनाना उनका मकसद है। यह बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा करके हरियाणा प्रदेश को एक ऐसी अच्छी सुविधा प्रदान करेंगे जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत भी है। इसके साथ ही साथ आपकी सरकार द्वारा यह चिंता भी जाहिर की गई थी कि डाक्टर्ज की पढ़ाई के लिए बहुत कम लोग ही इच्छुक होते हैं। इसका सीधा-सा कारण यह है कि यदि कोई बच्चा किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाता है तो उसके लिए उसे एक करोड़ रूपया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए खर्च करना पड़ता है। यही नहीं मेडिकल कॉलेजिज की फीस भी इतनी ज्यादा है कि उसे आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप प्राईवेट लोगों को ज्यादा मेडिकल कालेजिज बनाने की इजाजत दोगे तो मानकर चलो कि केवल वे बच्चे उन प्राईवट कॉलेजिज में पढ़ सकेंगे जिनके पास पैसा होगा। इस तरह से जो बच्चे डाक्टर बनने के इच्छुक होंगे उनके सामने फिर किसी न किसी तरह से रूकावटें आकर खड़ी हो जायेंगी। अत: मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा प्राईवेट मेडिकल कॉलेजिज बनाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाये जायें। इन सरकारी मेडिकल कॉलेजिज में तमाम तरह की सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाए। आपकी सरकार द्वारा बार-बार इस बात पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि प्राईवेट अस्पतालों में डाक्टर्ज को ज्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं और सरकारी डॉक्टर्ज को तनख्वाह कम मिलती है जिसकी वजह से सरकारी डाक्टर्ज सरकारी नौकरी छोड़कर प्राईवेट अस्पतालों की ओर रूख कर लेते हैं। इस पलायन को रोकने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि सरकारी डाक्टर्ज को बेहतर इंसैंटिव्ज दिये जायें ताकि इन इंसेंटिव्ज का लाभ उठाते हुए यह डॉक्टर्ज हरियाणा प्रदेश में रह रहे लोगों की उचित सेवा कर सकें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बहुत जायज चिंता व्यक्त की है लेकिन इकोनोमिक्स का सिद्धांत है Demand and Supply. अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है then rates go high. अध्यक्ष महोदय, यदि ज्यादा मेडिकल कॉलेजिज खोल दिये जाते हैं तो गुणवत्ता में कमी आ जायेगी और यह बात भी नहीं है कि हमारी सरकार केवल प्राईवेट अस्पतालों को ही इंटेंसिव दे रही हो। हमारी सरकार पंचकुला में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई) भिवानी में भी हम सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। जीन्द में भी हमारी सरकार, सरकारी मैडीकल कॉलेज खोलने जा रही है। मैं इस संबंध में केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी.नढ्ढा जी से मिला भी था और मैंने उनसे यह कहा था कि जैसे ही हमारे यह तीन मेडिकल कॉलेज का प्रोसैस इनिशियेट हो जाये तो आप हरियाणा प्रदेश को प्रत्येक साल दो-दो मेडिकल कॉलेज जरूर दे दिया करें। हमारी सरकार इस दिशा में बहुत अग्रसर है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजिज भी खुलें लेकिन यदि प्राईवेट सैक्टर्ज के भी अच्छे कॉलेजिज आते हैं और अगर उन प्राईवेट मेडिकल कॉलेजिज का सरकारी मेडिकल कॉलेजिज के साथ कम्पटीशन होता है then it will be a healthy competition और इस प्रकार से जो माननीय सदस्य ने अभी चिन्ता जाहिर की थी कि प्राईवेट मेडिकल कॉलेजिज में एडमिशन पर करोड़ों

[श्री अनिल विज]

करोड़ रूपये खर्च हो जाते हैं, उस पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। अभी हाल ही में all Health Ministers of India की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था और मैने उनसे हिन्दुस्तान के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अपील की थी ताकि हिन्दुस्तान के गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी डॉक्टरी कर सके। (इस समय मेजें थपथपाई गईं) यह एडमिशन के पैसे इसलिए इतने ज्यादा दिये जा रहे हैं क्योंकि जिस अनुपात में डाक्टर्ज तैयार किये जाने चाहिए थे उस अनुपात में मेडिकल कॉलेजिज नहीं बनाये जा सके। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय,. . . (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, यह प्रश्न काल का समय है। यदि प्रश्न काल में इस प्रकार की चर्चा होगी तो फिर आप ही बतायें कि किस प्रकार से एक निश्चित समय में सभी प्रश्नों को टेकअप किया जा सकेगा। इस प्रकार की चर्चा में प्रश्न काल का महत्वपूर्ण समय निकल जायेगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मसला है और मैं केवल इसी गम्भीर विषय पर अपनी बात रखकर बैठ जाऊंगा। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से यह बात कही कि सरकार हरियाणा प्रदेश में तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेजिज बनाने जा रही है। आप प्रदेश में स्वास्थ्य के मसले पर कानून बना सकते हो परन्तु प्राईवेट मेडिकल कॉलेजिज में जो एडमिशन के नाम पर, एन.आर.आई. के एडमिशन के नाम पर तथा अन्य दूसरी चीजों के नाम पर अंधाधुंध 50-50 लाख रूपये लिये जाते हैं, उन प्राईवेट मेडिकल कॉलेजिज पर भी अंकुश लगाने के लिए सरकार के द्वारा कोई न कोई कानून जरूर बनाया जाना चाहिए ताकि लोगों की जेब ना काटी जा सके। मैरिट के आधार पर बच्चों का एडमिशन हो सके। आप अपने प्रदेश में कानून बना सकते हैं, वही कानून देखकर बाकी राज्यों की सरकारें भी कानून बनायेंगी जिससे आम गरीब आदमी को लाभ मिल सकेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, प्राईवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में वैसे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन्ज़ दी हुई हैं लेकिन फिर भी जैसे नेता प्रतिपक्ष ने कहा मैं इसको एग्जामिन कराऊंगा। जो लुट मचती है, अगर हम उसको रोक सकते हैं तो we will definitely do it.

डॉ0 अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कई जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। नारनौल का उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, नारनौल सबसे ज्यादा गरीब इलाका है जहां पर कोई भी सुविधा नहीं है। इस हल्के के सारे के सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए जयपुर जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसके बारे में कोई स्पेसिफिक बात है तो ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस माननीय मंत्री जी जरूर कहें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार अपने फंड से प्रदेश के सारे जिलों में एक साथ मेडिकल कॉलेज बना दें। एक-एक मेडिकल कॉलेज को बनाने की एवरेज लगभग 400-500 करोड़ रूपये की आती है। अध्यक्ष महोदय, किसी

काम की कहीं से तो शुरूआत होती है। उसी दिशा में हम शुरू कर रहे हैं। मनेठी में भी हमने मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए कहा हुआ है। मनेठी में एम्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी एम्स का एक्सटैंशन काउंटर हम बाढसा में ले करके आए हैं। हम सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाना चाहते हैं। किसी जिले में पहले किसी जिले में बाद में, हम कोशिश जरूर करेंगे कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने।

Ditch Drain Project

***1218. Shri Ranbir Gangwa :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :-

(a) the present status of Ditch Drain Project adjacent to Yamuna river together with the total amout incurred on the said project; and

(b) whether the above said project has been completed; if so, the full details thereof?

कृषि मंत्री (ओमप्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

यमुना नदी के साथ कोई भी डिच ड्रेन नहीं है। पश्चिमी यमुना नहर (डब्लयू. जे. सी.) के साथ-साथ यमुनानगर शहर से धनोरा तक 69670 फुट लम्बाई की डिच ड्रेन बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा रु० 13.71 करोड़ की प्रकाशकीय स्वीकृति प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जन स्वास्थ्य विभाग के डिपाजिट कार्य के रूप में दी गई थी। इस कार्य के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जन स्वास्थ्य विभाग ने रु० 11.25 करोड़ जमा करवाए थे और यह कार्य जिला यमुना नगर की औद्योगिक इकाइयों तथा घरों से उत्पन्न मल निकालने के लिए वर्ष 2009 में रु० 1125 लाख की राशि से सम्पन्न हुआ था। यह डिच ड्रेन धनोरा एस्केप में गिरती है और धनोरा एस्केप यमुना नदी में करनाल जिले में गिरती है। इस की निष्कासन क्षमता 60 क्यूसिक है तथा डिच ड्रेन बनाने के लिए 79.72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। आगे इस जमीन की कीमत न्यायालय द्वारा बढ़ाई गयी और इसके लिए रु० 1.79 करोड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जन स्वास्थ्य विभाग से लेकर जमीन मालिकों को वर्ष 2015-16 में दे दिए गए। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि यह यमुनानगर के इण्डस्ट्रीज के खराब पानी को लेकर जाती है।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न से संबंधित बात मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पहले हिसार में बी.एम.सी. के नाम से नहर थी, अब उसका नाम बदलकर सिवानी फीडर कर दिया गया है, जिसमें यमुना नदी का पानी आता था। पिछली सरकार के समय हिसार में उसमें केवल भाखड़ा नहर का पानी रह गया था। इस समस्या को देखते हुए हिसार के बुढ़ा, बासड़ा आदि गांवों के लोग पानी के लिए धरने पर बैठे। धरने को समाप्त करने के लिए माननीय मंत्री जी ने वहां के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके पानी का सप्ताह 12 दिन का कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, पानी का सप्ताह 12 दिन का कर दिया गया, लेकिन वह देवसर फीडर से काट कर किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमने पानी का सप्ताह 8 दिन और 16 दिन का तो देखा था लेकिन पानी का सप्ताह 12 दिन का कभी भी नहीं देखा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिवानी फीडर में दोबारा यमुना का पानी देंगे जिससे

[श्री रणबीर गंगवा]

हिसारवासियों को राहत मिल सके। भाखड़ा का पानी सिवानी फीडर और बालसमंद डिस्ट्रिब्यूट्री के द्वारा हिसार में जा रहा है। हिसार में पानी की आज बड़ी भारी समस्या बनी हुई है क्योंकि वहां पर पानी सिर्फ एक सप्ताह चलता है रिमॉडलिंग के नाम पर नहरें छोटी कर दी गई हैं। नहर की मोरियों से पीने का पानी ही मुश्किल से पहुंचता है। मैंने पहले भी कहा था कि नये सिरसाना माइनर पर डी.सी. ने फोर्स लगाकर पीने का पानी पहुंचाया था। नहर का पानी खेतों में तो पहुंचा ही नहीं है। अगर किसान वहां के एक्स.ई.एन. से इस बारे में कहते हैं तो वे बताते हैं कि हमने मोरी का माप ले लिया है और आपकी मोरी बिल्कुल सही है। मोरी कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिससे खेत में पानी पहुंच सके। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आप हिसार के किसानों को यमुना का पानी देकर उनकी सहायता करेंगे और उनका हक देंगे। दूसरी बात जो मोरियों को छोटी कर दिया गया है जिससे पर्याप्त पानी नहीं निकल रहा है। क्या आप किसी भी अधिकारी की जिम्मेवारी लगाकर पानी को चैक करवाएंगे कि ये जो न्यू सिरसाना माइनर, सिरसाना माइनर, बेहरिया माइनर और बालसमंद डिस्ट्रीब्यूट्री हैं इनसे किसानों को कितना पानी मिल रहा है। इसके साथ ही मेरा एक और क्वैश्चन है कि जो ओ.पी. जिन्दल नहर डेढ़ वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए थी उसमें आज तक पानी की लिफ्टिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ है। महीने में एक सप्ताह तो नहर में पानी आता है तथा उसमें भी अगर 1-2 घंटे लाइट चली जाए तो गरीब किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता है। क्या मंत्री जी इसके स्थाई समाधान के लिए सही कनैक्शन दिलवाएंगे और क्या किसी अधिकारी की ड्यूटी लगाकर मोरियों को ठीक करने का काम करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह मूल प्रश्न से संबंधित प्रश्न नहीं है। यह विभाग से रिलेटिड है लेकिन मूल प्रश्न से रिलेटिड नहीं है। (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, यह पानी यमुना नदी का था। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, जब हमने एस.वाई.एल. नहर पर चर्चा की थी तो हमने बताया था कि हम बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। माननीय सदस्य को जानकारी है कि यमुना एक बरसाती नदी है। माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ने भी बताया था कि यमुना के पानी में पहले हमारा 2/3 हिस्सा था जो एक मुख्यमंत्री के शासनकाल में घट गया था। इस बार मानसून सारे देश में कम हुआ है। हमारे प्रदेश में भी 50 प्रतिशत कम मानसून हुआ है। इस वर्ष साईक्लोन और बर्फबारी भी मार्च महीने में हुई है। नववर्ष के आगमन पर जरा-सी भी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई। इस बार हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी बारिश कम हुई है जिसकी वजह से यमुना का पानी पिछले वर्ष की तुलना में 2 हजार क्यूसिक कम आया है। इस वर्ष यमुना में एक हजार क्यूसिक के आसपास पानी चल रहा है। इस साल यमुना के माध्यम से कुल मिला कर 50 प्रतिशत पानी आया है। ईश्वर की कृपा से हमारे भाखड़ा डैम, पौंग डैम और एस.वाई.एल. नहर का जो सिस्टम था उसमें पानी का स्तर अच्छा रहा जिससे हम खरीफ और रबी की फसल को बहुत बड़ी मात्रा में बचा पाए। एक जमाने में यमुना का पानी हिसार तक जाता था और बहुत पुराने जमाने में फिरोजशाह गुजरी महल के लिए लेकर गये थे। उस जमाने में

राजा अपनी रानियों के प्रेम में उनके लिए इतनी दूर से नहर बनाकर पानी लेकर गए थे। अब हमारे पास ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब हमें पानी भाखड़ा-नंगल डैम के माध्यम से प्राप्त होता है। इसी को लिंक करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमें पूरे प्रदेश में एक-साथ पानी चलाने के लिए कम से कम 6 हजार क्यूसिक पानी की आवश्यकता है। हरियाणा प्रदेश को कुल चार चैनल सिस्टम में बांटा गया है। हम प्रदेश में समान मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए एक बार पहले चैनल में पानी को चलाते हैं फिर दूसरे चैनल में पानी को चलाते हैं। इस प्रकार से रोटेशन करके इन चारों चैनलों में पानी पहुंचाया जाता है लेकिन इस बार यमुना में पानी की उपलब्धता इतनी कम रही है कि हमने हरियाणा को 4 हिस्सों की बजाय 5 हिस्सों में बांटना पड़ा। जहां पानी पहले एक महीने से कम समय में दे पाते थे वहां पानी अब एक महीने से भी ज्यादा समय के बाद दे पाए हैं। हमारे बहुत से इलाको के पीने के पानी के टैंक की क्षमता इतनी नहीं थी कि वे एक महीने तक का पानी रिजर्व कर सकें और एक महीने तक शहर को पानी दिया जा सके। इस सीजन में हमें दिक्कत आई कि कैसे हम पशुओं को और मनुष्यों को पीने का पानी देने के इंतजाम कर सके। अध्यक्ष महोदय, आप सबको पता है कि धरने पर बैठे किसानों को खुश करके उठाने के लिए पानी को डायवर्ट करना पड़ता है। इसके लिए जो नहर आठ दिन बाद छोड़ी जाती थी उसको 12 दिन बाद भी छोड़ना पड़ता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, क्या करें हमें पानी इधर से उधर करना पड़ता है क्योंकि हम पानी की एक बूंद भी नहीं बढ़ा सकते। सदन दो दिन से पानी की लड़ाई लड़ रहा है। पानी की एक बूंद भी बढ़ाने का सामर्थ्य हममें नहीं है लेकिन उसकी मितव्ययिता के लिए प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। पानी की मितव्ययिता के लिए नई नई टैक्नोलोजी ला सकते हैं। रिसाइकिलिंग, पुनर्भरण या रिचार्जिंग से पानी को बचाया जा सकता है। शहरों में पानी की खपत कम हो इसके लिए टैक्नोलोजी बढ़ाई जा सकती है। शहरों में लोग एक बार बाथरूम जाते हैं तो 7-8 लीटर पानी बहा देते हैं इसलिए इस बर्बाद होने वाले पानी को भी कोई नई टैक्नोलोजी लाकर बचाया जा सकता है। आने वाले समय में हमें 3 करोड़ एकड़ फीट पानी चाहिए। अभी हम दो करोड़ एकड़ फीट पानी अवेलेबल कर पा रहे हैं। एस.वाई.एल. नहर के पानी, रावी- ब्यास के थोड़े हिस्से का पानी और यमुना नदी के पानी को मिलाकर हमें एक करोड़ एकड़ फीट पानी मिलता है। एक करोड़ एकड़ फीट पानी हम जमीन से निकालते हैं यानि कुल मिलाकर हम दो करोड़ एकड़ फीट पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमको कम से कम 3 करोड़ एकड़ फीट पानी चाहिए। जब बारिश पूरी होती है तब एक करोड़ 20 लाख एकड़ फीट होती है जिसमें से 60 लाख एकड़ फीट पानी रिचार्ज होता है तथा बाकी पानी बह जाता है। इस प्रकार जो 40 लाख एकड़ फीट पानी का गैप है इसके कारण हरियाणा डार्क जोन में बदलता जा रहा है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने पम्प हाउसिज हैं उनको 24 घंटे के लिए डायरैक्ट कनैक्शंज दिए जाएं ताकि बिजली जाने से नहरों का संचालन बन्द न हो, इस विषय पर डिपार्टमैंट काम कर रहा है।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : अध्यक्ष महोदय, हमारी मांग बहुत पुरानी है। यह ड्रेन पहले ही बन जानी चाहिए थी लेकिन अब तक नहीं बनी है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। इसके कारण नलवा तक पीने का पानी नहीं पहुंच पाता। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी मांग बहुत पुरानी है लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूं। पहले बी.एन.सी. थी अब सिवानी फीडर है उसका पानी

[श्री रणबीर सिंह गंगवा]

यमुना से काट दिया गया है। मैं कहना चाहूंगा कि सिवानी फीडर के साथ लगते 7 जिलों में जितना पानी आता है उतना ही पानी हमें मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि बी.एम.सी. में पहले वाला यमुना का पानी आ जाता है तो हमारे यहां के किसानों को थोड़ी राहत मिल पाएगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक मिसाल दे रहा था कि लोग यमुना का पानी कहां तक ले गए थे। इस बार तो यमुना में पानी है ही नहीं। हरियाणा एक अच्छा राज्य है और मैं इसकी प्रशंसा करना चाहता हूं। इंटरलिंकिंग की बात देश में चल रही है। हरियाणा पूरी तरह से इंटरलिंकड है और हम सब तरफ का पानी यहां से वहां ले जाने में सक्षम हैं। हरियाणा में इस बार 4 की बजाय 5 बार पानी देने का संकट आया है। यदि यमुना का पानी बढ़ जाता है तो हम फिर से उसको 4 बार कर देंगे और सब जगह पानी दे दिया जाएगा।

Heavy Driving Licenses

***1224. Shri Zakir Hussain**
Shri Naseem Ahmed **:** Will the Transport Minister be pleased to State :-

(a) The number of heavy driving licenses issued in District Mewat; and

(b) whether it is a fact that the heavy driving licenses are not being renewed for the last 4-5 years in Mewat; if so, the reasons thereof?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) :

(क) श्रीमान, जिला मेवात में दिनांक 29.02.2016 तक 142 भारी वाहन ड्राईविंग लाईसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) नहीं श्रीमान, प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि 142 हैवी लाईसैंस ईशू हुए हैं। सभी जानते हैं कि मेवात जिले और मेवात क्षेत्र में लोगों के पास ड्राईवरी सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है और लोग ज्यादातर ट्रक चलाते हैं। मंत्री जी के जवाब से ही प्रश्न खड़ा होता है कि वहां पर हैवी लाईसैंस बहुत कम बनाये जा रहे हैं। वहां पर हैवी लाईसैंस बनाने की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंज पैंडिंग हैं। इसी के साथ-साथ जो लाईसैंस रिन्यू होने हैं वे भी करीबन 30 हजार पैंडिंग हैं जो बाहर से बने हुए हैं, जो 2-2 या 3-3 बार एन.ओ.सी. आने के बाद नूंह आर.टी.ओ. आफिस से रिन्यू हुए हैं लेकिन आज उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा। वे लोग वहां पर पिछले 7-8 साल से धक्के खा रहे हैं उनके लाईसैंस रिन्यू न होने के कारण वे बेरोजगार बैठे हैं। कांग्रेस राज में उनके साथ अन्याय हुआ है। मेरे से पहले श्री आफताब अहमद जी वहां से विधायक थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। उस समय दो नम्बर की कमाई के लिए पैसे लेकर लाईसैंस रिन्यू किए जाते थे। अब खुशकिस्मती से उनकी सरकार चली गई। मेवात में लोग लाईसैंस रिन्यूवल को लेकर बहुत परेशान हैं। कुछ दिन पहले फलाईंग स्कवैड ने चैकिंग की थी जिसमें सामने आया कि वहां पर दलालों ने कुछ गलत लाईसैंस

बनवाये थे उसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। आधे से ज्यादा लाईसैंस ठीक पाये गये थे। इसमें मेरी मंत्री जी से यही अर्ज है कि यदि कोई कसूरवार है तो दलाल हैं इसलिए वहां पर जो 30 हजार लाईसैंस रिन्यू होने हैं उनको तुरंत रिन्यू किया जाये क्योंकि लोग बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं तथा जो नये लाईसैंस की एप्लीकेशंज आई हुई हैं उन्हें भी तुरंत बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेवात के लोगों को हैवी लाईसैंस बनवाने के लिए टैस्ट देने बहादुरगढ़ जाना पड़ता है इसलिए मोटर ड्राईविंग सैंटर नूंह में खोला जाये। इस बारे में कई सालों से प्रोपोजल भी चल रहा है। मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यह प्रोपोजल प्रोग्रैस पर है। लेकिन जब तक ड्राईविंग सैंटर नहीं बनता तब तक नूंह में ही ड्राईविंग टैस्ट लेने की कोई टैंपरेरी व्यवस्था की जाए।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, हम हर महीने नूंह में हैवी लाईसैंस बनाने के लिए एप्लीकेशन इनवाईट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी ने पूछा है 30 हजार के करीब लाईसैंस रिन्यू नहीं किए गए। इसकी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि वर्ष 2011 में 2978 लाईसैंस रिन्यूवल के लिए आये और 2950 रिन्यू किए गए तथा 28 लाईसैंस फर्जी पाये गये। इसी तरह वर्ष 2012 में 30 हैवी लाईसैंस न्यू जारी किए गए, 6740 लाईसैंस रिन्यूवल के लिए आये और 6729 लाईसैंस रिन्यू किए गए तथा 11 लाईसैंस फर्जी पाये गये। इसी तरह वर्ष 2013 में 18 हैवी लाईसैंस न्यू जारी किए गए, 328 लाईसैंस रिन्यूवल के लिए आये और 310 लाईसैंस रिन्यू किए गए तथा 18 लाईसैंस फर्जी पाये गये। इसी तरह वर्ष 2014 में 50 हैवी लाईसैंस न्यू जारी किए गए, 4953 लाईसैंस रिन्यूवल के लिए आये और 4953 लाईसैंस रिन्यू किए गए। इसी तरह वर्ष 2015 में 26 हैवी लाईसैंस न्यू जारी किए गए, 4466 लाईसैंस रिन्यूवल के लिए आये और 4466 लाईसैंस रिन्यू किए गए। इस तरह से टोटल 20170 लाईसैंस रिन्यू किए गए हैं और 625 लाईसैंस फर्जी पाये गये हैं। इसके लिए हमने नोटिस जारी कर दिए हैं ये लाईसैंस आगरा और मथुरा के बने हुए हैं। जहां तक माननीय साथी ने ड्राईविंग ट्रेनिंग सैंटर खोलने की बात की है इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि हमने मेवात के छपेड़ा में बहुत बड़ा ड्राईविंग सैंटर खोलने के लिए भारत सरकार के पास प्रोपोजल एप्रूवल के लिए भेजी है बहुत जल्द वहां पर यह सैंटर खोला जायेगा।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, मेरा निवेदन यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि 20 से 25 हज़ार ड्राईविंग लाईसैंस अभी भी ऐसे हैं जो उस मामले में उलझे हुए हैं। जिनकी सी.एम. फ्लाईंग स्कवॉयड से इंक्वायरी हुई थी। उसके बाद वर्ष 2014-15 में यह बात उलझी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जो कि हमारे जिले की ग्रिवैंसिज कमेटी के इंचार्ज़ हैं इस सम्बंध में न्यूज पेपर में एक एडवटाईज़मैंट देकर इस समस्या का समाधान करें। इस मामले में दूसरी बात मैं यही कहना चाहता हूं कि बहादुरगढ़ में ड्राईविंग कॉलेज बनने में अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा क्योंकि वह बहुत बड़ा ड्राईविंग कॉलेज है। मैं यह चाहता हूं कि जब तक बहादुरगढ़ में डाईविंग कॉलेज नहीं बन जाता तब तक मेवात में किसी भी सरकारी बिल्डिंग में इसका एक सब-सैंटर खोल दिया जाये और वहां पर नौजवानों को ड्राईविंग का प्रशिक्षण दिया जाये। अगर किसी सरकारी बिल्डिंग की उपलब्धता न हो तो मेरे मरहूम दादा जी के नाम से मेवात में एक कालेज है उसमें इस कार्य के लिए जितने कमरों की माननीय मंत्री जी डिमाण्ड करेंगे वह मैं आज ही देने के लिए तैयार हूं। ये चाहे 10 कमरें मांगे या फिर 15 कमरे मैं इनको उतने ही कमरे दे दूंगा। चाहे ये कल से ही वहां पर ऑफिस बनवा दें

[श्री जाकिर हुसैन]

और काम शुरू करवा दें। यह कॉलेज 36 एकड़ में है जहां पर ड्राईविंग का टैस्ट भी लिया जा सकता है। यह मैं माननीय मंत्री जी को ऑफर देता हूं और जब बहादुरगढ़ में ड्राईविंग कॉलेज बन जाये उस समय ये अपने उस सब-सैंटर को शिफ्ट कर लें। एक और बात मैं इस सम्बंध में यह बताना चाहता हूं कि जिन बेचारों के फर्जी ड्राईविंग लाईसैंस बने इसमें दलालों का कसूर था लेकिन दलालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित लोगों ने दलालों को पैसे भी दिए। मैं यह चाहता हूं कि दलालों के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने उनसे ड्राईविंग लाईसैंस बनवाये उनके दोबारा से टैस्ट लेकर उनके ड्राईविंग लाईसैंस बनाये जायें। स्पीकर सर, यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, दिनांक 06.09.2013 को तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लाईंग स्कवॉयड ने यह रेड की थी जिस समय ये फर्जी लाईसैंस पाये गये थे। मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार-विमर्श करके पूरे हरियाणा प्रदेश के 21 के 21 जिलों में ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इस समय हमारे बसों के लिए 18 ड्राईविंग ट्रैनिंग स्कूल फंक्शनल हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे हरियाणा प्रदेश के 21 के 21 जिलों में ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की हमारी योजना है। मैंने इन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल्ज़ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अन्य प्रस्ताव पर भी सहमति ले ली है जिसके तहत हम इन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल्ज़ में ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवायेंगे ताकि हमारे इन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल्ज़ से निकलने वाले विद्यार्थी प्रदेश और देश में स्थित बड़ी-बड़ी कम्पनियों में अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। इतना ही नहीं हम तो यह चाहते हैं कि हमारे इन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल्ज़ से निकलने वाले विद्यार्थी विदेश में जाकर भी बड़ी-बड़ी कम्पनियों में जॉब प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया है और इसकी सराहना भी की है। इससे हमारे प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त जो माननीय साथी श्री जाकिर हुसैन जी ने सुझाव दिया है जैसा कि इन्होंने भी बताया है मैं मेवात जिला की ग्रिवैंसिज कमेटी का चेयरपर्सन हूं इसलिए मैं वहां पर पर्सनली तौर पर जाकर इस सारे मामले को चैक करूंगा और माननीय साथी के सुझाव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, मैंने जो निवेदन किया है वह बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों के लिए यह बहुत ही मुश्किल है कि इतनी दूर बहादुरगढ़ जाकर वे कहां ठहरेंगे और क्या करेंगे ? इसलिए ये कृपा करके एक टैम्पोरेरी सैंटर वहां पर खोल दें ताकि वहां के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने इनको आपके माध्यम से अभी बताया कि यह इनको भी विदित है कि मैं मेवात जिला की ग्रिवैंसिज कमेटी का चेयरपर्सन हूं इसलिए मैं वहां पर पर्सनली तौर पर जाकर इस सारे मामले को चैक करूंगा और माननीय साथी के सुझाव पर हर हालत में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। इस बात का मैं इनको पुन: आश्वासन देता हूं।

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि वे छपेड़ा गांव में ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि इस

स्कूल के निर्माण की कार्रवाई तो अभी-अभी कागजों में चली है। पिछले लगभग डेढ़ साल से सरकार ने इसके निर्माण की घोषणा भी की हुई है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक तो इस ड्राईविंग ट्रैनिंग स्कूल के लिए जितनी ज़मीन एक्वायर की जानी थी वह भी अभी तक पूरी की पूरी एक्वायर नहीं हो पाई है। इसलिए इस ड्राईविंग स्कूल की स्थापना में बहुत समय लगने वाला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इस ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल को जल्द से जल्द बनवाने का कष्ट करें ताकि हमारे मेवात के जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं और जो ड्राईविंग का काम करते हैं चाहे कोई ट्रक चलाता है, चाहे कोई बस चलाता है या फिर चाहे कोई डम्पर चलाता है उनको रोजगार मिल सके। इसके लिए जैसा कि हमारे विधायक श्री जाकिर हुसैन जी ने कहा मैं भी उनके साथ अपनी बात को जोड़ते हुए कहता हूं कि सरकार द्वारा वहां पर एक सब-सैंटर खोल लिया जाये ताकि जो नौजवान बेराजगार बैठे हैं उनको जल्दी से जल्दी सही रोजगार मुहैया हो सके। जो छपेड़ा में स्कूल बनाने जा रहे हैं उसके बारे में भी एक निश्चित समय सीमा बतायें कि वह कब तक तैयार हो जायेगा।

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है मैं पुन : उस बात को दोहरा देता हूं कि हमने छपेड़ा में ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण के लिए भारत सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। हम इसकी जल्दी से जल्दी पैरवी करके बहुत जल्दी ही छपेड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने श्री जाकिर हुसैन जी को बताया मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं कि मैं पर्सनली तौर पर वहां पर जाकर पूरे मामले को देखूंगा और आप दोनों विधायक साथियों की इस डिमाण्ड पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जल्दी से जल्दी इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य किया जायेगा।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि नॉर्म्स के हिसाब से उस सैन्टर के लिए 11 एकड़ जमीन एक्वायर की जानी थी तथा विभाग ने केवल 8 एकड़ जमीन एक्वायर की है तथा यह कार्रवाई भी पिछले 15 दिन में पूरी हुई है। अगर इसी गति से यह कार्य चलता रहा तो आपकी सरकार के 5 साल निकल जायेंगे लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह कार्य कितने समय में पूरा हो जायेगा?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से ही जमीन एक्वायर की जायेगी और नॉर्म्स के हिसाब से ही सभी कार्य किये जायेंगे। जल्दी ही हम भारत सरकार से अनुरोध करके वहाँ पर सैन्टर बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं इस मामले में व्यक्तिगत रूचि लेकर सारे कार्य को चैक करूँगा और इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जायेगा।

To increase the Yields of Pulses

***1230 S. Jaswinder Singh Sandhu :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether any scheme has been formulated by the Government to increase the yields of pulses togetherwith the incentives being provided to the farmers to increase the yields of pulses alongwith being provided by the Government in regards to marketing thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी हां, श्रीमान जी, दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय खादय् सुरक्षा मिशन-दलहन तथा दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये अतिरिक्त क्षेत्र कवरेज नामक दो योजनाएं केन्द्रीय तथा राज्य सरकार (50:50) के आधार पर लागू की गई हैं। वर्ष 2015-16 में क्रमश: कुल 1471.91 लाख रुपये तथा 399.984 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा इन स्कीमों के अन्तगर्त अनुदान पर बीज, कीटनाशक, शुक्ष्म पोषक तत्व, जिप्सम, कृषि औजार, स्प्रिंकलर सैट आदि का प्रोत्साहन के रूप में आबंटन किया गया है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड राज्य में दलहनों के क्रय-विक्रय के लिए विभिन्न मार्किट कमेटियों के माध्यम से विपणन के लिये सुविधायें प्रदान कर रहा है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से किसानों को प्रोत्साहन देने के नाम पर जो कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध करता हूँ कि दालों की जो कीमतें हैं वे बहुत ज्यादा कम हैं इसलिए सरकार अपने स्तर पर केन्द्र सरकार से लिख कर दालों की कीमतें बढ़ाने का प्रयास करे। आज गेहूँ, सरसों और दालें तथा किसान की अन्य फसलें एक महीने में पक कर मंडियों में आ जायेंगी। जब मंडी में किसान की फसल आती है तो उसका भाव 30-35 रूपये प्रति किलो के भाव से मिलता है और जब वही चीज किसान के हाथ से निकल कर बाजार में आती है तो उन तमाम चीजों के भाव सातवें आसमान पर पहुंच जाते हैं। उससे भी आगे जब किसी स्टोर से किसी नमक और मसाले वाले चिप्स का पैकेट लेने जाते हैं तो उसके भाव 200-250 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार अपने स्तर पर केन्द्र सरकार से भाव बढ़वाने के प्रयास करे। दूसरी बात मैं स्प्रिंक्लर सिस्टम के बारे में पूछना चाहता हूँ। इस विषय पर पिछली सरकार ने तो कोई नेक काम नहीं किया था लेकिन इस सरकार ने भी किसानों के साथ ज्यादती करने का ही काम किया है। पहले स्प्रिंक्लर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगवाने के लिए सब्सिडी काट कर किसान से कीमत लेते थे और अपने-आप सारा सैट लगा कर जाते थे लेकिन अब जिस कम्पनी से सैट खरीदे जाते हैं वह कम्पनी कहती है कि पहले आप पूरा पैसा हमारे पास जमा कीजिए उसके बाद आपको सब्सिडी दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने अपने खेत में 10 एकड़ में अमरूद लगवाया है और उसको लगवाए हुये एक साल हो गया है तथा उसके सारे पैसे मैंने अपनी जेब से भरे हैं। 11 :00 बजे अध्यक्ष महोदय, जो फलदार पौधे थे हालांकि यह बात इस विषय से हट कर है लेकिन फिर भी कृषि मंत्री जी मैं यह बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। मैंने पिछले सैशन में भी यह बात उठाई थी कि जो फलदार पौधे हैं वह बहुत ज्यादा महंगे हो गये हैं और स्प्रिंक्लर सिस्टम के ऊपर जो सब्सिडी है वह मुझे आज तक नहीं मिली। यदि एक एम.एल.ए. का यह हाल था तो एक साधारण किसान को इसमें क्या राहत मिलेगी ? इसके बारे में आप अपने महकमें को सचेत करें कि यह जो स्प्रिंक्लर सिस्टम पर सब्सिडी मिलती है वह जल्दी से जल्दी मिले। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह दालों के भाव बढ़ाने की है जिसको केन्द्र के स्तर पर करें तभी जाकर आपका यह डायवर्सिफिकेशन का स्वप्न पूरा होगा वर्ना इसमें किसान को कोई राहत मिलने वाली नहीं है।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक का जो कंसरंड है वह बहुत वाजिब है। वास्तव में यह कहूंगा कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम दलहन की खेती को बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं पा रहे हैं और उसका एक कारण दलहन की ऑर्गेनाइज्ड खरीद का अभाव है, अच्छे भाव का अभाव है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से हम गेहूं और धान की प्रिक्योरमैंट बहुत संगठित तरीके से करते हैं और एक निश्चित समय में करते हैं जिसमें किसान को लगता है कि अगर इस फसल का इतना उत्पादन होता है तो इतने पैसे तो आ ही जाएंगे। लेकिन किसान दलहन के बारे में, दालों के बारे में उतना सुनिश्चित नहीं होता। यह दोनों विषय कि दालों के अच्छे भाव मिले और भाव ही न मिले बल्कि मंडियों में दालों की खरीद भी हो, ऑर्गेनाइज्ड खरीद हो इन दोनों विषयों की वास्तव में आवश्यकता है। मैं भी उनकी इस बात से सहमत हूं। राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ बार-बार इन विषयों को उठाती है। आगे जो रबी की फसल आ रही है उसके लिए पुरजोर ताकत के साथ हम राज्य सरकार की तरफ से इस पक्ष को सी.ए.सी.पी. के सामने भी रखेंगे जो पैसे तय करने वाला केन्द्रिय बोर्ड है। इसकी खरीद के बारे में भी हम कृषि मंत्रालय भारत सरकार से बात करेंगे। इन्होंने जो दूसरी बात कही उसमें हमारे सामने एक झंझट है और उस झंझट का समाधान करने का रास्ता बाकी सदस्यों को भी सुझाना चाहिए। पहले सामान्यत: ऐसा रहा है कि सब्सिडी सीधी कंपनियाँ ले लेती है और उसमें से वह कितना गोलमाल करती हैं उसका कोई हिसाब नहीं रहता। किसान जब दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि अगर सीधा भाव लगवाएगा तो यह भाव है और सब्सिडी का भाव लगवाएगा तो इससे डेढ़ गुणा भाव है इसमें वह गलत तो नहीं कह रहा है। अब उसमें से एक विषय सामने आया है कि हम सब्सिडी का पैसा डायरैक्ट किसान को दें और जब हम सब्सिडी का पैसा डायरैक्ट किसान को दे रहे हैं तो फिर कम्पनी वाला किसान से पूरे पैसे मांगता है और पूरे पैसे किसान के पास होते नहीं। यानि हम एक जो अच्छाई ला रहे हैं वह अच्छाई एक तरह से यहां आकर बुराई में बदल गई है क्योंकि पूरे पैसे न होने से किसान उसको खरीद नहीं पाता, ले नहीं पाता और उसके कारण से बात यहां आकर अच्छाई में से अटक रही है। इसका समाधान डिपार्टमैंट वाईज क्या करें किस तरह से इस रास्ते पर आगे बढ़ें हम यह सोच रहे हैं। लेकिन इसमें पैसा डायरैक्ट किसान के पास जाने से किसान मालिक हो जाता है कि मैं कौन सी कम्पनी का सैट खरीदूं, कौन सी दुकान से खरीदूं, कौन सा लगवाऊं लेकिन जब कम्पनियों की लिस्ट दी जाती है तो मलकियत अर्थात एक तरह से फैंसला करने की ताकत किसान की नहीं रहती कम्पनी की हो जाती है और कम्पनी एक काम और भी करती है वह लॉबिंग करके हमारी सब्सिडी को जल्दी भी खर्च करवा देती है। वह जा-जाकर हमारी सब्सिडी को लगवा देती है क्योंकि उसमें उसका वेस्टिड इंट्रस्ट होता है, उसका प्रोफिट बनता है। अगर वह कोशिश नहीं करती तो जितनी सब्सिडी जानी चाहिए उतनी भी नहीं जाती क्योंकि किसान अपने लेवल पर इंसैंटिव नहीं लेता। मशीनरी उस लेवल पर काम नहीं कर पाती। इनकी जो कठिनाई है वह भी इन्होंने बताई उसके लिए मैं विभाग से जितने भी लोगों की ऐसी सब्सिडी बची हुई है वह तुरंत जारी कराएंगे। एक प्रश्न मैंने हाऊस में खड़ा किया है अगर किसी सदस्य के मन में इसके बारे में और अच्छे सुझाव हों तो डिपार्टमैंट को बताईयेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Pardhan Mantri Jan Dhan Yojana

***1232. Sh. Rajdeep Phogat :** Will the Finance Minister be pleased to state the number of zero balance accouts opened for the BPL families under "Pardhan Mantri Jan Dhan Yojana" in the State from October, 2014 till to date together with the districtwise number of families to whom the financial assistance has been provided under the said insurance scheme in case of accidents.

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

अ- राज्य में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 15 जनवरी 2016 तक 5258697 बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से 21.37 प्रतिशत, यानि, 1123573 बैंक खाते पूंजीविहीन हैं। बैंक केवल बी0पी0एल0 परिवारों के खोले गए खातों का विवरण नहीं लेते क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सभी परिवार जिनका कोई बैंक खाता नहीं था उनको इसमें सम्मिलित करने का प्रावधान था।

ब- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत अक्तूबर, 2014 से जिलावार कुल 87 परिवारों (विवरण अनुलग्नक में संलग्न है) को दुर्घटना बीमा के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमा क्लेम।

क्रमांक	जिला	दर्ज हुए दावों की संख्या	निपटाये गये दावों की संख्या	कुल राशि (लाखों में)
1	रोहतक	11	11	11
2	यमुनानगर	16	16	16
3	जींद	2	2	0.6
4	करनाल	0	0	0
5	झज्जर	17	8	8
6	पानीपत	0	0	0
7	सोनीपत	10	8	8
8	भिवानी	0	0	0
9	कैथल	0	0	0
10	कुरूक्षेत्र	7	6	6
11	सिरसा	0	0	0
12	हिसार	4	4	4
13	रेवाड़ी	2	1	1

14	फतेहाबाद	3	1	1
15	रेवाड़ी	4	4	4
16	अम्बाला	14	14	14
17	नारनौल	7	7	6.3
18	मेवात	1	1	1
19	फरीदाबाद	1	1	1
20	गुड़गांव	1	1	1
21	पलवल	5	2	2
	कुल	**105**	**87**	**84.9**

Details of Loans and Capital Expenditure

***1238 Sh. Abhay Singh Chautala :** Will the Finance Minister be pleased to state :-

(a) the month wise detail of Loans/Market Borrowing through sale of securities or otherwise from the market by the State Government for the period from 01-04-2015 to 29-02-2016 : and

(b) the month wise detail of Capital Expenditure (Revenue Capital/ Accounts) incurred for the period from 01-04-2015 to 29-02-2016

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(क) वर्ष 2015-16 के दौरान मासवार बाजारी ऋण का विवरण।

क्रम संख्या	मास का नाम	रु० करोड़ों में
1	मई 2015	1900.00
2	जून 2015	1000.00
3	जुलाई 2015	1900.00
4	अगस्त 2015	1000.00
5	सितम्बर 2015	2000.00
6	नवम्बर 2015	800.00
7	दिसम्बर 2015	1900.00
8	जनवरी 2016	1100.00
9	फरवरी 2016	2500.00
योग		**14100.00**

वर्ष 2015-16 में बाजारी ऋण की राशि रु0 17019 करोड़ हरियाणा विधान सभा द्वारा अनुमोदित की गई।

(ख) प्रधान महालेखाकार, हरियाणा से प्राप्त सिविल लेखा अकाउंट के अनुसार राज्य का मासवार अनुमानित पूंजीगत व्यय का विवरण :-

क्रम संख्या	मास का नाम	पूंजीगत व्यय की राशि (रु० करोड़ों में)
1	अप्रैल 2015	146.77
2	मई 2015	589.37
3	जून 2015	365.55
4	जुलाई 2015	320.94
5	अगस्त 2015	230.00
6	सितम्बर 2015	341.55
7	अक्तूबर 2015	542.14
8	नवम्बर 2015	461.25
9	दिसम्बर 2015	437.97
10	जनवरी 2016	436.31
योग		**3871.85**

To Fill up the Vacant Posts of Doctors

***1287. Shri Makhan Lal Singla :** Will the Health Minister be pleased to state :-

(a) the number of posts of doctors lying vacant in General Hospital, Sirsa togetherwith the time since these post are lying vacant; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the vacant posts of doctors in the abovesaid Hospital; if so, the details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

(क) श्रीमान जी, नागरिक अस्पताल, सिरसा में चिकित्सकों के स्वीकृत पद तथा रिक्तियों का विवरण निम्न हैं :-

पद नाम	सितंबर 2014 को स्थिति			11.03.2016 को स्थिति		
	स्वीकृत	भरे हुये	रिक्त	स्वीकृत	भरे हुये	रिक्त
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3	3	0	3	4	1 सरप्लस
चिकित्सा अधिकारी	43	27	16	43	30	13

(ख) जब भी नई भर्ती होगी रिक्त पदों को भरने के लिये प्रयास कर लिये जायेंगे।

———————

Construction of By-Pass

***1247. Shri Naresh Kaushik :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a by-pass in north side of the Bahadurgarh; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी।

Survey of BPL

***1257. Shri Balwant Singh :** Will the Rural Development Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct new BPL survey; if so, the time by which it is likely to be conducted ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी। अत: इस प्रकार समय सीमा से संबंधित प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

Replacement of Obsolete Electricity Wires

***1223. Shri Naseem Ahmed :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electricity wires in Sakras, Biwan, Pathkhori, Mahum, Nagina, Dondal, Umra, Ibrahembas, Agon, Doha, Badarpur, Rithar etc. villages of Firozepur Jhirkha constituency; if so, the time by which the said obsolete wires are likely to be replaced ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, नहीं। विभिन्न क्षेत्रों में तारों को आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदला जाता है।

Demand and Supply of Electricity

***1261 Shri Bhagwan Dass Kabirpanthi :** Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) whether it is a fact there is a great difference between demand and supply of electricity in the State; if so, the details thereof; and

(b) whether the efforts are being made by the Government to augment the capacity of existing power houses; if so, the names of power houses for which the proposal has been prepared ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान,

(क) नहीं, श्रीमान। प्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उत्पादन स्टेशनों से सप्लाई शेड्यूल्ड है।

(ख) अगले कुछ वर्षों के लिए प्रर्याप्त बिजली की उपलब्धता के कारण ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***1271. Balkaur Singh :** Will the Chief Minister be please to state :-

(a) Whether it is a fact that scheme for installation Solar System has been implemented in the State; if so the full details thereof together with the subsidy given under the scheme; and

(b) Whethe any special concession under the scheme has been given to the Scheduled Castes; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हाँ, श्रीमान जी राज्य में 24.55 मेगावाट क्षमता के 165 सौर उपकरण स्थापित किये गये हैं और 3.97 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

Repair/Reconstruction of Roads

***1306. Sh. Mahipal Dhanda :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the roads of Sector-24, 25, 29, 6, 17, 13 and 18 of HUDA in District Panipat are in very bad condition; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct or repair the above said roads togetherwith the time by which the above said roads are likely to be repaired reconstructed ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

सैक्टर - 24, 25, 29, 6, 17, 13 और 18 पानीपत की कुछ सड़कों की मुरम्मत हाल ही में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है तथा इन सड़कों की स्थिति अच्छी है। सभी सड़कों को यातायात योग्य रखने के लिये नियमित रखरखाव किया जा रहा है। इन सैक्टरों में बाकी बची सड़कों की, जिनकी विशेष मुरम्मत की आवश्यकता है, एक वर्ष से कम समय में मुरम्मत कर दी जाएगी।

Appointment of Doctors

***1313. Dr. Pawan Saini :** Will the Health Minister be pleased to state the time by which the appointment of Lady Doctors, Medicine doctors and surgeons are likely to be made in the Hospital of Ladwa and whether there is any proposal under consideration of the Government to appoint MD medicine and MS surgeon in the said Hospital ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पद केवल वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी के काडर के हैं न कि विशेषज्ञ काडर के हैं।

वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाडवा में एक महिला चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है।

अतारांकित प्रश्न एंव उत्तर

State Nourishing Mission

288. Shri Balwan Singh Daulatpuria : Will the Women and Child Development Minister be pleased to state the details of the scheme formulated by the Government under State Nourishing Mission for children, girls and women to check malnutrition and deficiency of blood ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, राज्य पोषण मिशन बनाया जा रहा है।

Supply of Electricity

264. Shri Kehar Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply round the clock electricity to the farmers of Haryana; if so, the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान

To Open a Madical College

282. Sh. Ravinder Baliala : Will the health Minister be pleased to state whether is any proposal under consideration of the Government to open a Medical College in Ratia Assembly constituency; if so, the time by which the said college is likely to be opened ?

स्वस्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

Land under the Municipal Committee of Rania

328. Shri Ramchand Kamboj : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state :-

(a) the total acreage of land under the Municipal Committee of Rania together with the details of agricultural, Commercial land separately; and

(b) the land under possession of Rania Municipal Committee together with the yearly income thereof?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

नगर पालिका, रानियां के अधिकार क्षेत्र की कुल भूमि का विवरण

(i)	कास्त गैर मुमकिन (प्राईवेट व्यक्तियों के कब्जे में)	= 77 एकड़ 7 कनाल 2 मरला
(ii)	गैर मुमकिन प्लाट (प्राईवेट व्यक्तियों के कब्जे में)	= 37 एकड़ 5 कनाल 6 मरला
(iii)	कृषि भूमि (नगर पालिका, रानियां के कब्जे में)	= 13 एकड़ 1 कनाल 6 मरला
(iv)	व्यवसायिक भूमि (नगर पालिका, रानियां के कब्जे में)	= 2 कनाल 14 मरला
(v)	खाली भूमि (नगर पालिका, रानियां के कब्जे में)	= 4 एकड़ 6 कनाल 0 मरला
(vi)	पार्क (नगर पालिका, रानियां के कब्जे में)	= 7 एकड़ 0 कनाल 13 मरला
(vii)	गऊशाला (नगर पालिका, रानियां के कब्जे में)	= 4 एकड़
(viii)	शमशान भूमि (नगर पालिका, रानियां के कब्जे में)	= 2 एकड़ 7 कनाल 7 मरला
(ix)	खेल विभाग के पास स्टेडियम के लिए	= 5 एकड़ 7 कनाल 10 मरला
(x)	उद्योग विभाग के पास आई.टी.आई. के लिए	= 5 एकड़
(xi)	तहसील के लिए	= 13 कनाल
(xii)	पशुपालन विभाग के पास अस्पताल के लिए	= 13 कनाल
(xiii)	प्राथमिक पाठशाला	= 1 एकड़
(xiv)	उच्चतर पाठशाला	= 5 कनाल 19 मरला
(xv)	जन स्वास्थ्य विभाग	= 15 कनाल 6 मरला
(xvi)	नगर पालिका कार्यालय	= 6 कनाल 0 मरला
(xvii)	ग्राम पंचायत के समय से अवैध कब्जे में है और कथित भूमि पर आर.एस.ए. नं0 2791 ऑफ 2004 के अन्तर्गत विचारधीन है, भूमि के कब्जे बारे स्थगन आदेश है।	= 2 एकड़ 7 कनाल 7 मरला
	कुल	= 183 एकड़ 5 कनाल 18 मरला

(क) नगर पालिका, रानियां के अधिकार क्षेत्र में कुल 183 एकड़ 18 मरले भूमि है, जिसमें 13 एकड़ 1 कनाल 6 मरला कृषि भूमि है तथा 2 कनाल 14 मरला व्यवसायिक भूमि है।

(ख) नगर पालिका, रानियां के अधिकार क्षेत्र की 13 एकड़ 04 कनाल भूमि से कुल वार्षिक आय 25,11,210/-रुपये प्राप्त होती हैं।

---

262. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Chief Minister be pleased to state :-

(a) The number of power plants sanctioned since October 2014 till date;

(b) The number of Solar Power Plants operating in the state; and

(c) The details of subsidy provided by the state Government to install renewable energy plants?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(अ) अक्तूबर, 2014 के बाद 174 सौर विद्युत संयंत्र एवं 3 बायोमास विद्युत संयंत्र स्वीकृत किए गए है।

(ब) राज्य में 165 सौर विद्युत संयंत्र चल रहें हैं।

(स) रूफटोप ग्रिड क्नेक्टिड/ऑफग्रिड सौर विद्युत संयंत्रों के लिए राज्य अनुदान के रूप में 3.97 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

---

285. Shri Ved Narang : Will the Environment Minister be pleased to state whether it is a fact that the water of Yamuna River is being polluted by the industries of Haryana and U.P.; If so whether there is any proposal under consideration of the Government to check the pollution in Yamuna river together with the details of financial assistance provided by Central Government alongwith the total amount spent on it ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हाँ, श्रीमान जी, यह सत्य है कि हरियाणा के उद्योगों से उपचारित तथा अनुपचारित बहि:स्त्राव बहाव यमुना नदी में बहाया जा रहा है।

हरियाणा राज्य यमुना नदी में औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी उद्योगों ने अपने बहि:स्त्राव को उपचार करने के लिए अपने पास व्यक्तिगत बहि:स्त्राव संयन्त्र (ई.टी.पी.) लगा रखे हों या वे इसे यमुना नदी में मिलने वाले नालों में बहाने से पहले बहि :स्त्राव उपचार संयन्त्रों (सी.ई.टी.पी.) में उपचारित कर रही हो।

उद्योगों के व्यक्तिगत ई.टी.पी./सी.ई.टी.पी. के इलावा, हरियाणा राज्य उद्योग तथा अवसंरचना विकास निगम (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) तथा हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (हुड्डा) के पास यमुना नदी में मिलने वाले नालों में बहि:स्त्राव के बहाव से पूर्व औद्यागिक बहि :स्त्राव के उपचार के लिए 66 मिलीयन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) की क्षमता के लिए 6 और सी.ई.टी.पी. हैं। एच.एस.आई.आई.डी.सी. गुड़गांव, रोहतक तथा सोनीपत जिलों में औद्योगिक बहि:स्त्राव के उपचार के लिए 66 मिलीयन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.)की क्षमता के 4 और सी.ई.टी.पी. स्थापित कर रही है।

एच.एस.आई.आई.डी.सी. तथा हुड्डा ने इन सी.ई.टी.पी. की स्थापना के लिए "निर्यात अवसंरचना तथा सम्बद्ध स्कीम विकास के लिए राज्यों को सहायता" के अंतर्गत भारत सरकार से 2014-2015 के दौरान 15.24 करोड़ रुपये तथा 2015-2016 के दौरान 5.00 करोड़ रुपए की कुल राशि प्राप्त की है। इनमें से 2014-2015 के दौरान प्राप्त 10.24 करोड़ रुपए पहले ही खर्च कर लिए गए हैं।

Allotment of plots by HSIIDC

291. Sh. Jaswinder Singh Sandhu : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state the total number of plots and the name of person to whom the plots have allotted in Industrial Essetes/IMTs areas by the HSIIDC in the State from April, 2005 to October 2014 together with the name of the Industrial units which has started functioning alongwith the details thereof ?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी,

(1) एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने अप्रैल, 2005 से अक्तूबर 2014 के दौरान अपनी विभिन्न औद्योगिक सम्पदाओं/आई.एम.टीज. में 5222 औद्योगिक प्लाट आबंटित किए थे। जिन व्यक्तियों को ये प्लाट आबंटित किए गए थे उनके आंबटन का नाम सहित विवरण ***अनुबन्ध-1** में प्रस्तुत है।

(2) उपरोक्त 5222 प्लाटों के आबंटन में से अप्रैल 2005 से 31 अक्तुबर 2014 की अवधी के दौरान 3116 ईकाईयाँ क्रियान्वित/कार्य प्रारम्भ कर चुकी हैं। इन 3116 मामलों का विवरण **अनुबन्ध-2** पर प्रस्तुत है। बाकी प्लॉट या तो आंबटी द्वारा अर्पित (सरैंडर) कर दिये गये हैं या निगम द्वारा पुन: प्राप्त (रिज्युम) कर लिये गये हैं अथवा क्रियान्वयन के अन्तर्गत हैं।

295. Shri Naseem Ahmed : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state :-

(a) the blockwise details of the fund provided to the district Mewat under the HRDF scheme during the year from 2009 to 2015; and

(b) whether the works have been completed for which the above said funds have been allotted; if so, the details and names of the villages in which these works have been performed?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया है।

वक्तव्य

(क) वर्ष 2009 से 2015 के दौरान हरियाणा ग्रामीण विकास निधि योजना के अंतर्गत जिला मेवात को कराई गई निधि का ब्लॉकवार बयौरा **पताका 'क'** पर रखा है।

(ख) पूर्ण कार्यों तथा अन्य कार्यों का ब्यौरा जिनके लिए उक्त समय में राशि जारी की गयी है ***पताका 'ख'** पर रखा है।

Opening of P.H.C.

296. Shri Rajdeep Phogat : Will the Health Minister be pleased to state the time by which the PHC is likely to be opened in village Imlota of Dadri consituency which was declared two years ago?

---

* पूर्व प्रथानूसार अनुबंध-1 तथा 2 विस्तृत होने के कारण विधान सभा की लाईब्रेरी में रखवाया गया।

* पूर्व प्रथानूसार पताका 'क' तथा 'ख' विस्तृत होने के कारण विधान सभा की लाईब्रेरी में रखवाया गया।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, गांव ईमलोटा में 05.08.2014 से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से ही कार्यरत है।

To open a Regional Centre of Agriculture University

233. Shri Hari Chand Middha : Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Regional centre of Agriculture and Hotriculture University in Jind city; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैंने हैपेटाईटिस, दलितों तथा महिलाओं पर अत्याचार व बलात्कार रोकने, स्कूलों की दशा सुधारने, प्रदेश में टूटी हुई सड़कों की दशा तथा दूसरे अनेक महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों पर कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिये थे। अध्यक्ष महोदय, उनका क्या फेट है? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, सभी विषयों पर कालिंग अटैंशन थोड़े ही दिये जाते हैं लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा हैपेटाईटिस विषय पर दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकर कर लिया गया है तथा ओलावृष्टि विषय पर दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21.3.2016 के लिए लगा दिया गया है। बाकी जो अन्य विषय हैं उन पर आप राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तफसील से अपनी बात रख सकते हैं। जिन विषयों पर तुरन्त प्रभाव की जरूरत थी उनको मैंने स्वीकार कर लिया है। (विघ्न)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : स्पीकर सर, मैने भी कुछ कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिये थे। विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि जिन विषयों पर तुरन्त प्रभाव की आवश्यकता थी, उन विषयों पर आधारित आपके कालिंग अटैंशन नोटिसिज को स्वीकार कर लिया गया है। ढुल साहब जो आपने " थारी पैंशन-थारे पास" बुजुर्गों को पैंशन का लाभ न मिलने की समस्या पर कालिंग अटैंशन नोटिस दिया था उसको मैंने 17.3.2016 के लिए स्वीकार कर लिया है। (विघ्न)

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मैंने हरियाणा राज्य में परिवहन समितियों की बसों का बंद करने विषयक एक कालिंग अटैंशन नोटिस दिया है। मुझे उसका फेट बताया जाये। अध्यक्ष महोदय, इस निर्णय की वजह से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, वैसे तो यह कालिंग अटैंशन नोटिस विचाराधीन है लेकिन अब जबकि आपने इस बारे में पूछ ही लिया है तो मैं इस पर जल्द ही निर्णय करूंगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूँगा कि जो आपने वर्तमान समय में बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि तथा हैपनिंग हरियाणा पर कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिये थे उनको मैनें स्वीकार कर लिया है।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध केवल मात्र परिवहन समितियों की बसों को बंद करने विषयक कालिंग अटैंशन नोटिस के बारे में है। आप इस कालिंग अटैंशन नोटिस को जल्द से जल्द लगायें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, मैं इस पर जल्द ही निर्णय करूंगा। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, मैंने बिजली के बढ़े हुए बिलों के बारे में भी एक कालिंग अटैंशन नोटिस दिया था। आपसे अनुरोध है कि उसका भी फेट बताया जाये।

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, आपके द्वारा दी गई कई कालिंग अटैंशन नोटिसिज को आने वाले तीन दिनों के लिए स्वीकार कर लिया गया है और जो आपने अभी अपने कालिंग अटैंशन नोटिस का फेट पूछा है तो उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संबंध में जल्द ही निर्णय किया जायेगा। आप आज के लिए जो कालिंग अटैंशन मोशन स्वीकृत है उस पर चर्चा कर लीजिए।

मुख्य संसदीय सचिव श्री श्याम सिंह राणा को उनकी सद्भावना (हारमोनी) पद यात्रा के लिए बधाई

श्री सुभाष बराला : माननीय अध्यक्ष, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : बराला जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों हरियाणा में जिस प्रकार का वातावरण रहा उसकी वजह से हमारे समाज में कुछ विकट परिस्थितियां पैदा हो गई थी। समाज के ताने बाने को सदृढ़ करने के लिए तथा आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य संसदीय सचिव तथा विधायक माननीय श्री श्याम सिंह राणा जी एक सद्भावना पद यात्रा पूरी करके इस सदन में पहुंचे हैं। मैं समझता हूँ कि एक पवित्र उद्देश्य के लिए की गई उनकी सद्भावना यात्रा की इस सदन के माध्यम से हौसला-अफज़ाई करते हुए सरहाना की जाए। (इस समय मेजें थपथपाई गई)

श्री अध्यक्ष : राणा जी, आपने समाज की भलाई व आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए जो यह सद्भावना यात्रा की है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री श्याम सिंह राणा जी सद्भावना यात्रा नहीं बल्कि सद्भावना पद यात्रा करके विधान सभा में पहुंचे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय,. . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, श्याम सिंह राणा जी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं एक बार उन्हें अपनी बात कह लेने दें।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री श्याम सिंह राणा) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के माध्यम से इस सद्भावना यात्रा के पीछे जो मेरी भावना रही है उसको बताना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश के विकट हालात को देखकर मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि मुझे अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए और जरूरत समझी की ऐसे विकट हालात में हरियाणा प्रदेश में सद्भावना यात्रा

की बहुत आवश्यकता है। लोगों के दिलो में आपसी प्रेम व भाईचारा पैदा करने करने व एकता का संदेश देने के लिए मैंने रादौर से हरियाणा विधान सभा तक सद्भावना यात्रा पूरी की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस यात्रा में तय की गई दूरी राणा जी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जो पद यात्री होते हैं वह एक दिन में औसतन 30 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं जबकि राणा जी ने तो एक दिन में 50 किलोमीटर की पद यात्रा की है। (शोर एवं व्यवधान) राणा जी, आप अपनी बात कांटीन्यू रखिये।

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, रादौर से हरियाणा विधान सभा की दूरी 120 किलोमीटर की है। 120 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा करने में मुझे अढ़ाई दिन का समय लगा। मैं दो दिन 50-50 किलोमीटर चला और तीसरे दिन चण्डीगढ़ पहुंच गया। यहां का जो 20 किलोमीटर का एरिया है उसमें धारा 144 लगी होने की वजह से मैनें यह यात्रा पांच अन्य सदस्यों के साथ पूरी की। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े लोगों ने भी पैदल यात्राएं की हुई हैं। स्वर्गीय चौधरी चन्द्र शेखर जी ने कन्याकुमारी से दिल्ली राजघाट तक की 6000 किलोमीटर की यात्रा 5 महीने 26 दिन में पूरी की थी। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने भी देश भर में पैदल यात्रा की थी। उस वक्त अभय सिंह चौटाला जी भी थोड़ा बहुत राजनीति में हिस्सा लिया करते थे। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझसे कहा था कि भाई श्याम सिंह आप देवी लाल जी के साथ यात्रा करो तो मैंने उस समय स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के साथ भी यात्रा की थी। परन्तु उस वक्त की यात्रा में जो लोगों का एक लगाव हुआ करता था वैसा अब देखने को नहीं मिलता। यह देश महात्मा गांधी का देश है। एक बार उन्होंने कहा था कि जब देश के नेता हिन्दुस्तान की जान कहे जाने वाले गावों में यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई नतीजा सामने निकलकर आयेगा और देश की समस्याओं का कोई न कोई समाधान अवश्य निकलेगा। आज प्रदेश में जो वातावरण बना हुआ है उस वातावरण में इस सदन के सभी 90 विधायकों को अपने अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई न कोई यात्रा जरूर करनी चाहिए। जब हम लोगों के बीच जाकर उनकी बात सुनेंगे तो हम नजदीक से लोगों के मन टटोल सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरी इस यात्रा के दौरान जाट बिरादरी के लोगों ने भोजन व अन्य दूसरी सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा। यही नहीं वह मेरे साथ हाथ में झंडा लेकर आगे-आगे भी चले। जाट बिरादरी के लोगों ने इस पद यात्रा को बहुत सम्मान दिया। अध्यक्ष महोदय, यह देश संत फकीरों का देश है। हमारे समाज को साधू-संतों तथा फकीरों ने बनाया है। यह समाज किन्हीं पॉलिटिकल लीडर्ज का बनाया हुआ नहीं है। हमारी 36 बिरादरी के रहने के सौहार्दपूर्ण तरीके का निर्माण हमारे देश के संतों ने, फकीरों ने, ऋषियों ने तथा मुनियों ने बहुत ही गूढ ढंग से किया है। हमारा समाज अमर है परन्तु व्यक्ति नाशवान है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इस समाज के अन्दर कोई विघ्न डालता है तो यह समाज उसको कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी मालूम है कि जब यह समाज किसी को बनाता है तो उसको बुलंदियों तक उपर उठाता है। चौधरी देवी लाल ने पद यात्रा की तो लोगों ने उनको पलकों पर बिठाया। श्री चन्द्र शेखर ने पद यात्रा की तो लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचाया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप बिश्नोई : एक यात्रा का जिक्र और कर दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिश्नोई जी, आपने ट्रैक्टर की यात्रा की थी।

श्री श्याम सिंह राणा : बिश्नोई जी, आपने ट्रैक्टर यात्रा के साथ-साथ एक यात्रा और की थी। उस यात्रा में मैं आपके साथ था। यमुनानगर की यात्रा में भी मैं आपके साथ था।

श्री अध्यक्ष : बिश्नोई जी, श्री श्याम सिंह जी सब यात्राओं में आपके साथ थे।

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि समाज को मत बांटो। यदि कोई भी नेता अपने स्वार्थ के लिए समाज बंटेगा तो समाज का ही नुकसान होगा। किसी भी व्यक्ति को सरकारी संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है। आदमी अपनी सारी जिन्दगी में बड़ी मुश्किल से घर और दुकान बनाता है यदि उसका घर या दुकान फूकेंगे तो उसके मन पर क्या बितेगी ? इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी का मकान या दुकान न फूंके जिससे उसका कोई भी नुकसान न हो। भाईचारे का यह संदेश सदभावना यात्रा के माध्यम से दे सकते हैं। जो भाईचारे का संदेश हम टी.वी. एवं अखबारों के माध्यम से देते आए हैं अगर वही संदेश लोगों के बीच में जाकर देंगे तो सौ फीसदी उसका पोजिटिव असर पड़ेगा। श्री बख्शीश सिंह, बहन सीमा त्रिखा, श्री बलवंत सिंह, श्री घनश्याम जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और विशेषकर श्री नायब सैनी जी ने सदभावना यात्रा में भाईचारे का संदेश देने में मेरा भरपूर सहयोग किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सच्चाई के साथ कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के लोग आपस में मिलजुल कर इक्ट्ठा हो कर रहना चाहते हैं, उन्हें रहने दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

आदमपुर निर्वाचन क्षेत्र जिला हिसार के गांवों में हाल में हुई वर्षा तथा ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त फसलों का मामला उठाना।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में आए तुफान और ओलावृष्टि से मेरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में फसलों का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। आदमपुर, नलवा और हांसी हल्के के सदलपुर, सारणपुर, बाणा, चुल्लड़, चौधरीवास, पनिहार, कालवास आदि गांवों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके कारण लोग उचित मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार स्पेशल गिरदावरी करवा कर किसानों को उचित मुआवजा दे।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बराला साहब ने सदन को बताया कि श्री श्याम सिंह जी ने 120 किलोमीटर सदभावना यात्रा निकाली थी। श्री श्याम सिंह जी ने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे की भावना से रहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी हरियाणा प्रदेश के 21 जिलों में जाकर सदभावना सभाएं करके शांति बनाए रखने की अपील की थी। सदभावना सभा में हर बिरादरी के लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था। मैं इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता कि यह उग्र प्रदर्शन किसने किया? हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक की इच्छा है कि 36 बिरादरी के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। आपस के भाईचारे को खत्म करने वाले लोगों के नाम सरकार को बताने के बावजूद भी

सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई का एक भी कदम नहीं उठाया गया है। जिन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत सरकार को मिल गए उनके खिलाफ तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं अपनी तरफ से श्री श्याम सिंह जी को सदभावना यात्रा निकालने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। श्री श्याम सिंह जी का सुझाव मानकर सभी विधायक अपने-अपने हल्कों में जायेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में भाईचारे का माहौल बना रहेगा। इससे प्रदेश के भाईचारे को तोड़ने वाले लोग जनता के सामने आ जाएंगे और जनता को पता लग जाएगा कि किन लोगों ने इसका राजनैतिक लाभ लेने के लिए हरियाणा प्रदेश को आग के हवाले किया है। इस कार्य से सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और उन्हें अहसास होगा कि आप सद्भावना रखना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके अन्य साथी भी आपके पदचिह्नों पर चलेंगे न कि प्रदेश के माहौल को बिगाड़ेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव-

कैंसर तथा हैपेटाईटिस-बी और सी संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे रविन्द्र सिंह विधायक तथा पांच अन्य विधायकों श्री बलकौर सिंह, केहर सिंह, नगेन्द्र भडाना, जसविन्द्र सिंह संधू, तथा राजदीप सिंह फौगाट की तरफ से हरियाणा प्रदेश में दिनोंदिन कैंसर व हैपेटाईटिस-बी और सी आदि बीमारियों के तेजी से बढ़ने और उनकी रोकथाम न होने के बारे में एक ध्यानाकर्षण सूचना प्राप्त हुई है। मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। श्री रविन्द्र सिंह, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ेंगे।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं और बलकौर सिंह केहर सिंह, नगेन्द्र भडाना जसविन्द्र सिंह सन्धु व राजदीप सिंह फौगाट विधायकगण इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय कि ओर दिलाना चाहते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में दिनों-दिन कैंसर एवं हैपेटाईटिस बी और सी आदि की बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं जोकि प्रदेशवासियों के लिए चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम आदमी के इलाज के लिए उचित चिकित्सा प्रबधों में लापरवाही बरती जा रही है और विभाग ने उनके स्वास्थ्य की कोई चिन्ता नहीं है। विभाग ने अभी तक इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई सार्थक प्रयास नही किए। हरियाणा में हर रोज कैंसर व अन्य बीमारियों से सैंकड़ों मौतें हो रही हैं और हजारों मरीज इन बीमारियों से पीड़ित हैं। इन बीमारियों से पीड़ित प्रदेशवासियों के प्रति सरकार के ऐसे बेरूखे व्यवहार की वजह से मरीजों का तो भगवान ही मालिक है। प्रदेश सरकार कैंसर व हैपेटाईटिस बी आदि बीमारियों को गंभीरता से नही ले रही और न ही इसके बारे स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है। सरकार के इस ढुलमुल रवैये से इन बीमारियों के मामलों में हर रोज वृद्धि हो रही है। हरियाणा के 23 प्रतिशत गांवों में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं और 17.7 फीसदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 58 फीसदी में स्टाफ के रहने के लिए भवन नही है, 70 फीसदी में महिला चिकित्सक नहीं और 37 फीसदी में इलाज का उचित प्रबंध नही हैं जिसकी वजह से आम आदमी के लिए निजी अस्पतालों में इलाज करवाना बस की बात नहीं। स्वास्थ्य विभाग की प्रचार-प्रसार में कमी के कारण लोगों को इन बीमारियों के बारे में जागरूकता नहीं।

अत: सरकार सदन में वक्तव्य दे।

वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबधी

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री महोदय उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : मैं विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा हरियाणा राज्य में सार्वजनिक महत्व जैसे कि कैंसर, हैपेटाईटिस बी तथा सी के बारे में व्यक्त की गई संवेदनशीलता की प्रशंसा करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग हरियाणा राज्य के किसी भी भाग से इन बीमारियों की आकस्मिक बढ़ोतरी की स्थिति की बारीकी से और लगातार निगरानी कर रहा है तथा इसके प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठा रहा है।

कैंसर किसी कोशिका अथवा अंग की असामान्य वृद्धि जो सामंजस्य रहित, अनियन्त्रित तथा अव्यवस्थित होती है जो उत्तेजना की समाप्ति पर भी जारी रहती है। कैंसर एक घातक रोग है जिसका यदि शीघ्र पता न लग पाए जो मौत का कारण बन जाता है। इसके अतिरिक्त, यह पीड़ित तथा उसके परिवार के लिए भीषण आघात, दर्द तथा वित्तीय बोझ का कारण बन जाता है।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि कैंसर की घटनाओं तथा कैंसर के कारण मौतों में वृद्धि हो रही है। इस विषय पर हरियाणा अथवा पूरे देश में कोई प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अधिकतर आंकड़े भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दर्ज की गई कैंसर की प्रविष्ठियों के आधार पर लिए गए अनुमानित आंकड़ों पर आधारित हैं। भारत में कैंसर के अनुमानित 29 लाख मामले हैं तथा हर वर्ष 11 लाख नए मामले जुड़ रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत जनसंख्या आधारित कैंसर प्रविष्ठियों के आधार पर बनाई गई तीन वर्ष 2009-11 तक की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में प्रति वर्ष कैंसर के अनुमानित 22430 मामले तथा 9870 मौतें दर्ज होनी सम्भावित हैं।

यह रिपोर्ट यह दर्शाती है कि कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या में हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में नाममात्र की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, दीर्घायु में वृद्धि, बेहतर जांच तथा उपचार सुविधाओं तथा बेहतर रिपोर्टिंग के परिणाम स्वरूप हुई है। हालांकि, कैंसर की प्रविष्ठियों की अनुपस्थिति में हरियाणा में कैंसर का कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है तथा आंकडों की डुप्लीकेसी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

कैंसर के रोगियों के उपचार में आरम्भिक पड़ताल, उपचार तथा तत्पश्चात फोलोअप सम्मिलित है। कैंसर मामलों के प्रबन्धन के लिए बहुअनुशासनात्मक तथा बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसका प्रभावी प्रबन्धन केवल तृतीय स्तरीय चिकित्सा संस्थानों में ही उपलब्ध है जहां फिजीशियन, सर्जन, पैथोलोजिस्ट, औंकोलोजिस्ट तथा रेडियोथैरेपिस्ट सहित जांच पड़ताल, कैमोथेरेपी इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

रीजनल कैंसर सेन्टर, पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक में व्यापक उपचार की सुविधायें हैं। यह केन्द्र 3 कोबाल्ट टैलीथैरेपी यूनिट तथा एक ब्रैकीथैरेपी मशीन से सज्जित है। करनाल,

नल्हड़ मेवात तथा खानपुर कलां, सोनीपत में तीन और चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं। धीरे-धीरे यहां पर कैंसर रोगियों के लिये टरसरी केयर ईलाज की सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी। गांव बाढसा जिला झज्जर में 32 एकड़ में 2035 करोड़ रुपये की लागत से 710 बिस्तरीय राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना भी क्रम में है।

स्वास्थ्य विभाग ने जिला स्तर पर कैंसर रोगियों को उपचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रभावकारी मापदण्ड अपनाए गए हैं। इसमें जनता में जागरूकता लाना, जीवन शैली के मुद्दे तथा पर्यावरण, निदान, तृतीयक स्तरीय संस्थानों में उपचार एवं अनुसंधान सम्मिलित है। जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ बिनाईन (benign) तथा आरम्भिक चरण के कैंसर संभालते हैं। विभिन्न नागरिक अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हरियाणा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नम्बर 46/19/2014-5एच.बी.। दिनांक 29.10.2014 द्वारा कैंसर को नोटीफायबल बीमारी भी घोषित किया गया है, जिसमें सभी निदान और उपचार केन्द्रों (सरकारी एवं निजी) को एक निर्धारित प्रोफार्मा में कैंसर के मामलों को रिपोर्ट करना होगा।

भारत सरकार का कैंसर, मधुमेह, ह्रदय रोग तथा अपघात की रोकथाम एवं नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम हरियाणा के मेवात, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, सिरसा तथा यमुनानगर जिलों में लागू किया जा रहा है। इन नागरिक अस्पतालों में लैब की सुविधायें मजबूत की गई हैं तथा विभिन्न अस्पताल जहां पैथोलोजिस्ट उपलब्ध हैं, में कैंसर के निदान के लिए पैप स्मीयर, फाईन नीडल एसपीरेशन साईटोलोजी, बायोपसी इत्यादि आरम्भ की गई हैं। इन जिलों से स्वास्थ्यकर्मी, स्टाफ नर्स तथा चिकित्सकों को कार्यक्रम राज्य की गतिविधियों में प्रशिक्षित किया गया है। कार्यक्रम जिलों में स्वास्थ्यकर्मी आम कैंसर जैसे कि मुंह तथा गले, स्तन तथा सरवाईकल के संदिग्धों को चुन रहे हैं। कार्यक्रम राज्य के अन्य 8 जिलों में विस्ताराधीन है। वित्त वर्ष 2016-17 में इस कार्यक्रम को राज्य के सभी जिलों में अमल/विस्तारित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिला मेवात, अम्बाला तथा कुरूक्षेत्र से 4 चिकित्सकों तथा 4 स्टाफ नर्सों को पैलिएटिव मैडिसिन संस्थान, मैडिकल कालेज कालीकट, केरला में पैलिटिव केयर में प्रशिक्षित किया गया है।

मार्च, 2015 में माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राज्य में कैंसर तथा हैपेटाईटिस सी के सभी पहलुओं के अध्ययन हेतु एक टीम गठित करने के लिए एक अर्द्धसरकारी प्रार्थना की गई थी इसके उपरांत अर्द्धसरकारी तौर पर हरियाणा में कैंसर राहत कोष गठित करने बारे मामले को जून, 2015 में उठाया गया था।

विभाग स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियां कर रहा है जिसके अंर्तगत जीवन शैली में परिवर्तन, दैनिक व्यायाम के लाभ, सन्तुलित आहार, खाने की आदतें तथा कैंसर के सामान्य लक्षणों से सम्बन्धित पोस्टर विकसित किए गए। इनको जन जागरूकता के लिए वितरित किया जा रहा है। गैर संचारी रोग की जागरूकता के बारे पुस्तिकाओं की छपाई प्रक्रियाधीन है।

लोगो में कैंसर के प्रति जागरूकता बनाने एवं बढ़ाने बारे स्वास्थ्य केन्द्रों पर विभिन्न कैंसर संबंधित दिवस जैसे कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी इत्यादि मनाये जा रहे हैं।

विश्व में तंबाकू का सेवन कैंसर को बढ़ाने का प्रमुख कारण है। भारत में लोगो का विशेषकर युवा तथा बच्चों को तबाकू के सेवन के बुरे प्रभावों से बचाते हेतु एक व्यापक कानून

[श्री अनिल विज]

(Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply, and Distribution) एक्ट 2003 लागू किया गया है। लोगो को तंबाकू के स्वास्थ्य पर प्रभावों तथा क्रय धूम्रपान बारे, तंबाकू विरोधी कानून के प्रावधान तथा समाज को तंबाकू के सेवन के प्रचलन को कम करके तथा उनको तम्बाकू का सेवन छोड़ने हेतु शिक्षित करने मे उनकी भूमिका बारे अवगत करवाया गया है।

राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र, बैंगलोर, राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान, भारत सरकार द्वारा राज्य के अलग अलग हिस्सों में कैंसर के बढ़ते मामलों के अवलोकन हेतु हरियाणा के लिए एक प्रोजेक्ट "इस्टैबिलिश्मेंट ऑफ कैंसर एटलस" को अनुमोदित तथा स्वीकृत किया गया है, जिसका अमल प्रक्रियाधीन है।

सभी कैंसर रोगियों को स्वास्थ्य केन्द्रों में ईलाज तथा फॉलोअप के लिए जाने हेतु हरियाणा परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

राजकीय मैडिकल कॉलेजों तथा स्नातकोत्तर केन्द्र रोहतक के अतिरिक्त निजि क्षेत्र में कई टरसरी केयर केन्द्र हैं जो राज्य के कैंसर मरीजों को व्यापक उपचार सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।

हैपेटाइटिस यकृत (लीवर) की सूजन है, जो वायरल संक्रमण के कारण होता है। हैपेटाइटिस वायरस पांच प्रकार का होता है- ए, बी, सी, डी, और ई। हैपेटाइटिस ए और ई दूषित खाना खाने और दूषित पानी पीने से होता है। हैपेटाइटिस बी, सी और डी शरीर के संक्रमित तरल पदार्थों के साथ संपर्क में आने से, दूषित रक्त या रक्त उत्पादों की प्राप्ति से, असुरक्षित यौन संबंध से, दूषित सूई और सीरिंज के उपयोग से होता है।

अतिपाति (Actue) हैपेटाइटिस में बहुत ही सीमित या कोई भी लक्ष्ण नही होता अथवा इसमें पीलिया (त्वचा व आंखों का पीला होना) गहरा पीला मूत्र आना, अत्याधिक थकान, उबकाई, उल्टी व पेट में दर्द हो सकता है।

हैपेटाटिस सी के बारे में स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में दिसम्बर 2011 में आया जब रतिया में हैपेटाटिस सी से ग्रस्त रोगी ध्यान में आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक एवं पी०जी०आई०एम०एस० चण्डीगढ़ की मदद से रतिया में हैपेटाइटिस सी की महामारी का कारण झोलाछाप डाक्टरों द्वारा बिना साफ की गई व सीरिंज से बार-बार टीका लगाना व एक ही सीरिंज से कई लोगो द्वारा नाड़ी में नशे का टीका लगाने तथा असुरक्षित यौन संबंध बनाना था।

सामान्य जनसंख्या में हैपेटाइटिस बी और सी के प्रसार लिए रक्त दाताओं में हैपेटाइटिस बी और सी की सीरो-रिएक्टीविटी अप्रत्यक्ष सूचक है। पिछले तीन वर्ष का डाटा निम्न प्रकार है:-

हरियाणा में वर्षवार रक्त दाताओं में हैपेटाइटिस बी तथा हैपेटाइटिस सी की सीरो-रिएक्टीविटी:-

सन्	हैपेटाइटिस बी की सीरो-रिएक्टीविटी (%)	हैपेटाइटिस सी की सीरो-रिएक्टीविटी (%)
2012-13	1.01	0.87
2013-14	0.87	0.87
2014-15	0.87	0.90
2015-16 (जनवरी 2016 तक)	0.87	0.81

इस डाटा से यह स्पष्ट होता है कि हैपेटाइटिस बी तथा हैपेटाइटिस सी की प्रसार दर रक्त दाताओ में जोकि सामान्य जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है पिछले तीन वर्ष से बढ़ नहीं रहा है।

हरियाणा के सभी ब्लड बैंक रक्त जारी करने से पहले रक्त यूनिट में हैपेटाइटिस बी तथा सी की जांच कर रहे हैं। एच०एस०बी०टी०सी० (हरियाणा स्टेट ब्लड ट्रांसफयूजन कांउसिल) लोगों को इस संक्रमण के बारे में जागरुक करने के लिए तथा डिस्पोजेबल सीरिंज, सूई और सुरक्षित यौन व्यवहार का उपयोग करने के लिए नियमित आई०ई०सी० गतिविधियां कर रहा है। प्रत्येक वर्ष डॉक्टरों, प्रयोगशाला, तकनीशियनों तथा स्टाफ नर्सों को रक्त सुरक्षा के मानकों के रखरखाव में प्रशिक्षित किया जाता है।

हरियाणा में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू०आई०पी० Universal Immunization Programme) के अंतर्गत हैपेटाईटिस-बी के संक्रमण से बचाव के लिए वर्ष 2011 से हैपेटाइटिस-बी टीकाकरण किया जा रहा है। हरियाणा, उत्तर भारत का प्रथम राज्य है, जहाँ पेंटावेलेंट (हैपेटाइटिस-बी युक्त) के टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में दिसंबर 2012 से शामिल किया गया, इस टीके की तीन डोज़ से शिशुओं को पांच बीमारियों (गलघोंटू, काली खांसी, टेटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाला न्यूमोनिया एवं दिमागी बुखार और हैपेटाइटिस-बी) से सुरक्षा मिलती है।

सार्वभौमिक टीकाकरण सारणी (यू०आई०पी०) के अनुसार हैपेटाइटिस-बी की "बर्थ डोज" प्रसव के 24 घंटे तक तथा पेंटावेलेंट की तीन टीके 6, 10 व 14 सप्ताह की उम्र पर लगाये जाते हैं। जिला स्वास्थ्य सूचना प्रणाली-2 (District Health Information System-2) के अनुसार अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 तक हैपेटाइटिस-बी बर्थ डोज की कवरेज 54.8 प्रतिशत तथा पेंटावेलेट (हैपेटाइटिस-बी युक्त) के पहले, दूसरे व तीसरे टीके की कवरेज, क्रमश: 91.8 प्रतिशत व 86.6 प्रतिशत है।

सभी स्वास्थ्य तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं (आशा व ऑगनवाड़ी) को हैपेटाइटिस-बी व पेंटावेलेंट का टीका लगाने तथा जन साधारण को टीकाकरण हेतू प्रेरित करने के लिए दिशा-निर्देश व ट्रेनिंग दी गई है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू०आई०पी०) के तहत ये वैक्सीन, सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कालेजों, बाहरी औषधालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों और टीकाकरण सत्रों में नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है।

[श्री अनिल विज]

राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 में विशेष टीकाकरण अभियान "मिशन इन्द्रधनुष" के दो चरण कराऐ गये हैं, जिसका उद्देश्य हाई रिस्क एरिया (ईंट भट्ठे, निर्माणधीन क्षेत्र, बाहरी स्लम, अल्प सेवित क्षेत्र इत्यादि) के दो वर्ष तक के उन सभी बच्चों को टीकाकरण सेवाऐं उपलब्ध कराना था जिनका टीकाकरण पहले कभी नहीं हुआ या आंशिक टीकाकरण हुआ था।

स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा हैपेटाइटिस सी के प्रबन्धन के लिए नीति तैयार की गई। इस नीति के अनुसार हैपेटाइटिस सी का उपचार हरियाणा डोमिसाइल के अनुसूचित जाति/बी०पी०एल० वर्ग के रोगियों को नि:शुल्क प्रदान की जाती है। पी०जी०आई०एम०एस० का गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, हैपेटाइटिस सी रोगियों के प्रबन्धन के लिए नोडल केन्द्र हैं और डॉ० प्रवीण मल्होत्रा विभागाध्यक्ष, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक के उपचार चिकित्सक हैं। अब तक हरियाणा में हैपेटाइटिस सी के 2070 अनुसूचित जाति/बी०पी०एल० वर्ग के रोगियों को नि:शुल्क योजना के तहत नामांकित किया गया है, इन में से लगभग 400 रोगियों का उपचार अभी चल रहा है। वर्तमान में सामान्य श्रेणी के लगभग 1200 रोगियों का इलाज रियायती दर पर नामांकित किया गया है, जिन में से 250 रोगियों का उपचार अभी चल रहा है। शुरू में इलाज इंजेक्शन पैग इंटरफेरॉन द्वारा किया जाता था। लेकिन मौखिक दवा संयोजन के प्रक्षेपण (oral drug combination) के साथ इलाज मौखिक दवा द्वारा जनवरी 2016 से शुरू किया गया जिससे पहले से हैपेटाटिस सी के उपचार की लागत में और कमी आई है।

हरियाणा सरकार, हरियाणा वासियों को सभी स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए विभाग सम्पूर्ण रुप से विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं पूरे प्रदेश में, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार स्थापित कर रहा है, ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसानी से पहुँच सकें।

प्रदेश में 58 नागरिक अस्पताल एवं उप मण्डल अस्पताल, 119 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 485 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 2630 उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जहाँ तक उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 20% व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 11% कमी की बात है यह भारतीय सरकार के मानदंडों जोकि जनसंख्या के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित करने की वजह से है।

हरियाणा एक छोटा राज्य है, इसलिए गावों से स्वास्थ्य केन्द्रों की दूरी, जिनमें आपातकालीन सेवाएँ, टीकाकरण व प्रसव आदि सेवाएं उपलब्ध हैं, कम हैं।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाले मुख्य कार्य, आसानी से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला अस्पतालों मे किए जा सकते हैं जोकि गाँव से लगभग 20-30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसके अलावा, हमारे पास बहुत ही मजबूत एंबुलैंस प्रणाली है। 375 एंबुलैंस दिन रात हैल्पलाइन न० 102 के अंर्तगत सेवाएं देती हैं।

यह भी बताना जरूरी है कि स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाना एक लगातार प्रक्रिया है। जब भी ग्राम पंचायत उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जमीन देने का प्रस्ताव देती हैं तो स्वास्थ्य विभाग भवन निर्माण व कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जरूरी कदम उठाती है। सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर रिहायिश के प्रबंध हैं।

चिकित्सकों के संबंध में बताना चाहता हूं कि चिकित्सकों के 3280 स्वीकृत पदों में से 480 पद खाली है। 270 चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर हैं।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 31 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। बहुत सारे आरक्षण मे आने वाले पद जैसे कि विकलांग, सेवानिवृत सैनिकों के पद खाली रह जाते हैं। 148 महिला डॉक्टर विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात हैं।

हरियाणा सरकार चिकित्सकों के सभी पद भरने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के लिए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया को हरियाणा जन सेवा आयोग से निकाल कर स्वास्थ्य विभाग को चयन व नियुक्ति के लिए जिम्मेवारी दी गई है।

कुछ समय पहले ही 389 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इनमें से कुछ ने ज्वाइन नहीं किया। इसलिए 111 चिकित्सकों को वेटिंग लिस्ट में से नियुक्ति पत्र दिए गए। चिकित्सकों के खाली पदों की कई और भी वजह है जैसे कि आरक्षित पद, विकलांगों, पूर्व सैनिकों की उपलब्धता न होना। कुछ चिकित्सक उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं पर आखिरकार यह भी जनहित की ही बात है।

आखिर में, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से सावधान है व कैंसर, हैपेटाइटिस बी व सी की रोकथाम व बचाव के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों में जागरुकता भी फैलाई जा रही है। बुनियादि ढांचे की कमी को पूरा करने व डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के वक्तव्य से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ और एक-दो सवाल आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल यह है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका अरली स्टेज पर पता नहीं चलता। आदमी अच्छा-भला दिखाई देता है लेकिन बाद में जब चैकअप करवाता है तो डॉक्टर बताता है कि आपको तो थर्ड स्टेज का कैंसर है। इसके ईलाज का एक तरीका यह भी है कि इसका पहले ही चैकअप करवा लिया जाये। अगर उसका समय पर चैकअप हो जाये और अरली स्टेज पर कैंसर डिटैक्ट हो जाये तो इसका इलाज सम्भव है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कैंसर की रोकथाम के लिए अभी तक हरियाणा में कोई चैकअप अभियान क्यों नहीं चलाया जा सका जिससे इस रोग की रोकथाम की जा सके। मेरा दूसरा सवाल यह है कि 13-2-2013 को पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक में प्रयास शुरू हुआ था, जो रेडियोलॉजी डिपार्टमैंट में रीजनल कैंसर सैन्टर है उसको अपग्रेड करने की बात हुई थी। उसको अपग्रेड करने के लिए एटॉमिक ऐनर्जी रेगूलेटरी बोर्ड की कुछ ऑब्जर्वेशन आई थी जिसमें बोर्ड ने यह कहा था कि considering the present work load in your faculty, the staff members in Radiology department are not adequate. यह स्टाफ पर्याप्त नहीं है। उसके ऐवज में वहाँ की फैकल्टी की मीटिंग हुई तथा उस फैकल्टी ने यह चिन्ता व्यक्त की कि यदि स्टाफ को पूरा नहीं किया गया तो एटॉमिक ऐनर्जी रेगूलेटरी बोर्ड इस सैन्टर को बंद भी कर सकता है। उसके उत्तर में अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा, स्वास्थ्य विभाग ने पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक को दिनांक 11-6-2015 को एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने भी स्टाफ की कमी के बारे में चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि हम स्टाफ की कमी को दूर

[प्रो. रविन्द्र बलियाला]

करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन इस प्रकार है : - Regional Cancer Centre is the only Cancer Centre of Haryana catering to the needs of cancer patients of Haryana State and Atomic Energy Regulatory Board may shut down this centre, if compliance is not done well-in-time. इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि 11-6-2015 का अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा, स्वास्थ्य विभाग का पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक को जो पत्र लिखा गया है उसकी कम्पलायंस हुई है या नहीं हुई है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला तो कैंसर की अरली डिटैक्शन के बारे में पूछा है कि अगर कैंसर का अरली डिटैक्शन हो जाये तो कैंसर के मरीजों को बचाया जा सकता है। Sir, it is very true हमारा भी यही प्रयास रहता है कि इसका अरली डिटैक्शन हो जाये और मरीज का पता लग जाये कि कैंसर शुरू हो गया है तो उसको क्योर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, उसके लिए अभी हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। मैं इस बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जा कर मिला था और मैंने उनको कहा था कि अगर वे हमें 10 वैल इक्विप्ड वैन जिसमें सारी लैबोरेट्री और मैमोग्राफी तथा अन्य सुविधाएं हों, दे दें तो मैं हरियाणा के एक-एक गांव में एक-एक घर में जा कर सबकी स्कैनिंग करवा लूँगा कि कौन पेशैन्ट है और कौन पेशैन्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अब एक नई टैक्नॉलोजी आई है जिसमें लिक्विड टैस्ट के माध्यम से कैंसर का पता लगाया जा सकता है। मैंने अपने विभाग को आदेश दिये हैं कि उसके बारे में स्टडी करें। अभी मीडिया चैनलों पर ही उसका प्रचार किया जा रहा है कि ब्लड टैस्ट करने से ही पता चल जाता है कि उक्त पेशैन्ट में कैंसर के सैल हैं या नहीं हैं। यह नई टैक्नॉलोजी है और अभी शायद यह हिन्दुस्तान में इन्ट्रोडयूस नहीं हुई है लेकिन फिर भी मैंने अपने विभाग को कहा है कि इसका पता लगायें। अध्यक्ष महोदय, अगर उसकी कॉस्ट हमारी पहुंच में होगी तो हम उसको खरीदने की कोशिश करेंगे ताकि एक-एक गांव के एक-एक घर में जा कर सबके एक बार टैस्ट किये जा सकें। हम जिन्दगियाँ बचाना चाहते हैं। मैंने उसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इस पर कितना खर्च आयेगा अभी इस बारे में नहीं बताया जा सकता है। दूसरी बात माननीय साथी ने पी.जी.आई. रोहतक के रीजनल कैंसर सैन्टर के बारे में पूछी है। अध्यक्ष महोदय, इनकी बात ठीक है कि जब तक एटोमिक ऐनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से परमिशन न मिल जाए तब तक यह काम हो नही सकता लेकिन हमने सारी औपचारिकताएं कम्पलीट करके केस उनको भेजा हुआ है तथा हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसकी परमिशन हमें मिल जाएगी और हम वहां पर कोबाल्ट सैंटर शुरू कर देंगे।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ऑब्जरवेशन दी है कि स्टाफ पूरा करो।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टाफ की बात है तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी हमने लगभग 1300 डॉक्टरों की सैंक्शन दी है। सर, हमारे प्रदेश में पिछली सरकार के समय में बड़े अजीब-अजीब काम हुए थे। पी.जी.आई. रोहतक में ट्रॉमा सैंटर बना दिया गया है जिसका उद्घाटन भी कर दिया गया लेकिन न तो कहीं पर इक्विपमैंट्स का प्रावधान किया गया और न कहीं पर मैन पॉवर का प्रावधान किया गया। मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वहां गया और मैंने वहां पर पट्टिका लगी हुई देखी कि इसका उद्घाटन हुए तीन साल

हो गये हैं तो हमें पता चला कि इसमें बाकी के कोई प्रावधान किये नहीं गये। अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई प्रोजैक्ट बनाया जाता है तो वह कम्पलीट बनाया जाता है कि सिविल वर्क कितना होगा, मैन पॉवर कितनी लगेगी, रनिंग कौस्ट क्या आएगी, इक्विपमैंट कौन-कौन से लगेंगे परंतु दुर्भाग्य से हमारी पूर्ववर्ती सरकार को खाली सिविल वर्कों में ही इन्ट्रस्ट था। अब ऐसा क्यों था ? उसको हम सभी समझ सकते है यहां सभी राजनीतिक लोग बैठे हैं। उसी प्रकार से जो जच्चा-बच्चा अस्पताल बने हुए हैं उनमें भी कोई प्रावधान नहीं किये गये। सर, मैंने डॉक्टरों की पोस्टें सैंक्शन कर दी हैं प्रक्रिया जारी है और यह जो हमारा ट्रॉमा सैंटर बना है इससे हमारी पी.जी.आई. को बहुत बड़ा लाभ होगा। वह बिल्डिंग बनकर बेकार खड़ी है। वह किसी काम नहीं आ रही है इसलिए हम इन सारी कमियों को दुरूस्त कर रहे हैं।

श्री हरिचन्द मिड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम पाकिस्तान से और पंजाब से लुटकर आए थे और यहां हरियाणा में आने के बाद हमने दिन रात मेहनत की है जिसका फल हमें मिला है। हमारे परिवारों ने हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत से हमें आज यहां तक ला कर खड़ा किया है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आज भी कितने प्रतिशत लोग ऐसे है जो भूखे सोते हैं जिनको रोटी नहीं मिलती। मैं यह चाहता हूं कि आज आपके राज में ऐसा न हो। मैं मिसाल के तौर पर एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार राजा कर्ण भ्रमण पर गये हुए थे। एक बच्चे ने एक छोटा-सा पत्थर फैंका और वह पत्थर कुदरती राजा को लग गया तो राजा ने बच्चे को बुलाया जिसको लेने के लिए मंत्री दौड़कर गये और उस बच्चे को पकड़कर राजा के पास ले आये तो राजा ने उस बच्चे को अपने पास बिठाया और कहा क्या बात है बेटा आपने यह पत्थर मुझे क्यों मारा ? वह बच्चा कहने लगा कि मैं और मेरी माँ तीन दिन से भूखे हैं इसलिए मैंने बेर को तोड़ने के लिए इस पत्थर को फैंका था लेकिन मैंने आपको नहीं देखा था तो राजा ने उस बच्चे को बिठाया और उसको खाना खिलाया और उससे पूछा कि तुम्हारी माँ कहां है? उसने कहा कि वह घर पर है मैं उनके लिए कुछ बेर लेकर जाऊंगा जिससे हम दोनों अपनी भूख मिटाएंगे। तब राजा ने मंत्रियों को कहा कि कल दरबार है और वह दोनों माँ-बेटा वहां पर आए। मंत्री उन दोनों माँ-बेटे को दरबार में लेकर आए तो राजा ने दरबार में घोषणा की कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं सारी प्रजा का और इन दोनों माँ-बेटे का पूरा ख्याल रखूंगा। इन्हीं बातों से हम यह उम्मीदें रखते हैं कि जीन्द हल्के की तरफ जोकि एक गरीब हल्का है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, ध्यान दिया जाए। अगर आपको बताएं कि कभी जीन्द का दिल था लेकिन आज जीन्द का दिल मुरझा गया है तो हमें सरकार से उम्मीद है कि हमें मुरझाने न दें। हम आपसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं इसलिए हमारा भी ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।

श्री नगेन्द्र भडाना : अध्यक्ष महोदय, आज कैंसर की बीमारी एक महामारी के रूप में फैल रही है जिसको मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। फरीदाबाद जिले में मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र में जिसमें पाली, धोत और उसके आस पास के गांव आते हैं जिनमें कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। अभी हाल के दिनों में नव भारत टाईम्स में एक लेख आया था जिसमें इसका विस्तृत ब्योरा आया था। पाली मोहतावाद में क्रेसर जोन लगा हुआ है जोकि सरकारी नॉर्म्स को पूरा नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है और चारों तरफ महामारियां फैल रही हैं वहां पर टी.बी. की बीमारी के भी बहुत ज्यादा पेसेंट आ रहे हैं। तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा वहां पर जो पेशैंट की संख्या दिनों

[श्री नगेन्द्र भडाना]

दिन बढ़ती जा रही है उनके ईलाज के लिए, विशेषकर उस जोन के लिए कोई विशेष दल बनाकर वहां पर जांच की जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि फरीदाबाद जिले में पोल्यूशन का स्तर कितना है? जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से फरीदाबाद जिला पोल्यूशन के मामले में पूरे हिन्दुस्तान में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नगेन्द्र जी, आप पोल्यूशन पर कैसे बोलने लग गये हैं? आपने ध्यानाकर्षण सूचना तो हैपेटाईटिस बी-सी और कैंसर के विषय पर दी है और आप उस सब्जैक्ट से हटकर पोल्यूशन के सब्जैक्ट पर बोलने लग गये हो। (विघ्न)

श्री नगेन्द्र भडाना : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सब्जैक्ट पर ही आ रहा हूँ लेकिन क्योंकि आज सभी बीमारियों की जड़ पोल्यूशन है, उसकी वजह से पहले मैं पोल्यूशन के बारे में बता रहा था। अध्यक्ष महोदय, जल प्रदूषण के कारण हैपेटाइटिस बी तथा सी आदि जल जनित बीमारियां जो फैल रहीं हैं उनका मेन कारण पोल्यूशन है। पोल्यूशन के कारण ही कैंसर जैसी धातक बीमारियां भी फैलने लग गई हैं। अत: इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि फरीदाबाद जिले में पोल्यूशन का जो स्तर है वह वास्तव में कितना है और सरकारी स्तर पर इस पोल्यूशन को कम करने के लिए तथा नियंत्रण में करने के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं और सरकार के द्वारा इस दिशा में क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपने गांव में चिकित्सकों का दल भेजने की बात कही है, उसके संबंध में मैं माननीय सदस्य को पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चिकित्सकों का दल उनके गांव में भेज दिया जायेगा और सबका पूरी तरह से चैक अप किया जायेगा और जो बीमारियां होंगी उनका ट्रीटमैंट वहां के नजदीक लगते स्वास्थ्य केन्द्र में होगा। जहां तक फरीदाबाद के पोल्यूशन के बारे में माननीय सदस्य ने बात की है तो उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि पोल्यूशन दूसरे विभाग का मसला है। मैं यह भी भलीभांति मानता हूँ कि पोल्यूशन से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। फरीदाबाद में पोल्यूशन का स्तर क्या है इसके बारे में पोल्यशून विभाग के पास आंकड़े जरूर होंगे। अध्यक्ष महोदय, हम पूरी तरह सीरियस हैं और लेटस्ट जितने भी अध्ययन हमारे पास आये हैं उन अध्ययनों के मुताबिक तम्बाकू की वजह से कैंसर सबसे ज्यादा फैलता है। हमने अपने प्रदेश में शायद सितम्बर के महीने में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि सभी प्रकार का जो च्युऐबल तम्बाकू है, जो पैकटों में बिकता है या फलेवर्ड है या फिर किसी भी फोर्म में है उस सारे तम्बाकू पर प्रतिबंध लगा दिया जाये। परन्तु यह तम्बाकू लॉबी भी बहुत मजबूत है उन्होंने कांग्रेस के लीडर व वकील श्री अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से हाई कोर्ट में केस लगवा दिया और सिंघवी साहब ने उनके केस की पैरवी की और हमारी नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया गया। हमने उस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और फिर हमने दोबारा से प्रदेश में आदेश जारी कर दिये कि हरियाणा प्रदेश में कहीं पर च्युऐबल तम्बाकू नहीं बेचा जा सकेगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीते हमने आदेश जारी कर दिये कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से च्युऐबल तम्बाकू का वितरण नहीं किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जो हुक्का बार होते

हैं वहां पर निकोटिन का प्रयोग किया जाता है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा हमने निकोटिन को जहर की श्रेणी में डाल दिया है और इस तरह से आज कोई निकोटिन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके साथ और भी कदम उठाये जा रहे हैं जिसके जल्दी ही नतीजे सामने आयेंगे। इस प्रकार की घातक बीमारियों को रोकने के लिए my Government is very serious. इसके साथ ही मैं हैपेटाईटिस-सी के बारे में भी बताना चाहूँगा। यद्यपि माननीय सदस्य ने इसके बारे में नहीं पूछा है। हैपेटाईटिस-सी के ईलाज के लिए लोगों को पी.जी.आई. के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन हम इस बीमारी के निवारण के लिए मुफ्त दवाईयां उपलब्ध करवाते हैं। पहले इस बीमारी से संबंधित इंजेक्शन चार हजार रूपये का आता था लेकिन अब हाल ही में इसके लिए एक टेबलेट आई है अध्यक्ष महोदय, हैपेटाइटिस-सी के रोगी रतिया, फतेहाबाद बैल्ट में ज्यादा हैं। जिन्हें अपना ईलाज करवाने के लिए रोहतक जाना पड़ता है। हम विचार कर रहे हैं कि उन्हें 15 दिन या एक महीने की इकट्ठी टेबलेट मिल जाये ताकि उन्हें बार-बार आना-जाना ना पड़े। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि यह टेबलेट वहीं के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो, इसके लिए हम सर्वे करवा कर रिपोर्ट मंगवा रहे हैं ताकि सस्ता और बढ़िया ईलाज हो सके। अध्यक्ष महोदय, टेबलेट तो हम दे देंगे लेकिन इस बीमारी का ईलाज गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की देखरेख में ही होता है।

श्री बलकौर सिंह कालांवाली : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कैंसर और हैपेटाइटिस-बी,सी जिन दो बीमारियों का सदन में जिक्र हो रहा है, यें ऐसी बीमारियां हैं जिनसे मरीज को तो अपनी जान का खतरा होता ही है साथ में उनके परिवार वालों पर मुसीबतों पहाड़ टूट पड़ता है। महंगे ईलाज के कारण लोग सड़क पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मंत्री महोदय ने बड़े ही विस्तार से इन बीमारियों का जिक्र सदन में किया है। इन बीमारियों के ईलाज में बहुत सुधार की जरूरत है। खासकर सिरसा जिले के डबवाली और कालांवाली में इन बीमारियों के मरिजों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी डॉक्टरों की कोई टीम जांच करने के लिए नहीं आती है। सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि इन अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी तो है ही साथ में लैबोरेट्री और एक्सरे मशीन को चलाने वाला अटैंडेंट भी नहीं है। लोगों को मैडिसन और वैक्सीन का तो पता ही नहीं कहां और कैसे मिलेगी ? इसलिए वहां प्रचार-प्रसार की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्कृष्ट चिकित्सकों के नेतृत्व में गठित जांच टीमों को भेजा जाए ताकि वे इन बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक कर सके। स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ पब्लिक हैल्थ की भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है। हम देखते हैं कि शहरों में सीवरेज सिस्टम बहुत खराब है। कहीं पर सीवरेज ओवर फ्लो हैं और कहीं पर सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिल जाता है। जिसके कारण ये बीमारियों पैदा होती है। पिछले सत्र में इस बारे में प्रश्न लगाने के बाद सफाई तो हुई मगर आज फिर वही हालात पैदा हो गए हैं। पीने के पानी की समस्या बढ़ गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इन दो विभागों को आपस में मिलकर ऐसा कदम उठाना चाहिए ताकि इन बीमारियों के आने से पहले ही रोकथाम हो जाये। माननीय मंत्री महोदय ने जिस मैडिसन का जिक्र सदन में किया है, वह सिरसा के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाये ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि जितनी चिंता उन्हें है उतनी ही चिंता सरकार को भी है। इस बारे में सरकार ने पी.जी.आई., रोहतक और पी.जी.आई., चण्डीगढ़ से सर्वे भी करवाया हुआ है। जहां तक इस टेबलेट का सवाल है यह हमने जनवरी, 2016 से ही शुरू की है। धीरे-धीरे हम इस प्रोसैस को आगे बढ़ायेंगे ताकि हर मरीज को यह दवाई मिल सके। हमारे पास इस बीमारी से संबंधित सभी मरीजों का ब्यौरा है। बीपीएल परिवार के लोगों को यह दवाई पहले से ही फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है।

श्री केहर सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक एवं गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आज हरियाणा प्रदेश में कैंसर एवं हेपेटाइटिस बी और सी बीमारियां महामारी का रूप ले चुकी हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, आपके पास जो लिखित कागज है आप उसे पढ़ने की बजाय सदन की मेज पर रख दें। इसे सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाएगा। (विघ्न)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं अपने इस लिखित कागज को पढ़ने के साथ प्रश्न भी पूछूंगा इसलिए मुझे इसे पढ़ने की इजाजत दीजिए। अध्यक्ष जी, रोजाना सैकड़ों लोग कैंसर व हेपेटाइटस बी और सी के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं और हजारों व्यक्ति इन बीमारियों के मरीज होते जा रहे हैं। जब किसी भी परिवार में कैंसर व हेपेटाइटस बी और सी से ग्रस्त व्यक्ति का पता चलता हे तो उस व्यक्ति या उसके परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। इन बीमारियों का नाम सुनते ही उस बीमार व्यक्ति को अपने सामने मौत दिखाई देने लगती है। इन दोनों बीमारियों का ईलाज बहुत महंगा है। सामान्य परिवारों को इन दोनों बीमारियों का ईलाज करवाने के लिए मकान, जमीन तथा बर्तन तक बेचने पड़ रहे हैं। अब तक हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे इन दोनों बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को तथा परिवारों को राहत मिल सके। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, आप हाउस में प्रश्न पूछिये। इस तरह से लिखित कागज न पढ़ें (विघ्न)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं सदन को वह बात बता रहा हूं जिसका अब तक सदन में किसी ने जिक्र नहीं किया है। हरियाणा सरकार व स्वास्थ्य विभाग कैंसर व हेपेटाइटिस बी और सी जैसी भयानक बीमारियों के फैलने के कारणों का पता भी नहीं लगा पाई है ईलाज तो बहुत दूर की बात है। बीते वर्ष हल्का होडल के गांव बांसवा में कैंसर के कारण 16 लोगों की मौतें हुई और दर्जनों व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर से मरने वाले एक ही गांव के लोगों के नाम इस प्रकार हैं :- सुरेश, नैना, सुनीता, नरेश, राधा, यमुना, पप्पन, चतरसिंह, राजवीर, धनराज, गोपाल का दो वर्षीय पुत्र तथा मल्ली आदि कैंसर से ग्रस्त होकर मर चुके हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री केहर सिंह जी, आप टू दि प्वायंट बात कीजिए। (विघ्न)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष जी, जिले के गांव बांसवा के लोगों पर कैंसर काल बनकर घूम रहा है। कैंसर रोग से पिछले एक साल में अब तक 16 लोग अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं। यह जानलेवा रोग क्यों फैल रहा है, ये अभी स्वास्थ्य विभाग के लिए भी पहेली बना हुआ है। यह सिर्फ एक ही गांव की समस्या नहीं है। वहां पर आए दिन कैंसर पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्री केहर सिंह जी, आप इसे टू दि प्वायंट बताकर खत्म कीजिए। इसे सदन की कार्यवाही में शामिल कर लिया जाए। इस तरह से सारे लिखित कागज को सदन में पढ़ना उचित नहीं है। (विघ्न)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं एक बार पूरी बात सदन को बता दूं तो फिर मंत्री जी अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गया हूं। (विघ्न)

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष जी, जब तक मैं पूरी बात नहीं बता देता तब तक मंत्री जी सही ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे पूरी बात कहने की इजाजत दी जाए। पलवल जिले में कैंसर की वजह से हजारों मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली तथा नोएडा की फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल के माध्यम से फरीदाबाद और पलवल के गांवों में जाता है और उससे फल-सब्जियां पैदा होती हैं और जमीन में पानी रिचार्ज होता है। इन दोनों माध्यमों से यहां बीमारियां फैल रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस बी तथा सी जैसी घातक बीमारी के फैलने के कारणों का पता लगाने तथा इनको रोकने के कौन-कौन से ठोस कदम उठाए हैं। मैंने सवा साल पहले भी इसके बारे में बताया था परंतु विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। इस बीमारी की वजह पता करने के लिए आज तक विभाग का कोई भी आदमी पलवल में नहीं गया है। रोहतक पी.जी.आई. में डॉ. प्रवीण मेहता एक सुलझे हुए डॉक्टर हैं। आप कृपा कर ऐसे डॉक्टर्स की टीम को जिलावाइज भेजें ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को इस बीमारी से निजात मिल सके और वहां के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमें बताएं कि उन्होंने कैंसर और हेपेटाइटिस बी तथा सी जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

12 :00 बजे **श्री अनिल विज** : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी मैम्बर्ज की इस धारणा को दुरूस्त करना चाहता हूं कि हैपेटाइटिस-सी. गंदे पानी की वजह से होता है। हैपेटाइटिस-सी कभी भी गंदे पानी या खराब भोजन से नहीं फैलता। पहले भी कई साथियों ने कहा है कि गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। यह बात ठीक है कि गंदे पानी की वजह से और बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। हैपेटाइटिस-सी तभी फैलता है जब एक संक्रामक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति के खून के संपर्क में आता है चाहे वह नीडल से हो या किसी और प्रकार से हो। गंदे पानी से हैपेटाइटिस सी. हो जाए ऐसा मैडीकल साइंस नहीं मानती और इसका कोई आधार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बात बार बार आती है कि घग्गर नदी का पानी शहर में आ गया और उससे हैपेटाइटिस सी. हो गया इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। जहां तक माननीय साथी ने अपने गांव की बात की तो मैं इनको बताना चाहूगा कि मैंने भी समाचार पत्र में पढ़ा था कि उस क्षेत्र में इतने कैंसर के पेशियंट्स हो गए हैं। मैने उसी दिन हैल्थ डिपार्टमैंट की एक टीम वहां भेज दी थी। वह टीम वहां गई थी और उसने वहां जाकर देखा था। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी को भी मालूम है कि टीम वहां गई थी। अगर ये पूरी तरह से सैटिसफाइड नहीं हैं तो जैसा इन्होंने सजैस्ट किया है कि पी.जी.आई., रोहतक से एक टीम वहां भेजी जाए तो हम रोहतक पी.जी.आई. से एक टीम वहां भेज देंगे और चैकिंग करवा देंगे।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज 15 पर गुटका, पान मसाला और तम्बाकू पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है लेकिन हमारे यहां हर दुकान पर यह गुटका और पान मसाला पूरी तरह से बिक रहा है इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि एक दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के इस बारे आडर्ज आए हैं। मैंने उसी वक्त विभाग की टीम को भेजा और कहा कि कहीं भी तम्बाकू बिकता नजर नहीं आना चाहिए। मैंने विभाग में कहा है कि यदि मैने घूमते हुए कहीं किसी के एरिया में तम्बाकू बिकते हुए देख लिया तो उसकी खैर नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के आडर्ज आते ही आदेश जारी कर दिए थे।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को बता रहा था कि प्रदूषित जल की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां फैलती हैं लेकिन ये बात हैपेटाइटिस बी. और सी. की तरफ ले गए। हमारे यहां प्रदूषित पानी आ रहा है इसलिए वहां ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाना बहुत जरूरी है। सरकार की जिम्मेवारी है कि सबका स्वास्थ्य ठीक हो। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। गंदे पानी की समस्या केवल पलवल, मेवात, फरीदाबाद और गुडगांव की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की है।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब माननीय संसदीय कार्यमंत्री हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

शिक्षा मंत्री(श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं-

> "कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 17 मार्च, 2016 को सरकारी कार्य किया जाए।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

> "कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 17 मार्च, 2016 को सरकारी कार्य किया जाए।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

> "कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 30 को निलम्बित किया जाए तथा वीरवार, 17 मार्च, 2016 को सरकारी कार्य किया जाए।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

एस.वाई.एल. नहर के सम्बन्ध में श्री अरविन्द केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा दिये गये वक्तव्य का मामला उठाना।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर, ओमप्रकाश धनखड़ जी और सुभाष बराला जी यहां बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करना चाहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने एस.वाई.एल. नहर के बारे में कह दिया है कि यह नहर नहीं बननी चाहिए। कल ही इस विधानसभा में एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर एक निंदा प्रस्ताव पास किया गया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री का ब्यान आ रहा है कि एस.वाई.एल. नहर नहीं बननी चाहिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा कि मुनक नहर का पानी जो दिल्ली को जाता है उसको रोक दिया जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली को क्या अधिकार है कि वह एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में ऐसा बोल दे कि यह नहर नहीं बननी चाहिए।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय साथी परमिन्द्र सिंह ढुल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि केजरीवाल जी का जो ब्यान आया है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एस.वाई.एल. नहर का पानी हरियाणा को नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। क्योंकि 1979 में बी.बी.एम.बी. की 85वीं मीटिंग में दिल्ली के लिए दो लाख एकड़ फीट पानी आबंटित हुआ था। उस पानी को हम भाखड़ा मेन लाईन के माध्यम से लेकर आते हैं। इस तरह से 371 क्यूसिक पानी तो वही है और 125 क्यूसिक पानी सर्वोच्य न्यायलय के आदेश से और जोड़ दिया गया था। इस तरह से 496 क्यूसिक पानी भाखड़ा मेन लाईन से हम दिल्ली का लेकर आते हैं और उसके बाद मुनक हैड पर पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त 330 क्यूसिक पानी यमुना का हम वैस्टर्न यमुना कैनाल के थ्रू दिल्ली का पानी माणक पर पहुंचाते हैं । आगे सी.एल.सी. और दिल्ली ब्रांच भी हमारे एरिया में हैं जहां हम 826 क्यूसिक पानी देते हैं जिसमें से 719 क्यूसिक पानी दिल्ली में पहुंचता है जिससे दिल्ली की प्यास बुझती है। इसलिए मैं कहता हूं कि केजरीवाल जी का बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि हमें भी पानी का हिस्सा नंगल पर मिला हुआ है और हमें कैरियर चाहिए था। हम दिल्ली के लिए कैरियर का काम करते हैं। इसलिए केजरीवाल जी को देखना चाहिए कि उनको पंजाब का हित देखना है या दिल्ली का हित देखना है। अगर केजरीवाल जी पंजाब का पक्ष लेते हैं तो दिल्ली के लोग केजरीवाल के बारे में तय करें कि दिल्ली को पानी चाहिए या नहीं चाहिए। आरक्षण के दौरान तीन दिन खुबड़ु हैड पर पानी न पहुंचने के कारण दिल्ली में पानी की बहुत समस्या हो गई थी। इस तरह से केजरीवाल जी का बयान बिल्कुल हरियाणा के हितों के खिलाफ है, इस देश के संविधान की मर्यादा के खिलाफ है। सर्वोच्य न्यायलय के निर्णय के खिलाफ है और अंतर्राजीय समझौतों के खिलाफ है। इसलिए मैं सदन से निवेदन करता हूं कि केजरीवाल के बयान की एकमत से निंदा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया : यदि हाऊस की सहमति हो तो एक निंदा प्रस्ताव श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली द्वारा एस.वाई.एल. कैनाल के पानी को हरियाणा को न दिए जाने संबंधी उनके बयान के विरूद्ध पास किया जाये।

आवाजें : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदया : सदन सर्वसम्मति से इस बारे में प्रस्ताव पास करता है।
(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ होगी।

श्री जयप्रकाश (कलायत) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 14 मार्च, 2016 को सरकार का डाक्यूमैंट्री विजन इस महान सदन के सामने रखा। मैं इस अभिभाषण की कुछ बातों के बारे में सरकार से पूछना चाहूंगा। पिछले दिनों गुडगांव में ग्लोबल इन्वैस्टमैंट समिट का आयोजन किया गया और उसमें तरह तरह की बातें की गई। सरकार की ओर से कहा गया कि लाखों करोड़ों रूपये का इन्वैस्टमैंट बाहर से हरियाणा में आएगा। यह अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा बाहर से इन्वैस्टमैंट आए ताकि बेरोजगार जवानों को रोजगार मिल सके। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई।)** उपाध्यक्ष महोदया, इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि आप भी उस इलाके से संबंध रखती हैं वहां बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनमें क्षेत्रीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता बल्कि बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों गुड़गांव में चाहे मारूति उद्योग हो, चाहे हीरो होंडा हो उनमें हमारे प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे आई.टी.आई., पोली टैकनिक पढ़े हुए बच्चे जब इन कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां कहा जाता है कि कैथल, हिसार, और जींद के बच्चों को रोजगार नहीं दिया जायेगा। इन जिलों की वहां रोजगार में इंटरी नहीं है। इस तरह की रवायत वहां डली हुई है इसे खत्म किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, जमीन हमारी, बिजली हमारी, पानी हमारा और सड़क हमारी उसके बाद रोजगार दूसरे राज्यों के बच्चों को दिया जाता है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि जो हमारे युवा क्वालीफिकेशन पूरी करते हों उन्हें उन कंप्नीज में रोजगार मिले। यह अच्छा काम है। यदि हमारे राज्य के युवक क्वालीफिकेशन पूरी न करते हों तो वे बाहर के युवकों को रख सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, दूसरा सरकार ने अभिभाषण में लिखा है कि हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिलकर चल रहे हैं। यह अच्छी बात है कि सरकार किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले क्योंकि भारत वर्ष में 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं। जो उद्योग हैं वे भी खेती पर निर्भर करते हैं। हमारे कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। सफेद मक्खी से जो किसानों की फसल को नुक्सान हुआ है उसको लेकर इन्होंने मुआवजे की घोषणा की थी लेकिन इन्होंने हमारे साथ कंधा नहीं मिलाया या तो हमारे कंधे में कोई गड़बड़ी है क्योंकि सफेद मक्खी के कारण कलायत हल्के के किसानों की फसल भी 80 से 100 प्रतिशत तक खराब हुई है लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया गया। कैथल जिले में कलायत हल्के में कपास सबसे ज्यादा बोई जाती है। वहां की गिरदावरी भी की गई है। आपके ए.सी.एस. और चीफ सक्रेटरी साहब यहां बैठे होंगे इनसे आप जानकारी ले सकते हैं कि वहां पर 80 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत का नुक्सान हुआ है लेकिन कलायत विधान सभा को मुआवजे से वंचित किया गया है। लोगों के मन में जो यह अविश्वास की भावना है उसको पूरे

प्रयास करके दूर किया जाये। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में कलायत को ही शामिल न किया जाये बल्कि कलायत के साथ-साथ प्रदेश का जो भी हिस्सा व्हाईट फ्लाई के प्रकोप से पीड़ित है उसको भी इसमें शामिल किया जाये। इसके अतिरिक्त मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक निवदेन यह भी है कि जैसे आपने हाऊस में एस.वाई.एल. नहर का निंदा प्रस्ताव पास करवाया है इसी प्रकार का प्रस्ताव इस हाऊस में वर्ष 2004 में भी पास करवाया गया था। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के 9 सांसद थे जिनमें चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, मैं स्वयं और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री किशन सिंह सांगवान थे। जब श्री अमरेन्द्र सिंह जी ने सारे मुआवज़ों को टर्न-डाऊन कर दिया था तो चौटाला साहब हम सभी सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी से मिले थे क्योंकि यहां हरियाणा प्रदेश में लोकदल और भाजपा की सरकार थी, पंजाब और केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो हम सभी को आज ही प्रधानमंत्री जी से मिलने जाना चाहिए था क्योंकि आज लोकसभा का शायद वर्तमान सत्र का अंतिम दिन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि हमारे जो सभी सांसद हैं वे चाहे किसी भी दल के हों आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को उन सभी को साथ ले जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए था कि जो पंजाब सरकार ने पिछले दिनों किया है यह एक जघन्य और निन्दित काम है। आज अखबारों में यह समाचार भी छपा है कि वे आपको चैक देने जा रहे हैं। इसके लिए पंजाब सरकार के खिलाफ जो केन्द्र के स्तर पर कार्रवाही बनती है उसको अविलम्ब किया जाये। हम आपके साथ खड़े हैं और हम यह चाहते हैं कि पंजाब सरकार का वह चैक उनको वापिस करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम सभी को तत्काल माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से मिलकर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करनी चाहिए। ऐसे ही हमें इस काम के लिए भारत सरकार के ऊपर भी दबाव डालना चाहिए। इसी प्रकार से मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के बारे में कहना चाहता हूं कि उनकी आम आदमी पार्टी का पंजाब से क्या लेना देना ? ये वही केजरीवाल हैं जो 15-20 दिन पहले यह रोना रो रहे थे कि पानी के अभाव में दिल्ली प्यासी मर गई इसलिए भारत सरकार को इंटरवीन करके दिल्ली को हरियाणा से पानी दिलवाया जाये। आज यही केजरीवाल साहब पंजाब में जाकर हरियाणा के खिलाफ जहर का बीज बो रहे हैं। उन्होंने जो यह काम किया है इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। यहां पर केजरीवाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया यह बहुत अच्छा काम है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारत के संघीय ढांचे के ऊपर बार-बार प्रहार हो रहे हैं अगर ये प्रहार इसी प्रकार से होते रहे और भारतीय संघीय ढांचे को इनसे नहीं बचाया गया और अगर आने वाले समय में भारत सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी तो उसका राज्य सरकारों पर कोई नियंत्रण नहीं रह जायेगा और ये राज्य सरकारें निरंकुश बन जायेंगी जिससे आने वाले समय में भारत के भी उसी प्रकार से छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे जिस प्रकार से रूस के 16 टुकड़े हो गये थे। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे संघीय ढांचे की रक्षा करना हम सभी का बराबर दायित्व है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों और सभी विधायकों को साथ लेकर माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार से मिलकर

[श्री जय प्रकाश]

इन दोनों मुद्दों को उठायें और इनका समाधान करवायें। इस मामले में हम सभी आपका भरपूर साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

श्री महीपाल ढांडा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री जय प्रकाश जी को यह बताना चाहूंगा कि कल लोकसभा में इस मामले को हमारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश से केन्द्रीय मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और श्री वीरेन्द्र सिंह जी ने लोकसभा में उठाया था। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, जो बात श्री महीपाल जी ने बताई यह अच्छी बात है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हमें इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, से मिलना चाहिए। हम सभी को इस मामले में आपस में नहीं उलझना चाहिए बल्कि जो प्रदेश के हित में है वह काम जल्दी से जल्दी और बिना किसी देरी के करना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की जनता ने हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री को सौंपी है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़ें और इस मामले को पूरी तैयारी के साथ केन्द्र सरकार के साथ उठायें। जहां तक हमारी बात है हम हरियाणा प्रदेश के हितों की किसी भी लड़ाई में पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। जब इस विषय पर सारा विपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी को साथ लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने इस विषय को उठाना चाहिए। मेरे विचार से जो एस.वाई.एल. नहर का मामला है वह इसीलिए ज्यादा बिगड़ा हुआ है क्योंकि इस विषय पर हम आपस में ही ज्यादा उलझ जाते हैं। जबकि होना तो यह चाहिए कि इस मुद्दे पर हम सभी को एकमत होना चाहिए और हमें एकजुट होकर हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए लड़ना चाहिए। मैं बार-बार यह बात दोहरा रहा हूं कि हम सभी को एक साथ जाकर माननीय प्रधानमंत्री से इस विषय पर बात करनी चाहिए। तीसरी बात है शिक्षा की। शिक्षा की जो बात की गई और पिछले काफी समय से हम देख भी रहे हैं कि वर्तमान सरकार "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" का जो संकल्प है मैं समझता हूं कि यह संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब पूरे हरियाणा प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थान खोले जायेंगे। हमारे हरियाणा प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं और सब-डिविजन्स भी ऐसी हैं जहां की लड़कियां को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20-20 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, पिछले सत्र में मैंने यहां पर कलायत में कन्या महाविद्यालय खोलने की बात कही थी। मैंने पिछले सैशन में यहां पर यह कहा था कि प्रदेश में बहुत सी ऐसी जगहों पर कन्या महाविद्यालय खोल दिये गये हैं जहां पर निर्धारित नॉर्म्ज़ भी पूरे नहीं होते। हम कलायत में कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार को बार-बार रिकवैस्ट करते रहे और बार-बार एप्लीकेशन देते रहे लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कन्या महाविद्यालय नहीं खोला गया। इस काम के लिए कलायत और राजौंद में कपिल मुनि एजुकेशन सोसायटी ने ज़मीन भी दी है और साथ में बिल्डिंग भी दी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार का "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान तभी आगे बढ़ेगा और तभी सार्थक होगा, जब चाहे वह कलायत हो, राजौंद हो या हरियाणा प्रदेश का अंतिम छौर हो अर्थात रोहतक से लेकर कालका तक ज्यादा से ज्यादा महिला कॉलेज खोले जायें और सरकार की तरफ से इसी सत्र में

इस प्रकार की घोषणाएं हों, इससे महिलाएं शिक्षित होंगी। आज जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में शिक्षा का अभाव है, इसलिए इस तरह के जघन्य कांड हो रहे हैं उनसे बचने के लिए नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा नारी शिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिएं, चाहे वह कलायत हो, चाहे राजौंद हो। उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार से आज स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में हैपेटाईटिस बी, सी और कैंसर पर अपना जवाब दिया गया है मैं उससे संतुष्ट हूँ। इसमें एक बीमारी का नाम और जोड़ा जाना चाहिए था। आज हरियाणा में सबसे ज्यादा बीमारी हार्ट फेल की है। हार्ट अटैक से तो आदमी बच सकता है लेकिन हार्ट फेल होने से आदमी तुरन्त मर जाता है। आज इस प्रकार के केसिज गांव में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसलिए कार्डियोलॉजिस्ट का इंतजाम भी हर जिला स्तर पर किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर हर्ट प्रॉब्लम होने पर प्राथमिक उपचार मिल सके। आज अगर हरियाणा के बीच के इलाके में किसी को हर्ट प्रॉब्लम हो जाती है तो या तो रोहतक या चण्डीगढ़ या पटियाला जाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा एक निवेदन है कि जिस प्रकार से हैपेटाईटिस बी, हेपेटाईटिस सी और कैंसर के उपचार की बात की जा रही है उसी प्रकार से हर्ट फेल के लिए कार्डियोलॉजिस्ट का इंतजाम भी किया जाये। अपने जवाब में मंत्री जी ने एक बात और कही है कि हम बी.पी.एल. के लोगों का हैपेटाईटिस बी और हैपेटाईटिस सी का फ्री ईलाज करते हैं तो उपाध्यक्ष महोदया, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि बीमारी कभी यह नहीं देखती कि कौन बी.पी.एल. का है और कौन ए.पी.एल. का है। आज गांवों में भी और शहर में स्लम बस्ती में बसने वाले सभी लोगों की आर्थिक हालत कमजोर है। आज हम बात तो अमेरिका और इंग्लैंड की करते हैं लेकिन वहाँ पर तो सभी के लिए फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए इन चार बीमारियों (हैपेटाईटिस-बी, हैपेटाईटिस-सी, कैंसर और हर्ट फेल) का ईलाज प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए फ्री होगा तो यह बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए मेरे हिसाब से अगर चिकित्सा, शिक्षा, कृषि और पानी के लिए अधिक बजट का प्रावधान किया जाये तो राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के में एक सौंगल गांव है और वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर भी उपलब्ध हैं लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग नहीं है। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ पर तो डॉक्टर नहीं हैं और जहाँ डॉक्टर हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है। सौंगल गांव की डिस्पैन्सरी 20 वर्ष पहले बनी थी और अब वह जर्जर हालत में है इसलिए या तो उसकी नई बिल्डिंग बनाई जाये या उसकी अच्छी तरह से रैनोवेशन की जाये। इसी प्रकार से मेरे हल्के में 30-30 किलोमीटर तक पी.एच.सी. या सी.एच.सी. नहीं हैं जिससे महिलाओं की डिलिवरी के समय जच्चा-बच्चा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस काम के लिए सरकार ने जो फ्री एम्बूलेंस दी हैं वे भी इसमें ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पा रही क्योंकि 30-30 किलोमीटर तक कोई स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र नहीं है। इसलिए जहाँ भी जरूरी हो वहाँ पर पी.एच.सीज. ज्यादा खोली जायें। मेरे हल्के में कुराड़ गांव है जहाँ पर नजदीक कोई भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र नहीं है यहाँ तक कि डिस्पैन्सरीज भी नहीं हैं। अगर वे बना दी जायें तो जनता को उसका लाभ होगा। रही बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की तो इस पर सम्पूर्ण बहस तो तब होगी जब आप बजट लेकर आयेंगे ताकि पता चल सके कि आप किस विभाग के लिए कितना बजट लेकर आये हैं। आज के दिन टैक्नीकल ऐजूकेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सरकार से बार-बार रिक्वैस्ट कर चुके हैं कि कैथल जिले के जाखौली गांव के लोगों ने जमीन सरकार को दी है। वे लोग कहते हैं कि चाहे जितनी भी जमीन ले लो लेकिन हमारे गांव में

[श्री जय प्रकाश]

आई.टी.आई खोल दी जाये क्योंकि आज की जो पढाई है वह टैक्नीकल अधिक है। अब टैक्नीकल का जमाना आ गया है लोग फीटर, वैल्डर की ट्रैनिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रोजगार मिलेगा। मैडम, अब बात आती है माल विभाग की माल विभाग में जैसे कल फाईनैंस मिनिस्टर जवाब दे रहे थे तहसील की बिल्डिंग बनाई गई हैं लेकिन मंत्री जी यह भेदभाव है कि डेढ़-दो वर्ष से कलायत सब डिविजन है उसमें आज तक कार्यालय तक बनाने का काम नहीं किया गया है तो लोगों में विशवास कैसे पैदा हो। यह भेदभाव की चर्चा जो लगातार चलती है वह चर्चाएं इसलिए बनती हैं कि जो मूल समस्याएं हैं अगर वह सबको समान लेकर के नहीं की जाएंगी तो आपका यह नारा कि 'सबका साथ सबका विकास' का मामला अधूरा रह जाएगा। इसी तरह सड़कों का मामला आया पी.डब्लू.डी. मंत्री भी यहां बैठे हैं जिसके लिए मैं इनका धन्यवाद करूंगा क्योंकि इन्होंने हमारे इलाके में जो सड़कों की रिपेयर का कार्य था उनको इन्होंने पूरा करने का काम किया है लेकिन मंत्री जी चार मार्ग ऐसे हैं जो आपसे संबंधित है हरसोला से लेकर तितरम तक वैसे उसके लिए मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी है और मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। अगर हरसोला से तितरम तक सड़क बन जाती है तो किसान अपने खेत की उपज को क्रय-विक्रय के लिए मण्डी में लेकर आते हैं तो उनको 10 किलोमीटर का रस्ता बच जाता है जबकि यह रास्ता सारा 5 किलोमीटर का है।

उपाध्यक्ष महोदया : जयप्रकाश जी आप वाईंड अप कीजिए।

श्री जयप्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, केवल दो मिनट का समय और दीजिए वैसे भी मैं ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि बाकि तो हम 21 तारीख को एडजोर्नमैंट मोशन पर बोलेंगे। दूसरी बात मंत्री जी आपने कलायत में अनाज मण्डी बनाई लेकिन उसमें जो एक्सटैंशन का कार्य था वह अधूरा है। आपने लिखा है कि हमने कृषि की उपज के क्रय-विक्रय के लिए पूरे प्रदेश में सबसे अच्छी फल व अनाज मंडियां बनाई हैं लेकिन उसमें कलायत को भी जोड़ दीजिए। इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कलायत की मण्डी को एक सड़क की जरूरत है जिसके लिए आपको जमीन भी एकवायर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि खरक पाण्डू से लेकर अनाज कण्डी तक ड्रेनेज डिपार्टमैंट की एक पटरी बिल्कुल खाली है। खरक पाण्डू से नैशनल हाई-वे-65 तक वह सारा ही एक किलोमीटर का रास्ता है। इस तरह के जो छोटे-छोटे मार्ग हैं उनको भी बनवा दिया जाए ताकि इनसे किसानों को कुछ सहूलियत मिल सके। मैं समझता हूं कि पहले तो यह रोड़ज मार्केटिंग बोर्ड के अधीन होते थे और अब पी.डब्लू.डी. के पास भी काफी पैसा आया है। अत : दोनों मंत्री यहां बैठे हैं इस पर झगड़ा मत करना कि मुझे कहा है या मुझे कहा है आप दोनों में से जिसके भी अधीन यह क्षेत्र आता है वही बनवा देना और एक सड़क आई.टी.आई. से अनाज मण्डी तक की है वह भी बनवाने का कष्ट करें। मंत्री जी आपने लाम्बा खेड़ी के लिए जो पानी की व्यवस्था की है वह एक बहुत अच्छा कार्य किया है और भारत सरकार का जो ईरीगेशन डिपार्टमैंट का बजट आया है उसके बारे में वैसे तो जब मैं लोकसभा का सदस्य था उस समय भी हमने यह मुद्दा उठाया था कि जिस तरीके से डिफैंस का बजट है, रेल का बजट है उसी तरह से खेती-बाड़ी, बिजली विभाग और नहर विभाग इन तीनों विभागों का अलग से एक विभाग बनाया जाए ताकि यह पता लगे कि कहां पानी की जरूरत है और कहां नलकूप के लिए बिजली की

जरूरत है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन तीनों विभागों का एक विभाग बना दिया जाए। इसके अलावा हमारे यहां लाम्बा खेड़ी माईनर का काम लिटिगेशन की वजह से बन्द पड़ा है और लिटिगेशन खत्म हो चुकी है। अगर उस माईनर को भी बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज सबसे बड़ी जो समस्या है उसमें उपाध्यक्ष महोदया आप भी मेरा साथ देंगी और ये सारा सदन भी मेरा साथ देगा। एक ट्रांस्पोर्टर का मामला है जिसके लिए मैं कल मंत्री जी से मिला था। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 900 ट्रांस्पोर्टर इस प्रदेश के ऐसे हैं जो आप ट्रांस्पोर्टर की नई पॉलिसी लेकर आए हैं उसमें उनको वंचित कर दिया गया है जबकि उसमें उनको वंचित नहीं करना चाहिए था। आप नई पॉलिसी लागू कीजिए लेकिन उसको उसी दिन से लागू कीजिए जबसे वह घोषणा की गई है लेकिन पिछले लोगों का रोजगार छिनने का जो पत्र चला गया है हम में से कोई विधायक ऐसा नहीं होगा जिनके पास प्राईवेट ट्रांस्पोर्टर नहीं आए, इसलिए इस पॉलिसी में कम से कम उन लोगों को जरूर रखा जाए जिनके पास पिछली बार लाईसैंस थे।

उपाध्यक्ष महोदया : जयप्रकाश जी, आप अपनी बात को समाप्त करें।

श्री जयप्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हमारे कलायत में एक देवबण गांव है जहां बिजली बोर्ड की बात बहुत आती है वहां पर आप रेड बहुत करवाते हैं तीन बजे, चार बजे इस तरह बिजली बोर्ड की फलाईंग स्क्वार्ड जाती है जैसे किसी डाकू को पकड़ने के लिए जा रही हो जबकि एक गांव में बिजली की चोरी लेस मात्र होती है लेकिन कई बार इस तरह के हालात पैदा कर दिये जाते हैं जो किसी की जान के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। मेरे इलाके के कस्बा कलायत के एक गांव के एक किसान का बिजली का बिल आठ लाख रूपये आ गया जिसके कारण उसको हार्ट अटैक आ गया और वह मर गया। क्या एक किसान का आठ लाख रूपये का बिल आ सकता है ? उपाध्यक्ष महोदया, हम बिजली चोरी या लाईन लॉसिज के पक्षधर नहीं है। बिजली चोरी या लाईन लॉसिज रोकी जानी चाहिए परन्तु वास्तव में लाईन लॉसिज इसलिए है क्योंकि बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाता है। मेरा इलाका धान की फसल के लिए प्रसिद्ध है। मेरे इस इलाके के देवबन गाँव में एक पॉवर हाउस पिछले तीन साल से पैंडिंग पड़ा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, आप भी गांव से आती हैं आपने देखा होगा कि कई बार तो गांव में जो रेहड़ी है, गड्डी है या ट्रैक्टर है उसकी छतरी के उपर बिजली की तारें टच कर जाती हैं। आप बिजली के कनैक्शन तो बड़ी भारी मात्रा में करते जा रहे हैं लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं और आप सभी जब गांव में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं कि वहां पर बिजली की तारें बहुत नीचे हैं। दिन-प्रतिदिन करंट व शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं के कारण अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी जो अभी यहां सदन में मौजूद नहीं हैं जब पॉवर में नहीं थे तो दिल्ली में धरने पर बैठे कर्मचारियों को सांत्वना देने जंतर-मंतर पर गये थे और यह आश्वासन भी देकर आये थे कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दो आपको पंजाब के समान वेतनमान दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, बड़ी खेद की बात है कि आज तक सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है। आपने कर्मचारियों को फायदा पहुंचाना तो दूर, 9000 चयनित जे.बी.टी. टीचर्ज पर पानी की बौछारें तक करवा दी है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी, आपको 22-23 मिनट बोलते हो गये हैं। आप बैठिये। दूसरे विधायकों को भी अपनी बात रखनी है। यदि आप इस तरह से बोलते रहे तो दूसरे विधायकों के लिए अपनी बात रखना मुश्किल हो जायेगा।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, बस मैं थोड़ी देर में अपनी बात पूरी कर लूंगा। वैसे तो ज्यादा बोलने वाला बस मैं एक ही एक विधायक सदन में मौजूद हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल तंवर : उपाध्यक्ष महोदया, इनको इस तरह बोलने के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मेरे को बोलने की परमिशन दी थी और यहाँ सदन में मेरे पड़ोसी मुझे बोलने से मना कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी, सारे विधायकों को अपनी बात रखनी है आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, 9000 चयनित जे.बी.टी. टीचर्ज की बात को सुना जाना चाहिए। तीसरा मेरा यह कहना है कि ...(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी, इस सदन में एक से एक अनुभवी वह इंटेलीजेंट विधायक मौजूद हैं। आप प्लीज बैठिये। आप प्लीज अपनी बात समाप्त करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, मैं बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल तंवर : उपाध्यक्ष महोदया, जय प्रकाश जी सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा तेजपाल जी से निवेदन है कि वह मुझे बार-बार परेशान न करें मैं एक मिनट में अपनी बात कहकर बैठ जाउंगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बोल रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी, आपने सभी बातें सदन में रख दी हैं, आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेजपाल तंवर : उपाध्यक्ष महोदया, जय प्रकाश जी सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जय प्रकाश जी , आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया,* * * * *(शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : जो बातें श्री जय प्रकाश जी द्वारा बिना मेरी इजाजत के कही जा रही हैं उनको रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया,* * * * *(शोर एवं व्यवधान)

श्री टेक चंद शर्मा (पृथला) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस सरकार का एक मुख्य सिद्धांत है कि सबका साथ-सबका विकास और सरकार इस सिद्धांत पर पूर्ण रूप से कायम भी है। आज से कुछ सप्ताह पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने सामाजिक ताने-बाने व भाईचारे को ठेस पहुंचाने का कार्य किया था। मैं उन कारणों में न जाते हुए क्योंकि आगे चलकर इस पर बहस होनी है, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में भी देश-विदेश के उद्यमियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में चल रही सरकार में आस्था जताई है। अभी गुड़गांव में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इंवेस्टर्ज समिट हुआ था उसमें 5.84 लाख करोड़ के एम.ओ.यू. साईन हुए थे। अगर भविष्य में इतना निवेश हरियाणा प्रदेश में आता है तो निश्चय ही हरियाणा प्रदेश की शक्ल बदलने वाली है। इसके अतिरिक्त जैसाकि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि मेरी सरकार इस सत्र में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल, 2016 लाने वाली है तो निश्चित रूप से इस बिल के आने के बाद संपूर्ण हरियाणा प्रदेश में औद्योगिकीकरण की एक क्रांति आयेगी। उपाध्यक्ष महोदया, किसी भी राज्य में औद्योगिक विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे जो पिछले 10 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था उसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे के मानेसर-पलवल खण्ड के 54 किलोमीटर लम्बे भाग का इसी महीने उद्घाटन करने जा रही है। कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस-वे दिल्ली के नजदीक होने के साथ-साथ दोनों तरफ औद्योगिक यूनिट स्थापित होंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्टर्न पैरीफरल एक्सप्रेस-वे में एक बाधा यह है कि 1-1 किलोमीटर तक दोनों तरफ कोई भी औद्योगिक यूनिट लगाने का प्रावधान नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्ष 2016 की जो औद्योगिक पॉलिसी है उसमें एक-एक किलोमीटर दोनों तरफ औद्योगिक यूनिट लगाने का प्रावधान किया जाये। 4 नवम्बर, 2010 में एक पृथला औद्योगिक एरिया के नाम से एक अधिसूचना हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी कि इस विकास योजना में 3102 एकड़ जमीन यानी लगभग 1255.87 हेक्टेयर क्षेत्र को औद्योगिक उपयोग हेतु 12 सैक्टरों में प्रस्तावित किया जायेगा। वर्ष 2010 के बाद आज 2016 आ गया है, लेकिन आज तक इस योजना में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर दोबारा से विचार किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, किसानों के बारे में चिंता करना हमारा कर्त्तव्य बनता है क्योंकि वे हमारे अन्न दाता हैं। हमारी सरकार द्वारा पिछले साल 22 सौ करोड़ रूपये का मुआवजा किसानों को दिया गया है। मैं नहीं समझता कि इतना मुआवजा आज तक जब से हरियाणा बना है कभी भी टोटल मिलाकर दिया गया होगा। मार्च सत्र के दौरान सरकार द्वारा 12 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से राशि किसानों को मुआवजे के तौर दी गई थी। किसी भी प्रदेश की सरकार ने इतना मुआवजा किसानों को नहीं दिया है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण हुई फसल की बर्बादी के लिए 967 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया। प्राकृतिक आपदा में किसानों को मुआवजा देना

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सरकार का हक बनता है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जो फसल बीमा योजना या किसानों की भलाई के लिए चलाई जा रही अन्य योजनाओं के अनुसार मुआवजा दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा। सफेद मक्खी के प्रकोप से 5 जिलों में 967 करोड़ रूपये का जो मुआवजा दिया गया है, इसका हमें मालूम नहीं कि यह क्या होता है। क्योंकि हमारे यहां ना तो कपास होती है ना ही हमें इस चीज का पता है। मेरे माननीय साथी भाई जय प्रकाश जी कह रहे थे कि हमें तो सफेद मक्खी का मुआवजा ही नहीं मिला है। (शोर एवं व्यवधान) यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है क्योंकि एक वर्ष में पूरे प्रदेश में फसलों के नुकसान के कारण 1102 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया जाता है सिर्फ 5 जिलों में 967 करोड़ का मुआवजा केवल सफेद मक्खी के प्रकोप के कारण दिया जाता है फिर भी यह कहा जा रहा है कि सरकार मुआवजा देने में अनिमयताएं कर रही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि करनाल से लेकर अम्बाला और अटेली तक के क्षेत्र में लोगों को सफेद मक्खी और लाल मक्खी का पता भी नहीं है। हमें इस बात से एतराज नहीं है कि किसानों को सफेद मक्खी की वजह से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जा रहा है। यह खुशी की बात है कि किसानों को कम से कम फसल की भरपाई तो की जा रही है। मैं आपके माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि पूर्व की सरकारों ने किसानों को सफेद मक्खी का कितना मुआवजा दिया है। यह तो भाजपा की पहली सरकार है जिसने किसानों को सफेद मक्खी की वजह से खराब हुई फसल का इतना मुआवजा दिया है। हमारी सरकार के अलावा आज तक किसी भी सरकार ने किसानों को इतना मुआवजा नहीं दिया है। अगर किसी भी सरकार ने किसानों को सफेद मक्खी का मुआवजा दिया है तो इस सदन में से बताया जाए। (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : उपाध्यक्षा महोदया, आज तक किसी सरकार में इतनी फसल खराब भी नहीं हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : रणबीर गंगवा जी, आप कृपा करके बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा : उपाध्यक्षा महोदया, सत्ता पक्ष के साथी आज मुआवजे की बात कर रहे हैं। किसानों को फसल का मुआवजा चौधरी देवीलाल ने देना शुरू किया था। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : गंगवा जी, आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री(श्री कृष्ण लाल पंवार) : आदरणीय उपाध्यक्षा महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने गेहूं की फसल के बर्बाद होने पर 1092 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने पिछली सरकार के बकाया 243 करोड़ रूपये के मुआवजे को भी अदा किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : उपध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री रणबीर गंगवा जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने आज तक किसानों के लिए राजनीति के सिवाय कुछ नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होनें 9 सौ करोड़ रूपये ... (विघ्न) माननीय सदस्य असंध हल्के से 4 बार विधायक रहे हैं और अभी वहां से सरदार बख्शीश सिंह विर्क विधायक हैं। मंत्री जी हमें

बताएं कि इन्होंने असंध हल्के में गेहूं की खराब फसल का कितना मुआवजा दिया है। (विघ्न) असंध विधान सभा क्षेत्र के लिए एक पैसा भी नहीं दिया गया। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए 1092 करोड़ रूपये मुआवजे के लिये स्वीकर किये हैं। हमने असंध विधान सभा क्षेत्र के लिए दोबारा सर्वे करवाया है। अब किसानों का सही विकास हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री टेकचन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, आज सदन का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्य किसानों के हित की बात करने की बजाय सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव(सरदार बख्शीश सिंह विर्क) : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने किसी भी माननीय सदस्य की बात को बीच में नहीं काटा। अत: माननीय सदस्यों को भी मेरी बातों को बीच में नहीं काटना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र असंध की बात उठी है। यह बात किसी हद तक तो सही है। दूसरी बात पूरी सही नहीं है। जब सरकार ने सर्वे करवाया तो खेतों में कनक के बाद जीरी लग चुकी थी। उसके बाद उन्होंने किसानों से सी-फार्म कलैक्ट करके पिछली सरकार का सर्वे ही दोहराया है जिसमें कुल 89 लाख रूपये का मुआवजा दिया गया है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आने वाली फसल से पहले किसानों को मुआवजा दे देंगे।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : अध्यक्ष महोदय, ----

श्री टेकचंद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार किसानों के हित की बात करती है तो हमारे साथियों को तकलीफ होती है। जहां मुआवजा दिया जाता है उस बारे में ये कहते हैं कि किसान की फसल का वहां नुकसान हुआ ही नहीं है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि ये लोग इसी प्रकार से मिलीभगत करके इस तरह के काम किया करते थे। आज इस सरकार द्वारा 967 करोड़ रूपये मुआवजे की राशि दी गई है। उपाध्यक्ष महोदया, यह नुकसान पहली बार नहीं हुआ है, इस तरह के नुकसान पहले भी होते रहे हैं। गंगवा जी, जब आपकी सरकार में नुकसान हुए थे उस समय आपकी पार्टी ने मुआवजा देने की जरूरत नहीं समझी। आप लोग किसान विरोधी बात करते हो। (विघ्न) आप लोगों ने किसानों को 10-10 रूपये मुआवजे के रूप में दिए और किसानों के साथ भद्दा मजाक करने का काम किया था इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ही किसान विरोधी है। आप भी तो किसान विरोधी बातें कर रहे हैं। (विघ्न) यह बात रिकार्ड में लाई जाए कि आज तक कितना पैसा मुआवजे के रूप में दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने तो 967 करोड़ रूपये का मुआवजा देने का बहुत बढ़िया काम किया है।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, मुआवजा देने की शुरूआत चौधरी देवीलाल जी ने की थी। (विघ्न) इस सरकार में कानून व्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हरियाणा में जो हालात जाट आरक्षण के दौरान हुए हैं, ऐसे हालात मैंने अपने जीवनकाल में पहले कभी नहीं देखे। (विघ्न)

श्री ज्ञानचंद गुप्ता : गंगवा जी, आपके समय में तो किसानों को मुआवजे के नाम पर 10-10 रूपये के चैक दिए गए थे। (विघ्न)

श्री रणबीर सिंह गंगवा : उपाध्यक्ष महोदया, -----

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, इस सरकार में तो किसानों से एक एक लाख रूपये प्रोसैसिंग फीस ली जा रही है। (विघ्न)

श्री टेकचंद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, ये साथी मेरा टाइम खराब कर रहे हैं इसलिए मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जब इनको बोलने के लिए समय दिया जाएगा तब ये अपनी बात यहां रख लें। उपाध्यक्ष महोदया, जो सच्चाई है मैं उसे कहकर ही रहूंगा। (विघ्न) मैं तो पहली बार चुनकर आया हूं लेकिन जितने भी सदस्य यहां बैठे हैं उन सब लोगों को यह पता है और यह बात यहां लिखी भी हुई है कि या तो सभा में प्रवेश न किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए तो सच और स्पष्ट बात कही जाए। यदि यहां मनुष्य गलत बात कहेगा तो वह पाप का भागीदार होगा।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, ----

उपाध्यक्ष महोदया : संधू जी, आप बैठिए और जब आपको बोलने का समय मिलेगा तब आप अपनी बात कहना। (विघ्न)

श्री टेकचंद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, यहां लोगों का ध्यान डायवर्ट करके सच्चाई को सामने आने से रोकने की कोशिश की जाती है। जब आरक्षण की बात आती है तो ये लोग अलग बात करते हैं। किसानों की बात आती है तो इनके दो मुंह हो जाते हैं। ये लोग सच्चाई को सामने लाने की बजाय सदन को बरगलाने की बात करते हैं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, स्मार्ट सिटी की गिनती में हमारे हरियाणा के फरीदाबाद और करनाल शहर लिए गए हैं। फरीदाबाद में जब मैट्रो का उद्घाटन किया गया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस मैट्रो को आने वाले समय के लिए बल्लभगढ़ तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, हमारे देश का कुल क्षेत्रफल 1.4 प्रतिशत है जबकि हमारे किसान 14.14 प्रतिशत योगदान देते हैं। कई बार प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तो बेघर होने वाले लोगों के रहने के लिए भी उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो पिछले सत्र में बात आई थी और मैंने प्रश्न भी लगाया था कि कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में केवल 25 कालेज खोले गए थे। जिनमें से 21 कालेज केवल रोहतक, झज्जर और भिवानी में खोले गये थे। जबकि मौजूदा सरकार 'सबका साथ सबका विकास' के नारे के साथ चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में कॉलेज खोले जा रहे हैं और आने वाले समय में इसका फायदा पूरे प्रदेश को होगा। हमारी बहन नैना चौटाला जी के हल्के में भी नया कालेज खोला जायेगा और मेरे पृथला हल्के के मोहना में भी नया कॉलेज खोला जायेगा। पिछली सरकार की तरह नहीं है कि केवल चुनिंदा जिलों में कालेज खोले जायें बल्कि अब सरकार चारों तरफ कालेज खोलने जा रही है। इससे लगता है कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में चारों तरफ चहुँमुखी विकास होगा। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं ग्रामीण विकास की बात करना चाहूंगा। पिछले सत्र में ग्रामीण क्षेत्र से पढे लिखे प्रतिनिधि आये उनको लेकर सरकार एक बिल लेकर आई थी। उस बिल का आई.एन.एल.डी. और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने विरोध किया था कि इस बिल के आने से नुक्सान होगा। अब चुनावों के बाद जब उसका रिजल्ट आया है तो पंचायती राज संस्थाओं में एजुकेटिड और प्रगतिशील युवा चुनकर आये हैं। इसमें युवाओं की एवरेज 35.50 प्रतिशत है। हर विधान सभा क्षेत्र में आज

भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि सबसे अधिक चुनकर आए हैं इसमें भी कोई दो राय नहीं है और यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है और इस सदन की गरिमा का विषय है। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से स्वर्ण जयंती विकास धन राशि स्कीम ग्रामीण विकास के लिए पहली बार शुरू की गई है। इससे पहले यह योजना लागू नहीं थी। इसी तरह से 'हमारी योजना हमारा विकास' भी नई स्कीम चलाई गई है इस योजना के तहत सभी पंचायतों में पैसा दिया जायेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को मुबारकवाद देता हूं। पहले क्या होता था कि जिस गांव में सरकार के विरोधी पक्ष की पंचायत होती थी वहां पर पैसे नहीं दिए जाते थे लेकिन इस योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के हिसाब से पैसा दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, इसके साथ-साथ मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं उनका भी जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं जिन्होंने पृथला विधान सभा क्षेत्र में 26 सड़कें 22.3 करोड़ रूपये की लागत से बनवाई हैं या रिपेयर करवाई हैं। (विघ्न) परिवहन मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं उनसे मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि खनन का कार्य चालू हो गया है जिसके कारण ओवर लोडिड ट्रक आते हैं जिनमें साथ में पानी भी आता है जो नई बनी हुई सड़क पर पड़ने के कारण सड़क टूट रही हैं इसलिए इस तरफ वे विशेष ध्यान दें। मोहना से बल्लभगढ़ सड़क पर बहुत ज्यादा ओवर लोडिड ट्रक आते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से सरकार ने 'हमारा गांव जगमग गांव', स्कीम चालू की है जिसका पहला फीडर मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगाया गया है। वहां पर पहले 25 प्रतिशत की रिकवरी होती थी और 75 प्रतिशत का लॉस होता था लेकिन इस स्कीम के लागू होने से अब स्थिति उल्ट होकर 75 प्रतिशत की रिकवरी होती है और 25 प्रतिशत बिजली का लॉस होता है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार को मुबारिकवाद देता हूं। मैंने यहां कल भी एक बात सरकार के ध्यान में लाई थी कि मेरे हल्के में एक खंदावली गांव है जहां पर डेढ़ साल पहले 12वीं के स्कूल की झूठी नोटिफिकेशन दिखाकर बच्चों का एडमिशन कर दिया गया जबकि वहां पर शिक्षकों की बहुत ही ज्यादा कमी है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इसको भी ठीक करवाया जाये। परिवहन मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जैसे गुड़गांव से चण्डीगढ़ वॉल्वो बस चलती है उसी प्रकार से एक बस भविष्य के स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से चण्डीगढ़ के लिए भी चलाई जाये और अगर यह सम्भव हो तो यह और भी अच्छा हो जायेगा कि इस बस को पृथला से वाया फरीदाबाद चण्डीगढ़ के लिए चलाया जाये। हमारे यहां पर नेशनल हाईवे नम्बर 2 को अभी सिक्स लेन किया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार गांव सीकरी, कैली, पृथला और बधौला ऐसे हैं जो इस हाईवे के दोनों तरफ बसे हुए हैं और इस हाईवे के कारण वे दो-दो भागों में बंटे हुए हैं। मैं इस विषय में सम्बधित मंत्री जी को विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस मामले को केन्द्र सरकार के स्तर पर उठायें और इन गांवों में फ्लाई ओवर बनवाने की व्यवस्था करवायें ताकि रोड पर चलने वाला ट्रैफिक भी बिना किसी बाधा के चले और किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना भी न हो। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले यहां पर एक शेयर अर्ज़ करना चाहूंगा :-

"असमंजस में पड़े रहे तो नौका पार नहीं होगी,
लेकिन दृढ़ संकल्पित व्यक्ति की कभी हार नहीं होगी।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इस महान सदन में अपने विचार रखने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। हरियाणा वह प्रदेश है जिसको "हरि की भूमि" कहा जाता है। हरि का आरण्य मतलब इस प्रदेश के अंदर हरि का वास है। वर्ष 1966 में जब इस प्रदेश का जन्म हुआ उस समय जो विकास के बीज का रोपण इस प्रदेश में हुआ वह हमारी सरकार के प्रयासों से आज एक सम्पूर्ण वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है। हमारी सरकार विकास की विभिन्न योजनायें लाकर हरियाणा प्रदेश को पूरे राष्ट्र के विकास में एक अग्रणी भूमिका निभाने के योग्य बनाने की ईमानदारीपूर्वक कोशिश और जी-तोड़ मेहनत कर रही है। हमारा हरियाणा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के पथ पर बड़ी तेजी से अग्रसर है। आज हरियाणा प्रदेश और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। हरियाणा प्रदेश आज विकास का पर्याय भी बन चुका है। हमारा आज का हरियाणा विश्वास और आस का पर्याय भी बन चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जिसे भारत का दिल कहा जाता है उसके तीन तरफ हरियाणा बसा हुआ है। दिल्ली के नज़दीक ही हमारे हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद महानगर बसे हुए हैं। जब उद्यमियों द्वारा कोई विकास का पैमाना तय किया जाता है तो वह दिल्ली से सटे हुए शहरों के आधार पर तय किया जाता है। हमारा हरियाणा प्रदेश इसमें बिना किसी संदेह के आगे जा रहा है। मेरा इस महान सदन के सभी सदस्यों के माध्यम से सरकार से एक निवेदन है कि जैसा कि सभी जानते हैं कि पिछले दिनों प्रदेश में जो अनहोनी घटनाएं हुई मैं समझता हूं कि उसमें जो मुख्य रूप से कारण रहा वह यह था कि आज तक हमारे प्रदेश की धरती के ऊपर "मेरा हरियाणा और तेरा हरियाणा" का राग अलापा गया। चाहे हमारे हरियाणा में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का राज रहा और चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का राज रहा, सभी ने इसी "मेरा हरियाणा और तेरा हरियाणा" की भावना को ही मज़बूत किया। किसी ने भी हरियाणा प्रदेश को "मेरा हरियाणा और तेरा हरियाणा" की भावना से बाहर निकालने का न प्रयास किया और न ही बाहर निकलने दिया लेकिन हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने "सबका साथ और सबका विकास" का एक क्रांतिकारी नारा दिया। इसी का परिणाम यह हुआ कि आज हमारा हरियाणा प्रदेश "मेरा हरियाणा और तेरा हरियाणा" की संकुचित भावना से बाहर निकलकर "हमारा हरियाणा, अपना हरियाणा और सबका हरियाणा" की भावना की ओर अग्रसर है। जब यह कांसैप्ट पूरी तरह से लागू हो जायेगा हमारा हरियाणा अपना और सबका हरियाणा बन जायेगा। उसके बाद इस प्रकार की अनहोनी घटनाओं की पुनरावृत्ति यहां पर कभी भी नहीं होगी। इसके साथ ही साथ यहां पर एक एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा चला। ये दो बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर सर्वप्रथम मैं एक-एक लाईन में ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा है इसके ऊपर दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बयान आये। चाहे वह दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री का ब्यान हो इनके व्यक्तव्यों को सुनकर ऐसा लगता है कि ये व्यक्तव्य राजनीतिक हानि-लाभ को ध्यान में रखकर दिये गये हैं। मैं इस बारे में अपनी बात ज़रूर कहना चाहता हूं। किसी कवि ने इस बारे में दो पंक्तियां बहुत ही अच्छी लिखी हैं। वे हैं :-

पंछी या हवा के झौंके,
कोई सरहद न इनको रोके।

मैं भी यही कहना चाहता हूं कि पक्षियों के ऊपर, हवा के ऊपर और नदियों के ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक राज्य विशेष का कोई अधिकार नहीं है। जैसे नदियां प्राकृतिक रूप से बहती हैं हमें उनको निर्बाध रूप से बहने देना चाहिए और इस प्राकृतिक सम्पदा पर सभी को उनका ज़रूरी हक मिलना ही चाहिए। हम आज दिल्ली का पानी रोकने के हक में नहीं हैं लेकिन यह महान सदन और पूरा प्रदेश अपना पानी छोड़ने के हक में भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह जो "बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ" योजना चलाई है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये BB को BBB में बदल दिया। प्रधानमंत्री जी का नारा था "बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ" लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको और आगे बढाते हुये उसमें एक B और जोड़ दिया कि "बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ-बेटी-बढ़ाओ" क्योंकि बेटियों को बढ़ाना भी जरूरी है। इसीलिए माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे प्रदेश को पूरे देश में लिंगानुपात सुधार के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है जिसके लिए पूरी सरकार बधाई की पात्र है। पहला "बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ" चौक अम्बाला में स्थापित हुआ है तथा आदरणीय बहन कविता जैन जी ने उसका उद्घाटन किया है। यह एक कल्पना या कार्यक्रम मात्र नहीं है बल्कि यह निरन्तर चलने वाली एक साधना है। इसको हम "बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ" आन्दोलन कह सकते हैं जिसमें हरियाणा सरकार पूरे देश में एक अग्रणी भूमिका निभा रही है। मैं माननीय परिवहन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने इसी "बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ" योजना के तहत देश में पहली बार बेटियों की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट एप लांच किया है। बच्चे कहीं स्कूल में जाते हैं और 8-10 किलोमीटर दूर उनका स्कूल है तो मां-बाप को चिन्ता होती है कि हमारे बच्चों के साथ बस में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जब भी हमारा कोई सामान कोरियर के माध्यम से आना होता है तो हम 10 बार फोन करके कोरियर वाले से पूछते रहते हैं कि हमारा सामान आया या नहीं लेकिन इस 10 किलोमीटर के सफर में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। बहन कविता जैन जी ने अपने हाथों से उस एप का उद्घाटन किया है। उस एप से मां-बाप के मोबाइल पर बच्चे की लाईव लोकेशन आयेगी कि बच्चा बस में कहाँ पर बैठा हुआ है, ड्राईवर या कंडक्टर उसके साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है तथा उसको उस रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। बस स्कूल के रास्ते पर ही जा रही है या किसी और रास्ते पर जा रही है। हमने अम्बाला में 14 फरवरी, 2016 जिसको पाश्चात्य संस्कृति में वैलेंटाईनडे के रूप में मनाया जाता है उसको कन्या-पूजन-दिवस के रूप में मनाया। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूँ कि हमने पहली बार देश में सरकारी स्कूलों में Smart interactive working Class Room का उद्घाटन किया है। माननीय श्री सुभाष चन्द्रा जी जो जी.टी.वी. के मालिक हैं वे स्वयं इन स्कूलों का उद्घाटन करने के लिए आये थे। जो आकाश, फिटजी, हेलिक्स जैसे इन्स्टीट्यूट्स हैं उनकी फैकल्टी सरकारी स्कूलों के 1500 बच्चों को मैथ और साइंस पढ़ा रही है। अगर यह पायलट प्रोजैक्ट कामयाब सफल रहा तो आने वाले समय में हम उसको हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में लागू करेंगे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इन स्कूलों से निकलने वाले बच्चे मैथ और साइंस में नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी प्रकार से अभी हमारे साथी श्री टेक चन्द शर्मा जी ने हैपनिंग हरियाणा की बात की जिसमें 359 एम.ओ.यू. साईन हुये तथा उसमें 5.84 लाख करोड़ रूपये का निवेश हुआ। इस समय इंडस्ट्रीज हरियाणा की लाईफ-लाईन बन कर उभरी है और हरियाणा इसमें बहुत आगे जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री श्री अनिल विज

जी का भी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने नई खेल नीति बनाई है। इसी से संबद्ध 23 मार्च को शहीदे-आजम भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव जी की पुण्यतिथि पर भारत केसरी दंगल का आयोजन हो रहा है। इससे युवाओं को नशामुक्त बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी क्योंकि वे भी युवावस्था में इस देश पर अपनी जान को न्यौछावर कर गये थे। आज भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव जी सारे युवाओं के लिए आदर्श हैं। हमारी सरकार ने शहीदों को जिस प्रकार से आदरांजली देने का काम किया है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पर दो पंक्तियाँ अवश्य कहना चाहूँगा कि

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले।
वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा।।

इस बात को हमारी सरकार चरितार्थ करने में लगी हुई है।

13:00 बजे दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय अन्न योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रणेता पं. दीन दयाल उपाध्याय जी के अन्त्योदय दर्शन का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज में सबसे पिछली लाईन में बैठा है और जिसके तन पर कपड़ा नहीं, पेट में रोटी नहीं और रहने के लिए सिर पर छत नहीं है तथा पैरों में बिवाई फटी हुई है जब तक उस व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई ये मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार चलाना बेमानी है। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे गुजरात के, छत्तीसगढ़ के और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों को वह उसी धारणा पर चलते हुए आज वर्षों से लोगों की सेवा कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी इस अन्त्योदय अन्न योजना के राष्ट्रीय संयोजक रह चुके हैं। वह भलीभांति गरीब का दर्द जानते हैं इसलिए ऐसी जन-कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार दीन दयाल जन आवास योजना के तहत जो हमारे उत्तम और मध्यम क्षमता के कस्बे हैं उनमें सस्ते आवास बनाकर गरीब लोगों को दिये जाएंगे। इसके लिए भी मैं हमारी सरकार की सराहना करता हूं। जहां तक भ्रष्टाचार, ई-गवर्ननेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरैंस की बात है उससे आज तहसीलों के अन्दर वह दुकानदारियां बन्द हो गई हैं जो पिछली सरकारों के समय से चली आ रही थी। उस समय बोली लगा करती थी तहसीलों में पूरे मेले लगा करते थे जहां पर दलाल सक्रिय रहते थे। जब कोई आदमी अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने आता था तो वहां तहसीलों में दलालों द्वारा बोली लगती थी कि मैं तेरी रजिस्ट्री इतने प्रतिशत में करवा दूंगा और दूसरा कहता था कि मैं इतने प्रतिशत में करवा दूंगा। आज तहसीलों से वह सारा माहौल समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री डैश बोर्ड और सी.एम. विन्डो के माध्यम से जन संवाद का एक अनूठा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है मैं उसके लिए भी इनको बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ जो हमारी पढ़ी-लिखी पंचायतों के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाकर इस महान सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ जिससे पढ़ी-लिखी पंचायतें बनी हैं और आज समझ, शिक्षा, ज्ञान, प्रतिभा और काम करने वालों को जो मौका हमारी सरकार ने दिया है वह अपने आप एक अनूठा अनुकरणीय उदाहरण है और मुझे लगता है कि भारत का हर एक प्रदेश धीरे-धीरे इस ओर चलेगा और जल्दी ही पढ़ी-लिखी पंचायतें भारत के हर प्रदेश में नजर आएंगी। शहरीकरण के दबाव को कम करने के लिए तथा क्राईम को रोकने के लिए हमारी सरकार ने स्वर्ण जयन्ती महाग्राम योजना बनाई है और इसी के साथ हमारी सरकार ने नगर पंचायत का एक नया कॉन्सैप्ट तैयार किया है कि जो गांव 10 हजार या उससे

ऊपर की आबादी वाले हैं उनको नगर पंचायतों का दर्जा दिया गया है और उन गांवों में रूर्बन मिशन के तहत शहरों जैसी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है उसके लिए भी मैं हमारी सरकार को बहुत-बहुत साधूवाद देना चाहता हूं। हरियाणा में गौ-वध निषेध का जो नया कानून बना है जिससे गौ संवर्धन और गौ संरक्षण का जो नियम बना जिसकी पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में गौ भक्तों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। गीता जयन्ती महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में प्रोग्राम किये गये क्योंकि गीता के ऊपर पहले कुरूक्षेत्र में एक फंक्शन करके उस बात की इतिश्री कर ली जाती थी लेकिन पहली बार पूरे प्रदेश में गीता जयन्ती मनाई गई। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गांव भारत के दिल में बसते हैं। इन पांचों प्रकल्पों के लिए हमारी सरकार भलीभांति काम कर रही है। जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात है इस बार पंचायती चुनावों में जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत की रिजर्वेशन तय की थी उस आरक्षण की बजाय 42 प्रतिशत महिलाएं पंचायत चुनावों में जीत कर आई हैं और यह महिला सशक्तिकरण की जागृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम, जो गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी है उसके द्वारा गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया गया। माननीय मोदी जी ने भी अपने मन की बात में हरियाणा की अनूठी पहल का जिक्र किया इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मैं अपने अम्बाला शहर की बात करूं तो जो 10 सालों से हमारा बस स्टैण्ड गायब था जो पूर्व की सरकार ने गिरवा दिया था। मुझे लगता है कि भारत के 600 जिलों में अम्बाला अकेला एक ऐसा जिला मुख्यालय होगा जहां अपना बस स्टैण्ड भी नहीं था। पूर्व में जो सरकारें रही उनमें एक सुपर मुख्यमंत्री थे उन्होंने सबसे कीमती शहर की जमीन को हड़पने के लिए उस बस स्टैण्ड को 9-10 साल पहले गिरवा दिया और बस स्टैण्ड के लिए एक अलग से बेकार जगह को एक्वॉयर कर लिया गया लेकिन बस स्टैंड को बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गये। माननीय मुख्यमंत्री अम्बाला में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। मैंने उस कार्यक्रम में बस स्टैंड का जिक्र कर दिया और यहां ऑफिसर गैलेरी में ढिल्लों साहब बैठे हुए हैं वह भी इस बात के गवाह हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 9-10 साल से लटके हुए इस मसले पर महज चार मिनट में एक्शन लेते हुए रात को ही ढिल्लों साहब को फोन करके कहा कि अम्बाला का बस स्टैंड बनना चाहिए। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : उपाध्यक्ष महोदया, अम्बाला बस स्टैंड बनाने के कार्य को मंजूरी भी दे दी गई है।

श्री असीम गोयल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ माननीय श्री कृष्ण लाल पंवार जी का भी इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय विज साहब सिविल हॉस्पिटल का भी जिक्र कर रहे थे उस संबंध में मैं सदन के समक्ष बताना चाहता हूँ कि 40 करोड़ रूपये की लागत से 100 बैडों का एक नया अस्पताल हमारे अम्बाला शहर में मंजूर हो गया है। अम्बाला शहर की विभिन्न सड़कों के लिए चाहे वह सड़क पी.डब्लयू.डी. से संबंध रखती हो, चाहे वह एम.सी. से संबंध रखती हो या फिर हुडा से संबंध रखती हो, अम्बाला शहर की टूटी-फूटी सड़कों के लिए 52 करोड़ रूपया दिया गया है जिसके लिए मैं सरकार का बहुत-बहुत धन्यवादी हूँ। आज लोग

कहने लग गये हैं कि जो अम्बाला की चमक 1855 में हुआ करती थी वह कहीं खोकर रह गई थी। जो अम्बाला शहर महज एक गांव बनकर रह गया था, आज लगता है कि वह अम्बाला शहर अपनी आन-बान-शान को फिर से प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहा है। अम्बाला शहर की बाढ़ से मुक्ति के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साढ़े बाईस करोड़ रूपये स्वीकृत किए है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार वंचित से संचित और शोषित से पोषित अर्थात जो वंचित समाज है उसको संचित करने के लिए और जो शोषित समाज है उसको पोषित करने के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश को सही मायने में नम्बर वन प्रदेश बनाने के लिए हरियाणा एक- हरियाणवी एक का नारा दिया है। भारतवर्ष को पुन: विश्व गुरू बनाने के लिए जो हमारे देश की सरकार और अन्य कई प्रदेशों की सरकारें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की ओर देख रही हैं। मैं अपनी सरकार को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ और माननीय गवर्नर साहब का जो अभिभाषण था उसकी भी पूरी तरह से संतुति करते हुए पूरे महान सदन में आपके माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ और यह बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि :-

"सुर मेरी साधना का शेष रहना चाहिए,
मैं रहूँ, न रहूँ -मेरा देश रहना चाहिए।।"

इसी सोच के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है उसके लिए वह बधाई की पात्र है। धन्यवाद, जय हिन्द जय हरियाणा।

श्री जाकिर हुसैन(नूंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान खासतौर से जिला मेवात की जो बहुत सी समस्यायें हैं जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं किया गया है, उनकी ओर दिलाना चाहूँगा। जीवन में सबसे ज्यादा पीने के पानी की जरूरत होती है। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बहुत संवेदनहीन हो गये हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा विधान सभा की Subject Committee on Local Boadies and Panchayati Raj Institutions ने अपनी अध्यक्षा श्रीमती संतोष चौहान सारवान जी के नेतृत्व में 14 फरवरी, 2014 को मेवात का विजिट किया। बहुत से गांवों का दौरा किया गया। वहां पर मालब और मेवली गांवों को बड़े गांवों की श्रेणी में गिना जाता है। मेवली गांव को रेनीवैल स्कीम से जोड़ने के लिए हरियाणा विधान सभा की कमेटी ने अपनी संस्तुति दी और सरकार ने रेनीवैल स्कीम को पांचवें महीने में मंजूरी दे दी। मेरे पास उस मंजूरी की चिट्ठी है लेकिन बावजूद इसके आज तक जन स्वास्थ्य विभाग ने पैसे न होने के बहाने से इस गाँव को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए कोई शुरूआत नहीं की। मतलब मेरे कहने का यही है कि जनस्वास्थ्य विभाग बहुत ही संवेदनहीन विभाग बन गया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात जिले को पानी देने के लिए 400 करोड़ रूपये की रेनीवैल परियोजना शुरू की थी जिसके साथ कांग्रेस के शासन काल में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई थी। इस परियोजना के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड होने की कारण अब मेवातवासियों को इस योजना के बारे में आशंका उत्पन्न होने लग गई है। आज मेवात की जनता पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है वह सब पिछली कांग्रेस सरकार की देन है। रेनीवैल का मेन बूस्टिंग स्टेशन हूजपुरी गांव में बनना था। मेरे पास ओरिजनल प्रोजैक्ट की रिपोर्ट है लेकिन अफसोस इसको 15 किलोमीटर पीछे पलवल की तरफ

ले जाया गया। आज भी पूरा मेवात, मेडिकल कॉलेज और जिला हैडक्वाटर के सारे गांव पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बादली-नूंह पेयजल परियोजना के साथ बड़ी भारी छेड़खानी की जा रही है। सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिएं। लगभग 100-125 गांवों को पीने के पानी के लिए महरूम होना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, यह एक रिकॉर्ड की बात है। इसी तरह से आज हमारे साथ एक और भद्दा मजाक होने जा रहा है कि वर्ष 2011 में और उसके बाद नैशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड से परियोजना का प्रस्ताव हुआ था कि बादली में वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाया जाये और नूंह को बादली से सीधा जोड़ा जाये लेकिन यह परियोजना शुरू नहीं हुई । एन.सी.आर.पी बोर्ड ने इस परियोजना को शुरू किया था। मेडिकल कॉलेज को 8 लाख लीटर पानी हर रोज चाहिए। नूंह के 21 गांव व शहर को पानी देने की कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो लगातार चल सके। इसके लिए वहां से विभाग ने एक स्कीम बनाई, उस स्कीम को भी लागू नहीं किया गया बल्कि उस स्कीम में फरूखनगर और पटौदी को उसके साथ जोड़ दिया गया। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार बादली से फरूखनगर व पटौदी के लिए वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट की अलग पाइप लाइन आनी चाहिए थी। पटौदी के लिए पाइप लाइन अलग आनी चाहिए थी और नूंह के लिए पाइप लाइन सीधी जानी चाहिए थी, जिनको इकट्ठा कर दिया गया। हमारी आशंका इस बात की है कि रियेल एस्टेट में बहुत मंदा है। जैसे हर व्यापार में तेजी आती है वैसे ही सारे सी.एल.यू. पटौदी और रेवाड़ी में हुए हैं। आने वाले समय में यें सिर्फ गांव ना रहकर डिवैल्प होकर के गुड़गांव से भी बड़े शहर होंगे। उपाध्यक्ष महोदया आप खुद जानती है कि रेवाड़ी और गुड़गांव एक हो जायेगा। पानी की जो स्थिति होगी वह रैनीवैल परियोजना से बहुत ज्यादा भयावह होगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पहले वाली स्कीम के अनुसार ही बादली से नूंह तक पाइप लाइन सीधी आए उसके साथ बीच में कोई छेड़छाड़ ना की जाये, वरना नूंह के लिये ना आज पानी है और ना ही भविष्य में पानी मिलेगा। विभाग तो सिर्फ खानापूर्ति ही करता है कि हम वहां पर मीटर वगैरह लगा देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, आप देख रही हैं कि आज एस.वाई.एल. नहर के लिए हम पानी नहीं केवल पैसेज की मांग कर रहे हैं। जब पंजाब व हरियाणा एक था तो हरियाणा में विकास करने की मांग उठी थी। जब हरियाणा अलग हुआ तो दक्षिण हरियाणा के विकास करने की मांग उठी। रोहतक क्षेत्र से मुख्यमंत्री बने तो सिर्फ रोहतक का ही विकास हुआ। आज पीने के पानी की बात जब आती है तो दक्षिण हरियाणा के अहीरवाल कहते हैं कि मेवात कैनाल फीडर को साल्हावास कैनाल फीडर से पानी नहीं देंगे। पीने का पानी सुचारू रूप से सबको मिलना चाहिए। मैं चेयपर्सन श्रीमती संतोष चौहान सारवान का धन्यवाद दूंगा कि उनके निर्देश से विभाग ने एक स्कीम बनाई है और वह मात्र 22 करोड़ की लागत से पाइप लाइन बादली से पटौदी तक लगेगी जिससे यह पाइप लाइन सीधी बाईपास हो जायेगी। जबकि तीनों परियोजनाओं की कीमत 250 करोड़ रूपये की है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस स्कीम का अनुमोदन करने की कृपा करेंगे। इसी तरह मेवात जिले के नूंह, फिरोजपुर झिरका व नगीना के 80-80 गांवों में पीने के पानी की एक भी बूंद नहीं है। चौधरी चौटाला साहब का जो रैनीवल परियोजना का सपना था वह पूरा नहीं हुआ है। अब एक दूसरी रैनीवल 264 करोड़ रूपये की परियोजना है, उसे अटोवा गांव से हसनपुर गांव तक बनाया जाये। आज के आधुनिक युग में और मात्र 45 किलोमीटर दिल्ली से दूरी पर बसने के बावजूद भी नूंह में एक बूंद भी पीने के पानी की नहीं है। पूरे नॉर्थ वेस्ट सैन्टर में जम्मू कश्मीर के अलावा मुस्लिम माइनोरिटी का मेवात एक अकेला माइनोरिटी जिला है। आज

[श्री जाकिर हुसैन]
हमारे प्रदेश में पीने के पानी की यह हालत है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार इस विषय को संज्ञान में लेते हुए पीने के पानी की उचित व्यवस्था करे। पिछले सैशन में राज्यपाल अभिभाषण में मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का जिक्र किया गया था। मेरे पास इसकी कॉपी है लेकिन इस सैशन में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पेश किया है उसमें मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का कहीं जिक्र नहीं है। (विघ्न) हाँ, मेवात का जिक्र जरूर है।

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, राज्यपाल अभिभाषण में मेवात की बात आई है। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्षा महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की उस लाइन का भी गवर्नर एड्रेस में जिक्र नहीं है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद में घोषणा की थी कि नूंह को गुड़गांव से जोड़ा जाएगा उसका भी जिक्र नहीं है। यह घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी। (विघ्न)

मुख्यमंत्री (मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदया, जिस घोषणा की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं वह केंद्रीय बजट का विषय है।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, यहां मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की बात आई है। मेवात विकास बोर्ड की 6 सालों के बाद पिछले साल मीटिंग हुई थी लेकिन उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। पिछले वर्ष 29 करोड़ रूपये का बजट था। 29 करोड़ में से 14-15 करोड़ रूपये तनख्वाह के थे जो विद्यालयों इत्यादि को दिए गए थे। मेवात विकास बोर्ड जब बना था उसका ऐसा हाल नहीं था जैसा अब हो चुका है। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेवात विकास बोर्ड का जिक्र होना चाहिए था। इस गवर्नर एड्रैस में बहुत जगह रेलगाड़ी की बात आई है। कहीं पर मैट्रो रेलगाड़ी की बात आई है, कहीं पर रेल लाइन की बात आई है लेकिन कहीं पर भी हमारे मेवात जिले की जो सबसे पुरानी मांग थी कि गुड़गांव से अलवर को वाया नूंह रेलवे लाइन से जोड़ा जाए और इसके लिए हर बार सर्वे करने के लिए कहा जाता है। हमारी उस मांग को पूरा नहीं किया गया है। सन् 1973-74 में जब चौधरी तैयब हुसैन खां गुड़गांव से पार्लियामैंट के मैम्बर थे तब यह सर्वे किया गया था। आज भी वह केवल सर्वे ही है। हर साल कहा जाता है कि इस वर्ष लाइन शुरू हो जाएगी। हमारे क्षेत्र के साथ भद्दा मजाक किया जाता है। माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जब वर्ष 2009 में गुड़गांव से लोक सभा का इलैक्शन लड़ रहे थे तो इस रेल लाइन को बिछाने का वायदा किया गया था। इस साल भी हमसे रेलवे लाइन का और पैसेंजर ट्रेन चलाने का वायदा किया गया है। जब श्री आफताब अहमद मेवात से पूर्व मंत्री थे तो उस वर्ष बजट में रेलवे लाइन बिछाने के लिए कहा गया था। वर्ष 2014-15 में उन्होंने रेल की एक झांकी बनाई, रेल की सीटी बजाई और उसमें बैठकर वे फिरोजपुर-झिरका तक गए। आज तक हमने मेवात में रेल गाड़ी चलना तो दूर रेलवे विभाग की गाड़ी तक नहीं देखी। हमने तो वहां रेलवे की झण्डी तक नहीं देखी। इस वाक्या के जरिये हमारे साथ भद्दा मजाक किया गया है। मेवात जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र था पिछले 10-11 वर्षों में वह और अधिक पिछड़ गया है। उपाध्यक्ष महोदया, आज मेडिकल कॉलेज का बहुत जिक्र हुआ है। मैंने स्पीकर साहब से सप्लीमैंट्री की परमिशन भी मांगी थी। आज सदन में विकास, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग की बहुत बात हुई है।

हरियाणा में कुल 21 जिले हैं। मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेवात जिले का नाम स्वास्थ्य विभाग की डायरी में नहीं है। मेवात को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वर्ष 2005 में जिला बनाया था। मेवात को जिला बने हुए 11 वर्ष हो गए हैं लेकिन आज तक वहां न तो कार्डियोलोजिस्ट है, न गाइनाकोलोजिस्ट है, न रेडियोलोजिस्ट है और न ही कोई एम.बी.बी.एस. तथा एम.डी. मेडिसन डॉक्टर है। **(इस समय अध्यक्ष चेयर पर आसीन हुए।)** सरकार वैसे तो "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का नारा देती है परंतु मेवात जिले में आज तक किसी गायनाकोलोजिस्ट की नियुक्ति नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मेवात के लोग पिछड़ेपन का रोना रोते हैं। सरकार के सबसे ज्यादा विकास की बात करने वाले मंत्री श्री अनिल विज ने मेवात में गायनाकोलोजिस्ट की भी नियुक्ति नहीं की है। ऐसे में महिलाओं का विकास कैसे होगा और हम महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख पाएंगे और कैसे हमारे बच्चे अच्छा पढ़-लिख पाएंगे। मैंने मेडिकल कॉलेज की बात आपके संज्ञान में लानी चाही थी। अध्यक्ष महोदय, वहां के मेडिकल कॉलेज का बहुत बुरा हाल है। अनिल विज जी कह रहे थे कि गुटके पर प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे यहां सारे हॉस्पिटल में गुटके के रैपर्ज की गंदगी जगह जगह पड़ी हुई है। हॉस्पिटल की लिफ्टें खराब पड़ी हुई हैं। लिफ्ट के आगे इतना बड़ा गड्ढा है कि कोई बच्चा गिर जाए तो उसमें फंस जाए। इस हॉस्पिटल की एक लिफ्ट तो चल ही नहीं रही। एन.बी.सी.सी. की तरफ से इसका अभी कम्पलीशन भी नहीं हुआ। इस हॉस्पिटल की छतों की हालत खराब है, सीलिंग टूटी पड़ी हैं और बाथरूम्ज का हाल बहुत खराब है। मंत्री जी स्वास्थ्य की बात करते हैं इसलिए मैं उनको बताना चाहूंगा कि जिन पोलीबैग्स में मेडिकल वेस्ट जाता है वे बैग्स मैडीकल कॉलेज और होस्पिटल के बीच पड़े रहते हैं जिसके कारण वहां कुते भौंकते रहते हैं। इसकी कम्पलीशन नहीं हुई और पेमैंट के लिए एन.बी.सी.सी. के साथ झगड़ा चल रहा है। इसके लिए जो 1000 करोड़ रूपया आया है उसकी जांच करवाई जानी चाहिए। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री आफताब अहमद ने आज के डायरैक्टर संसार चंद शर्मा के साथ मिलकर सैंकड़ों करोड़ रूपये का घपला किया है। उन्होंने एन.बी.सी.सी. के छोटे कंट्रैक्टर्ज से पैसा खाया है। मेरे पास इस बारे सारे लैटर्ज हैं। इसका कोई भी काम कम्पलीट नहीं हुआ है। ओ.टी. के ए.सी. खराब पड़े हैं। वहां न तो पानी की व्यवस्था है और न ही लाइनें डाली गई हैं। बिजली की जो लाइनें डाली गई है उनको कवर नहीं किया गया है बल्कि उनके ऊपर लैंटर वाली रोड़ी डाल दी गई है। हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव जी मेडिकल कॉलेज में गए थे और उन्होंने खुद देखा था कि मेडिकल कॉलेज की मैस में जहां खाना बन रहा था वहां ऊपर से सीवरेज का पानी टपक रहा था और नीचे बालटी रखी हुई थी जिसकी जिला उपायुक्त ने वीडियो भी बनाई थी।

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आप 5 मिनट में वाइंड अप करें।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय,स्वास्थ्य मंत्री नूंह तक गए लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में आज तक नहीं गए इसलिए इसका संज्ञान मुख्यमंत्री महोदय को लेना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय को मेडिकल कॉलेज का दौरा जरूर करना चाहिए तथा वहां कई सौ करोड़ रूपयों का जो घोटाला हुआ है उसकी जांच के आदेश इसी सदन में देने चाहिएं। अध्यक्ष महोदय, लोगों की सेहत के साथ वहां खिलवाड़ हो रहा है। पिछले बजट सत्र में गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन बिल आया था और इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी ने सर्वसम्मति से उसका समर्थन किया

[श्री जाकिर हुसैन]

था। सबको इसकी चिंता थी लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक मेवात जिले में गौवंश के संरक्षण के लिए कोई अभ्यारण्य नहीं बना। किसी गौशाला में गऊओं को नहीं रखा जाता और न ही उनके लिए कोई मेडिकल सुविधा है। गोशालाओं में डाक्टर्ज नहीं हैं और आज गऊएं कुपोषण का शिकार होकर रोड पर एक्सीडैंट्स से मर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि मैंने पीछे भी निवेदन किया था कि बंदर भी हनुमान जी का रूप होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मोरनी यहां से ज्यादा दूरी पर नहीं है और आप सबने देखा होगा कि वहां बंदर केले के छिलके खाने पर मजबूर हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए भी कोई अभ्यारण्य बनना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि यह काम सवा साल में भी नहीं हो पाया। पिछले बहुत सालों से बी.पी.एल. कार्ड नहीं बने। जब भी लोग बी.पी.एल. कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि इसका सर्वे होगा। पिछली कांग्रेस सरकार में बी.पी.एल. कार्ड के मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। मैंने आंखों से देखा है जब 2009 में मैने लोकसभा का इलैक्शन लड़ा था तो मैं रिवाड़ी की तरफ वोट मांगने गया था। मैंने देखा था कि आलीशान कोठियों के सामने पुराने टूटे फूटे फोर व्हीलर्स खड़े थे। मैंने पूछा कि इतनी आलीशान कोठी के सामने ये फोर व्हीलर्स क्यों खड़े हैं तो लोगों ने कहा कि इन घरों के आगे क्या लिखा हुआ है। मैंने वहां देखा तो लिखा हुआ था बी.पी.एल. परिवार। लोगों ने पैसे देकर अपने आप को बी.पी.एल. परिवार में शामिल करवाया था। केन्द्र सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि घर के आगे बी.पी.एल. परिवार लिख दिया जाए। लोगों ने फिर नाम कटवाने के लिए भी पैसे दिए। मैं कहना चाहूंगा कि इस मामले में बहुत बड़ी धांधली हुई है इसलिए बी.पी.एल. का दोबारा सर्वे होना चाहिए। यह बात केवल मेवात की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। (विघ्न) मैं सिंचाई के बारे में केवल यह अर्ज करना चाहूंगा कि मेवात फीडर कैनाल को बनाने बारे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया और यह कैनाल बननी बहुत जरूरी है। इस कैनाल के लिए 600 क्यूसिक पानी ईयरमार्कड है जिससे पूरे मेवात को पानी मिल सकता है। मेरे प्रश्न के जवाब में सिंचाई मंत्री धनखड़ साहब ने इसी सदन में मुझे आश्वासन दिया था कि मेवात फीडर कैनाल बनवायेंगे लेकिन इसका राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। ये छोटी-छोटी बातें हैं इनकी तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और जो बातें रह गई हैं, उनके बारे में मैं बजट पर बोलते हुए जिक्र कर लूंगा। धन्यवाद।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता (पंचकुला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का एक विजन डाक्यूमैंट होता है और जो योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं या की जानी हैं उन योजनाओं के बारे में पूरा विस्तृत विवरण होता है। हरियाणा 1 नवम्बर, 1966 को अलग राज्य बना था और इसको बने लगभग 50 वर्ष हो गये हैं। यह साल हमारी स्वर्ण जयंती का साल है और इस साल में जो एतिहासिक निर्णय आदरणीय मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार ने लिए हैं वे अपने आप में इस बात का सबूत हैं कि हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास के नारे को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" और उसी को चरितार्थ करते हुए जो आज पूरे

प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं और उनमें मैं समझता हूं सबसे ज्यादा विकास के काम हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया वह पढ़ी लिखी पंचायतों के लिए बिल लाने का है कि हमारी पंचायतें पढ़ी लिखी हों ताकि जो प्रतिनिधि चुनकर आयें वे अपने गांव के विकास की बात कर सकें और गांव में आने वाले पैसे को भी ठीक प्रकार से खर्च करने के बारे में सोच सकें। हालांकि कुछ दलों ने उस बिल का विरोध किया था और सुप्रीम कोर्ट तक लोग गये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि सरकार ठीक निर्णय ले रही है। आज उसी का परिणाम है कि जो पंचायतें चुनकर आई हैं, जिला परिषद के सदस्य चुनकर आए हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य चुनकर आए हैं वे सभी युवा और पढ़े लिखे हैं। वे सोच सकते हैं कि गांव का विकास किस प्रकार हो सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण ही आज गांव में खुशहाली का वातावरण बना है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और मुबारिकवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस निर्णय को दूसरे राज्य भी फोलो करने के लिए तैयार हैं। जहां तक विकास की बात है हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए सभी जिलों का समान विकास किया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जायेगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि फलां जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जायेगा और फलां जिले में नहीं खोला जायेगा। इसी तरह से महिला पुलिस थाने भी सरकार ने हर जिले में खोलने का काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया यह वाकई बहुत सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं' को एक आंदोलन कहूंगा क्योंकि इस आंदोलन की शुरूआत हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पानीपत से की थी। इस बात की बहुत आवश्यकता थी क्योंकि लिंगानुपात बहुत गिर रहा था और जिस प्रकार से लड़कियों को घर में कैद करके रखा जाता था यह बेटियों को बचाने की एक शुरूआत थी कि बेटियों को किस प्रकार से बचाया जाये और लिंगानुपात में किस प्रकार से सुधार किया जाये। और आज यह उसी का परिणाम है जो हरियाणा प्रदेश में बेटियों के मामले में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। आज लिंगानुपात में पूरे देश में हरियाणा नम्बर एक की पोजीशन पर है। इस बात के लिए आज हरियाणा को एक पुरस्कार मिला है कि हरियाणा प्रदेश में बेटियों की संख्या निश्चित हुई है। हरियाणा प्रदेश में बेटियों को पढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां पर भी बेटियां पढ़ना चाहें अर्थात बेटियां जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहें उनको वहां पर ज़रूर पढ़ने का मौका मिले। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा कि बेटियों के पढ़ने के स्कूल गांवों में ज्यादा से ज्यादा खोले जायें। हमारी सरकार द्वारा अभी हाल ही में 7 व 8 मार्च को गुड़गांव में ग्लोबल इंवैस्टर्ज सम्मिट का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूं कि इस इंवैस्टर्ज सम्मिट को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा षड़यंत्र रचा गया था अर्थात वह इंवैस्टर्ज सम्मिट सफल न हो इसको ध्यान में रख कर एक षड़यंत्र को कार्यरूप दिया गया। मैं समझता हूं कि इस इंवैस्टर्ज सम्मिट के बड़े चौकाने वाले परिणाम सामने आये हैं जिनका हरियाणा प्रदेश की चहुंमुखी प्रगति पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। लगभग 398 पार्टीसिपेंट्स ने इस इंवैस्टर्ज सम्मिट में हिस्सा लिया जिनके साथ हरियाणा सरकार के पांच लाख चौरासी हज़ार करोड़ रूपये के एम.ओ.यूज. साईन हुए हैं। मैं समझता हूं कि इससे हरियाणा में विकास की एक नई गंगा बहने का अवसर प्रदान हुआ है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश बड़ी तेज़ गति से चहुंमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार एक औद्योगिक नीति लेकर आई है

[श्री ज्ञान चंद गुप्ता]

जिसके अंदर ए, बी, सी व डी विभिन्न कैटेगरीज़ तय की गई हैं। जहां-जहां पर भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां पर नई उद्योग नीति के तहत उद्योगों की स्थापना की जायेगी। इससे हमारी सरकार ने जो नारा दिया है कि "सबका साथ, सबका विकास" इसको सार्थक किया जायेगा। जिस भी जिले में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के उद्योगों की स्थापना की जायेगी और नई उद्योग नीति के तहत ही उन उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें मुहैया करवाई जायेंगी। इसके साथ ही साथ नई उद्योग नीति के तहत ही वहां पर उद्योगों को विभिन्न प्रकार की रियायतें मिलेंगी चाहे वह टैक्स में हो, चाहे वह बिजली के रेट्स में हो और चाहे वह भूमि की स्टैम्प ड्यूटी के रूप में हो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने निर्णय किये हैं वे सभी के लिए किए हैं। आज किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हमारी सरकार ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरैंस रखेंगे। अपने कहे के मुताबिक ही हमारी सरकार ने यह सब करके दिखाया। हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले जब तहसील में चाहे कोई किसान अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता था या फिर कोई व्यक्ति अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील में जाता था तो उस समय उसके मन के अंदर यह दुविधा रहती थी कि वहां पर उसके काम के लिए पता नहीं 10,000/- रूपये देने पड़ेंगे या फिर 20,000/- रूपये देने पड़ेंगे लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ई-रजिस्ट्री की प्रणाली शुरू की है इससे तहसीलों में भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है। आज कोई भी व्यक्ति तहसील में जाकर रजिस्ट्री करवा सकता है और उसे उसकी रजिस्ट्री उसी दिन मिले, इस बात की भी गारंटी की गई है। मैं समझता हूं कि यह हमारी सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि सरकारी कार्यों में इतनी ट्रांसपैरेंसी आई है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत 105 प्रकार की ई-सेवायें शुरू की गई हैं। जिनके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना लाईसैंस बनवा सकते हैं और वहां पर जाकर स्टैम्प पेपर खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि न जाने कितनी सेवाएं हमारी सरकार के द्वारा ई-गवर्नैंस के तहत शुरू की गई हैं। ऐसा करने से काम में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, काम में ट्रांसपैरेंसी आने के साथ-साथ काम में तीव्रता भी आई है। ऐसा होने से लोगों के काम जल्दी होने लगे हैं। इससे पहले यह होता था कि अगर कोई अपना लाईसैंस बनवाने के लिए तहसील में जाता था तो वहां पर दलाल खड़े हुए होते थे लेकिन यह सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों का ही परिणाम है कि हमारी तहसीलों को दलालों के चंगुल से मुक्ति मिली है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पंचकुला के लिए बहुत सारी चीजें प्रस्तावित की गई हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पंचकुला शहर का कायाकल्प करने के लिए और शहरी बदलाव अटल मिशन में पंचकुला को शामिल किया है उसका उद्देश्य सभी को नल से पीने का पानी और सभी को सीवरेज कनैकशन और सभी को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमैंट मिले। यह योजना 20 जिलों में शुरू की गई है और पंचकुला को भी इसमें शामिल किया गया है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अभी पंचकुला में 300 बैड का हॉस्पिटल तैयार हो गया है उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से आज स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि पंचकुला के लिए एक गवर्नमैंट कॉलेज और एक

मेडिकल कॉलेज शीघ्र शुरू होने जा रहा है उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से पंचकुला के सामान्य अस्पताल में इसी साल से एम.आर.आई. और सी.टी. स्कैन की सुविधा शुरू होने जा रही है तथा कुछ ही दिनों में हीमोडायलिसिस की सुविधा भी शुरू होने जा रही है। मैं समझता हूँ कि पिछले 50 साल में जो काम नहीं हो सके थे वही काम हमारी सरकार ने एक डेढ साल में शुरू करके दिखाए हैं। ये जो सुविधाएं वहाँ पर शुरू हुई हैं उससे आम आदमी को बहुत फायदा हुआ है। सरकार की पंचकुला में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने की योजना है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मोरनी की पहाड़ियों में 25 हजार औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट की योजना है जिससे इस क्षेत्र का विकास होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह भी विनती करना चाहता हूँ कि मोरनी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर वे अपार सम्भावनाएं हैं जिनके तहत मोरनी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर already existing infrastructure है। वहाँ पर बड़े-बड़े होटल हैं, सरकारी होटल हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमैंट के रैस्टहाउस हैं उनका यूटीलाईजेशन किया जा सकता है। अगर उस इन्फ्रास्ट्रक्चर का ठीक ढंग से यूटीलाईजेशन होगा तो सरकार को पैसा भी मिलेगा और पर्यटन को बढावा भी मिलेगा। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग 73 जो कि बरवाला से जगाधरी तक पहले ही फोरलेन सैंक्शन हो चुका था तथा अब बरवाला से पंचकुला के लिए भी उसके टैंडर हो चुके हैं, यह भी पंचकुलावासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसके बनने से पंचकुला से जगाधरी तक तथा उससे आगे जाने वाले लोगों को फायदा होगा तथा फोरलेन बनने से जो सड़क दुर्घटनाएं होती थी उनमें कमी आयेगी। पंचकुला के सैक्टर 26 में सैन्ट्रल पॉलिटैक्निक का मल्टी स्किल्ड सैन्टर खोलने की घोषणा भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में की गई है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि पंचकुला में स्मार्ट सिटी बनने की भी सभी विशेषताएं हैं। चण्डीगढ़ के बाद अगर कोई शहर प्लांड सिटी के रूप में डिवैल्प हुआ है तो वह पंचकुला है। 95 प्रतिशत पंचकुला प्लांड सिटी के रूप में डिवैल्प हुआ है। वहाँ पर 24 घंटे बिजली, पानी और सड़कें उपलब्ध हैं। वहाँ पर हर प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाएं अवेलेबल हैं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इसको स्मार्ट सिटी के दौर से बाहर रखा गया उसके पीछे एक षड़यंत्र है। वहां कॉरपोरेशन में कांग्रेस पार्टी के लोगों का कब्जा है और उन्होंने इस शहर को स्मार्ट सिटी में आने के लिए जो एक मीटिंग होनी चाहिए थी वह मीटिंग तक नहीं की। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी संज्ञान लिया जाना चाहिए और उसकी इंकवायरी करके उसमें कोई भी दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या मक्खियों की है। अभी कुछ सदस्य व्हाइट फलाई की बात कर रहे थे वे फसलों में लगने वाली सफेद मक्खी की बात कर रहे थे। हमारे पंचकूला में तो घरेलू मक्खियों की भरमार रहती है जो आदमी को बैठने ही नहीं देती। पंचकूला के जितने भी गांव हैं आप उन गांवों में जाकर देखिए अगर उनमें कोई शादी हो तो मक्खियाँ इतना भयंकर रूप से हमला करती हैं कि आदमी को वहां से उठकर जाना पड़ता है। इसकी वजह से लोगों के रिश्ते व शादियां होनी बन्द हो गई हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मैंने पहले भी सरकार से प्रार्थना की थी कि जहां पर यह मक्खियों की समस्या ज्यादा है उसको

[श्री ज्ञान चंद गुप्ता]

रोकने के प्रयास किये जाने बहुत जरूरी हैं। इसके साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि पंचकूला प्रशासन में आपस में तालमेल की कमी है। जहां तक सड़कों की बात है तो कुछ सड़कें हुडा के अधीन हैं, कुछ सड़कें नगर निगम के अधीन हैं और कुछ सड़कें हाऊसिंग बोर्ड के अधीन आती हैं। वहां के लोगों को 50-50 साल हो गये यह पता नहीं चला कि हमारी सड़क किसके अधीन आती है। इसलिए पंचकुला में पंचकुला डिवेल्पमैंट बोर्ड बनना चाहिए ताकि आपस में तालमेल हो सके। मैं समझता हूं कि जब तक डी.सी. का, हुडा का, नगर निगम का और हाऊसिंग बोर्ड का आपस में तालमेल नहीं होगी तब तक पंचकूला का विकास ठीक ढ़ग से नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष : ज्ञान चन्द जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। आपको डबल टाईम मिल गया है।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. बनवारी लाल(बावल)(अनु.जा.) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे गवर्नर एड्रैस पर बोलने का मौका दिया। मैं राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि जो बातें राज्यपाल के अभिभाषण में कही गई हैं वह प्रदेश को नई ऊंचाईयों तक ले जाएंगी। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जैसे अभी मेरे से पहले बहुत वक्ताओं ने बताया कि माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब से बनी है और सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैंसले किये हैं वह हरियाणा की जनता के विकास के लिए और सरकार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, नये-नये स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे जिनमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ-साथ सरकार ने गाय और गीता के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है इसी तरह से अभी रिसैंटली हैपनिंग हरियाणा सम्मिट का आयोजन करवा कर यह संदेश दिया है कि उद्यौगिक विकास के लिए सरकार कितनी चिन्तित है। सरकार ने किसानों को भारी मुआवजा देकर किसान हितेषी होने का भी एक सबूत दिया है। अब मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मेरे हल्के की कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पिछले 10 सालों से मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कोई कार्य नहीं करवाया। लेकिन जब से श्री मनोहर लाल जी की सरकार बनी है तब से हमारे क्षेत्र में विकास की बयार चली है। 4 जुलाई 2015 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बावल में एक रैली में बहुत सी घोषणाएं की थी। चौधरी चरण सिंह रिसर्च सैंटर बावल में बी.एस.सी. की एग्रीकल्चर विषय की कक्षाएं पिछले 15-20 सालों से बन्द पड़ी थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए घोषणा की थी कि इसी सैशन से यह कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और उसी सैशन से ही हमारी बी.एस.सी. एग्रीकल्चर विषय की कक्षाएं शुरू हो गई। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय श्री ओमप्रकाश धनखड़ जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह कक्षाएं शुरू की जिससे हमारे इलाके के बच्चों को कृषि का ज्ञान मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह रिसर्च

सैंटर, बावल के अधीन कृषि महाविद्यालय में जो आपने 50 सीटें दी है, इन 50 सीटों को देने के लिए आपका धन्यवाद लेकिन एक निवेदन यह भी है कि इस कृषि महाविद्यालय की बिल्डिंग और हॉस्टल के लिए बजट भी दिया जाये ताकि यह भविष्य में भी सुचारू रूप से चलता रहे अन्यथा यह बंद होने के कगार पर आ सकता है। ग्राम गोबिन्द पुरी में अंडर पास की मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। इस गांव के लोगों को सड़क पार करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अंडर पास न होने की वजह से काफी जान-माल व पशुओं का भी नुकसान हुआ करता था। परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य के लिए 14 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कर गाँव वालों को होने वाले जान-माल व अन्य नुकसान की समस्या से निजात दिलाई है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बावल शहर में जाम की समस्या बहुत ज्यादा है। यहां की फाटक न. 69 पर गाड़ियों का काफी बड़ी संख्या में आवागमन लगा रहता है जिसकी वजह से फाटक तकरीबन बंद ही रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बावल रैली में यह घोषणा की थी कि यहां पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री जी ने आर.ओ.बी. के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृत कर दिये जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में पीने के पानी की बहुत कमी है और जो पानी उपलब्ध है वह बहुत खारा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने बावल रैली के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कैनाल बेस्ड वाटर स्कीम की मांग की थी, जिसके लिए सरकार ने 93 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत कर इस परियोजना को स्वीकार कर लिया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे हल्के में कुछेक गांव और हैं जिनमें खारे पानी की समस्या है। नांदा ग्रुप के नाम से एक प्रोजैक्ट सैनेटरी बोर्ड के पास पैंडिंग है उस प्रोजैक्ट को भी स्वीकृत किया जाये ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस में शिक्षा के बारे में जिक्र किया गया है। शिक्षा सस्ती हो, सुलभ हो और गुणात्मक हो यह हमारी सरकार का प्रयास है। सरकार 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' को बढ़ावा दे रही है। इसी के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मेरे हल्के के जड़थल, टाकड़ी, बासदूधा व राजगढ़ के स्कूलों को अपग्रेड करके बारहवीं तक का किया जाए ताकि लड़कियों को घर से ज्यादा दूर स्कूल ना जाना पड़े क्योंकि सभी जानते हैं कि आजकल माता-पिता को बेटियों की चिंता ज्यादा रहती है। शिक्षा मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि बावल में एक महिला कॉलेज भी खोला जाए जिसके लिए जमीन पंचायत से दिलाई जायेगी। एक महिला कालेज, पाली में स्थित है जोकि प्राईवेट बिल्डिंग में चलाया जा रहा है इसका भवन भी बनाया जाये और उसमें स्टॉफ भी नियुक्त किया जाए ताकि बच्चों को सुविधा हो सके। इसके लिए जमीन भी पंचायत से दिलवा दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर है जिसके साथ किसी भी कॉलेज को नहीं जोड़ा गया है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी से मेरे क्षेत्र को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के साथ दक्षिणी हरियाणा के महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल तथा मेवात आदि जिलों के सभी कॉलेजों को जोड़ा जाए ताकि दक्षिणी हरियाणा के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़े। इसके साथ ही इस यूनिवर्सिटी की यू.जी.सी. के तहत ग्रॉंट भी बढ़ाई जाये और सबजैक्ट भी बढ़ाये जायें ताकि यह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से काम कर सके। अध्यक्ष महोदय, बावल रैली में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ट्रामा सैंटर की भी मांग रखी थी।

[डॉ. बनवारी लाल]

दिल्ली से लेकर जयपुर तक कोई भी ट्रामा सैंटर नहीं है। उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने बावल में ट्रामा सैंटर खोलने की घोषणा की थी। उसी घोषणा के मद्देनज़र मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ कि बावल में अविलम्ब ट्रामा सैंटर खोला जाये ताकि दुर्घटना में घायल लोगों की जान बचाई जा सके। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र के भाड़ावास गांव में एक पी.एच.सी. पिछले 15-20 साल से एक धर्मशाला में चल रही है। इस पी.एच.सी. के लिए संबंधित ग्राम पंचायत ने स्वास्थ्य विभाग को जमीन दे दी है अत: मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पी.एच.सी. को अलग बिल्डिंग में बनाया जाए ताकि लोगों को फायदा हो सके। हमारे प्रदेश में डॉक्टर्ज तथा पैरा मैडीकल स्टॉफ की बहुत कमी है और स्वास्थ्य एक ऐसा महत्वपूर्ण मसला है और कहा भी जाता है कि स्वास्थ्य ही जीवन होता है। यदि आदमी का स्वास्थ्य सही नहीं है तो चाहे कितनी भी सुविधायें हों वह सब बेकार हो जाती हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, बनवारी लाल जी स्वयं भी एक डॉक्टर है, वह भी ईलाज कर सकते हैं। (विघ्न)

डॉ0 बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक-दो का ईलाज तो ठीक है लेकिन सभी लोगों का ईलाज मुझ अकेले से थोड़े ही किया जा सकता है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, बावल रैली के ही दौरान मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष गाँव मनेठी में एम्स खोलने की डिमांड रखी थी जिसका जिक्र गवर्नर एड्रैस में किया गया है। इसके लिए दक्षिण हरियाणा के सभी विधायकों ने लिखित रूप में सहमति जताई थी, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ-साथ माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय केन्द्र की सरकार के संपर्क में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि इस परियोजाना को जल्दी से जल्दी लागू करें ताकि हरियाणा के लोगों के साथ-साथ राजस्थान के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उद्योग और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बावल एक औद्योगिक हब है, इसलिए यहां पर पॉलिटैक्नीक कॉलेज खोला जायें ताकि यहां के बच्चों को इस कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद इन उद्योगों में रोजगार मिल सके। इससे बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने धामलवास में मल्टी स्किल सैन्टर खोलने का जिक्र किया हुआ है, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बसें बहुत कम है, जिससे लोगों को और बच्चों को खासकर लड़कियों को स्कूलों में आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र के परिवहन बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाई जाये। अध्यक्ष महोदय, पहले दक्षिण हरियाणा के विकास में भेदभाव किया जाता था लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में 'सबका साथ सबका विकास' नारे के अनुरूप दक्षिण हरियाणा में बहुत विकास के काम हो रहे हैं। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला (डबवाली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया है। खासकर 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना को सरकार ने बहुत बढ़ाचढ़ा कर पेश किया है। प्रदेश सरकार के डेढ साल के कार्यकाल के दौरान नारे देने के सिवाय आम आदमी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में लिंगानुपात सुधार का जिक्र किया है, जिसे सरकार की उपलब्धि बताई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहने से पहले दो लाइन बोलना चाहूँगी।

"चुप रहना भी तहजीब है संस्कारों की,
लेकिन कुछ लोग हमें बेजुबां समझ लेते हैं"

अध्यक्ष महोदय, आज भी हमारा समाज पुरूष प्रधान कहलाता है। आए दिन महिलाओं पर घरेलू हिंसा, गैंग बलात्कार, पीटना, अपशब्द कहना और रोक-टोक जैसी घटनाएं आम होती रहती हैं, क्या यही महिला सशक्तिकरण की परिभाषा है? महिलाओं के कम शिक्षित होने की वजह से आए दिन उनके ऊपर इस प्रकार के जुल्म होते रहते हैं। महिलाओं का बेरोजगार होना भी काफी हद तक इसमें भागीदार है। तमाम महिलाएं वर्ष 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम से अनभिज्ञ हैं। यह अधिनियम 26 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ था। इस अधिनियम में महिलाओं को अपशब्द कहना, मारपीट करना, प्रताड़ित करना, रोक-टोक जैसी घटनाएं होने पर दण्डनीय अपराध का प्रावधान है। यहां भी महिलाएं अशिक्षित होने की वजह से कानून को समझ नहीं पाती है जिससे आए दिन ऐसी घिनौनी घटनाओं से प्रताड़ित होना पड़ता है। अध्यक्ष महादेय, महिलाओं पर घरेलू हिंसा रोकने के लिए और शिक्षित करने के लिए संरक्षण कानून बनाना चाहिए। महिलाओं के लिए अलग से अदालतों का गठन होना चाहिए जहां पर उनकी सुनवाई हो और उचित न्याय मिले। हरियाणा में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि यह आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाये ताकि महिलाओं की रक्षा हो सके। स्वरोजगार ग्रामीण महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण है, इससे महिलाओं में आत्मविश्वास जगेगा और एक परिवर्तन आयेगा। सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। दुनिया में स्त्री को पुरूष के बराबर जीने का हक है। परंतु दहलीज के अंदर महिलाओं के हालात आज भी ठीक नहीं है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 6 पुरूष आज भी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। हमारे देश में अशिक्षित होने के कारण दो-तिहाई महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। जो महिलाएं शिक्षित हैं और कामकाजी हैं वे हिंसा की इतनी ज्यादा शिकार नहीं होती। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा और देखा होगा कि बहादुरगढ़ की एक महिला प्रसव के लिए अस्पताल में गई थी। वहां बच्चे को जन्म देते ही उसके साथ बलात्कार कर दिया गया। यह घटना हॉस्पिटल में जो सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए थे उसमें कैद हुई है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है ? क्या यही बेटी बचाओ का अभियान है। क्या यही सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है ? सरकार मूकदर्शक बनकर यह सब देखती रही। रोहतक शहर के जी.आर.पी. थाने में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की पुलिस ने सरेआम पिटाई कर दी। उस पर चोरी का आरोप था। जब महिला के लड़के ने पुलिस वालों को कहा कि यह मेरी माँ है और मैंने इन्हें पैसे दिए थे तो फिर पुलिसकर्मियों ने उस महिला से माफी मांगी। क्या यही महिला सशक्तिकरण है ? अध्यक्ष जी, अभी लोक सभा में पंजाब के मोगा कांड की भी गूंज सुनाई दी है। उसमें एक महिला पर हिंसा का आरोप लगा था। उसके साथ बलात्कार किया गया था। यह मुद्दा बहुत जोर-शोर से उठा था। उस परिवार की आवाज

[श्रीमती नैना सिंह चौटाला]

दबाने के लिए पंजाब सरकार ने 25-30 लाख रूपये उस परिवार को मुआवजे के रूप में दिए। यह मुआवजा राशि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मुआवजा है। आज तक किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा नहीं दिया है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है ? किसी महिला की आवाज पैसे से नहीं दबाई जा सकती। आप इन चीजों के लिए जितना ज्यादा मुआवजा ऑफर करेंगे उतने ही अत्याचार बढ़ेंगे। कोई भी पुरूष अपनी माँ के पेट से पापी और हिंसक तथा बलात्कारी पैदा नहीं होता। पुरूष को हिंसक और पापी बनाने के लिए और वारदात करने के लिए भी हमारा समाज ही जिम्मेदार है। आए दिन नई-नई चीजें, जांच कमेटियां बैठा दी जाती हैं जो फैसले लेने में इतनी देर लगा देती हैं कि महिलाओं का हौसला ही टूट जाता है। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते-काटते महिलाएं थककर टूट जाती हैं और आए दिन निर्भया जैसे कांड होते हैं। भाजपा सरकार को कानून में ऐसे अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए और उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध करने की सोचकर बलात्कारी की रूह कांप जाए और उसे दोबारा करने की बात मन में भी न सोचे। एक महिला के रूप में "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" महिला सशक्तिकरण तभी सफल होगा जब हम महिलाओं, बुजुर्ग माताओं और बहन-बेटियों का मान-सम्मान करेंगे, उनको अच्छे और बेहतर शिक्षा संस्थान देंगे तथा उनकी सुरक्षा कर सकेंगे। अन्यथा "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" अभियान एक खोखला नारा बनकर रह जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम मनाया गया। इसमें गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को उनके परिवार के साथ राष्ट्र-ध्वज को फहराने के लिए आमंत्रित किया गया तथा उन्हें स्कूल प्रबंधन की मानद सदस्यता भी दी गई थी। इस कार्यक्रम की सभी समुदायों ने सराहना की। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या जिन 6 हजार लड़कियों ने राष्ट्र-ध्वज फहराया है आप उनको नौकरियों में प्राथमिकता देंगे और क्या आप उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां देने का प्रावधान करेंगे ? जब आपने उनको इतना बड़ा मान-सम्मान दिया है तो उनको नौकरी में भी अवसर दिया जाना चाहिए। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) सरकार का जो बजट आएगा मैं उसके लिए आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार का प्रबंध करना चाहिए। हरियाण की उत्तर साइड का तो मुझे नहीं पता है लेकिन सिरसा बेल्ट में जब मैं अपनी कांस्टीच्यूंशी में जाती हूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां पर बेटियां मेरे चारों ओर इकट्ठी होकर कहती हैं कि मैम, हमारे लिए कुछ करो। हम सिर्फ मूकदर्शक बनकर उनकी बातें सुनते हैं। मैंने कल कैबिनेट मंत्री श्रीमती कविता जैन जी से भी आग्रह किया था कि हमारी लड़कियां सिलाई-सैंटर के लिए हमसे बार-बार आग्रह करती हैं। (विघ्न) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि लड़कियों के लिए कुछ अच्छी स्कीम्ज निकालें। आपको भगवान ने गोल्डन चांस दिया है। मैं महिला होने के नाते इसके लिये आपसे अनुरोध करती हूं।

बैठक का समय बढ़ाना

14:00 बजे **श्री अध्यक्ष** : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्रीमती नैना चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि अहमदपुर और दारेवाला गांवों में लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है। हम जब गांव में जाते हैं तो लड़कियां हमें कहती हैं कि हमारे यहां स्कूल खुलवा दो इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे अहमदपुर गांव और दारेवाला दोनों गांवों में स्कूल खुलवा दें। सिरसा जिला लिंगानुपात के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में अव्वल आया है इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि क्या हमें अव्वल आने का कोई प्राइज नहीं देंगे ? क्या हमारे इलाके में महिला स्कूल, महिला कॉलेज या महिला मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान करेंगें क्योंकि जो जिला अव्वल आया है उसको कोई प्राइज तो मिलना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि यदि हमारे जिले में कोई मेडिकल कॉलेज खोला जाता है तो हमारे यहां शेरगढ़ के पास 40 एकड़ जमीन उपलब्ध है। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने इस जमीन पर नवोदय स्कूल खोलने के बारे में सोचा था। यह जमीन पंचायत की है लेकिन इसको आज तक कोई नवोदय विद्यालय नहीं मिला। अगर इस जमीन पर लड़कियों के लिए कोई मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाता है तो हमारे सिरसा जिले के लोग सरकार के अहसानमंद होंगे। अध्यक्ष महोदय, चौटाला गांव का जो हॉस्पिटल है उसकी बिल्डिंग की हालत बहुत ही जर्जर है। किसी महिला को प्रसव तो दूर अगर बुखार चैक करवाना होता है तो भी उसे भटिंडा या डबवाली जाना पड़ता है। वहां की बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि हो सकता है कि आज गिर जाए या कल गिर जाए। यह हॉस्पिटल चौधरी देवीलाल जी की देन है। मुझे लगता है कि चौटाला गांव के इस हॉस्पिटल की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी, मेरे ख्याल से आप मुख्यमंत्री बनने के बाद इस हॉस्पिटल में कभी नहीं गए होगे इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप एक बार वहां जाकर जरूर चैक करें कि कैसे वहां पानी गिर रहा है ? इस हॉस्पिटल के भवन निर्माण का कार्य जरूर करवाया जाए। इस हॉस्पिटल में खासकर महिलाओं के लिए डाक्टर्ज भी जरूर लगाए जाएं। अंत में मैं अपनी लिखी कविता पढ़कर सुनाना चाहूंगी-

"कहने को कहीं भी औरत आजाद है,
पर जिंदगी के जिंदादिली के फैसले लेने पर भी लाचार है
मां दुर्गा की भक्ति क्यों नहीं जागती इनमें,
बुरे को बुरा, अच्छे को अच्छा कहने की शक्ति क्यों नहीं आती इनमें।
हर मां का मन्दिर सजा है, पुरूषों की भीड़ से,
पर आदर सम्मान कहां है औरत की तकदीर में,
"पर" लगा दिए उड़ान भरने को,
पर पांव में लोहे की जंजीर है।
हे पुरूषों, काट दो उन जंजीरों को
और समझो इस शक्ति को,

[श्रीमती नैना सिंह चौटाला]

कि इसी मां में आपकी तकदीर है।
कृपा करे, सम्मान दे, मर्द औरत को, अपने जैसा इंसान समझे।
फिर कभी कोई मर्द कर्म ना करे निर्भया कांड जैसा।
हे मां, निर्भया बना दे, हे मां, मुझे शिक्षित बना दे
हे मां, मुझे कामकाजी महिला बना दे।"

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

शिक्षा मंत्री(श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमारी आदरणीय बहन नैना चौटाला जी बहुत अच्छा बोली हैं। वे अपनी भावनाओं को कविता में बोली हैं इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। इन्होंने आदमपुर, तेजा और शेरगढ़ में स्कूल खोलने के बारे में कहा है। हम इनके बारे में एग्जामिन करवा लेंगे और यदि ये तीनों जगह सारे नॉर्म्ज पूरी करती होंगी तो हम इन तीनों जगहों पर अवश्य स्कूल खुलवा देंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आदरणीय बहन ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है। मैं भी इसमें कुछ कहना चाहती हूं। बेटी होने के नाते मैं भी उनके दर्द को समझ सकती हूं। निश्चित रूप से हमारे प्रधान मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे देश की जो आधी आबादी है उसके बारे में सोचते हुए ही यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है और निश्चित रूप से उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। चाहे वह घरेलू हिंसा की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो या शिक्षा की बात हो हर मुद्दे पर हमारी सरकार काम कर रही है। जहां तक बहन ने महिलाओं के स्वरोजगार की बात की है इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि उन्होंने कल भी मेरे से बात की थी और मैंने अपने डायरैक्टर को उनके हल्के के लिए स्वरोजगार की योजनाएं बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त वहां के ए.डी.सी. और पी.ओ. को भी डायरैक्शंज दी जायेंगी कि जो बहनें काम करने के लिए सक्ष्म हैं अगर उनके साथ मिलकर प्रपोजल बनायेंगी तो उसको हम जल्दी परस्यू करेंगे। इस तरह से महिलाओं को आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाने का, समृद्ध बनाने का सपना हम आपस में मिलकर जरूर पूरा करेंगे।

श्री भगवान दास कबीरपंथी(नीलोखेड़ी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 14 मार्च को अपना अभिभाषण सदन में रखा जो कि प्रदेश की खुशहाली और तरक्की का आईना है। सवा साल पहले माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब इस प्रदेश की सत्ता का परिवर्तन हुआ उस समय प्रदेश के हालत बहुत लाचार थे और बुरी तरह से प्रदेश की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी तथा चारों तरफ समस्याओं का अम्बार था। हमारी सरकार आने से पहले प्रदेश में सड़कें टूटी हुई थी, शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था और चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तहसील और जिला कार्यालयों में कोई भी अधिकारी बिना पैसे के जनता का काम नहीं करते थे। ऐसे समय में हमारे मुख्यमंत्री जी को सरकार चलाना बड़ा मुश्किल था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले सवा साल में प्रदेश ने आर्थिक,

सामाजिक और शैक्षणिक यानि हर क्षेत्र में तरक्की की है। इसी तरह से सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी एक ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री हैं और उनका सपना था कि प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो। यही वजह है कि प्रदेश की तहसीलों में ऑन लाईन रजिस्ट्रियां शुरू की गई हैं ताकि आम आदमी और किसानों को रजिस्ट्री करवाने के लिए रिश्वत के पैसे न देने पड़ें। पहले बिना रिश्वत दिए तहसीलों में कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी लेकिन अब ऑन लाईन रजिस्ट्रियां शुरू करने से रिश्वत खत्म हो गई है। जिससे आम जनता और किसानों को बहुत लाभ मिला है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बुढ़ापा पैंशन में भी पिछली सरकार के समय में भयंकर घोटाला था। 3-3 हजार रूपये लेकर 45-50 साल के लोगों की भी पैंशन बना रखी थी। हमारी सरकार आने के बाद बुढ़ापा पैंशन को आधार कार्ड और बैंक से जोड़ने के बाद करोड़ों रूपये का घोटाला सामने आया और सरकार का करोड़ों रूपया बचा है जो कि अब विकास के कार्यों में लग रहा है। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रदेश की परिवहन व्यवस्था अच्छी हो और जिस प्रदेश की सड़कें भी अच्छी हों वह प्रदेश अपने आप ही तरक्की की राह पर तेज़ गति से अग्रसर हो जाता है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय पांच मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : हाँ जी, हाँ जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय पांच मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा(पुनरारम्भ)

श्री भगवान दास कबीरपंथी : स्पीकर सर, हरियाणा में बीते समय में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने न तो प्रदेश की परिवहन व्यवस्था को सुधारने की तरफ ध्यान दिया और न ही प्रदेश की सड़कों की दशा सुधारने की तरफ कोई ध्यान दिया। पिछली सरकारों के समय में प्रदेश की बहुत बुरी हालत थी। आज सदन में सभी माननीय सदस्य बैठे हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश का कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां की सड़कों पर काम न चल रहा हो। हमारी सरकार आने से पहले हरियाणा प्रदेश में लिंगानुपात गड़बड़ाया हुआ था जो कि हमारे प्रदेश पर एक कलंक था। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से इस घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ। इसका परिणाम सामने आने लगा है और आज हमारे हरियाणा प्रदेश में 1000 लड़कों के पीछे 900 लड़कियां हैं। हमारे प्रदेश की इस उपलब्धि के लिए हमारे प्रदेश को भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय से अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। चाहे हमारे प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की बात हो उसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसान भाईयों को बिना किसी भेदभाव के उचित मुआवज़ा दिलवाया। किसान भाईयों को 1092 करोड़ रूपया गेहूं के खराबे के लिए और कपास के खराबे के लिए 967 करोड़ रूपये का मुआवज़ा प्रदान करके मुसीबत की घड़ी में उनका साथ दिया और हौंसला बढ़ाया। इसी प्रकार से चाहे अभी कुछ दिन पहले प्रदेश में जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई थी उनसे हुए नुकसान की बात हो तो भी हमारे

[श्री भगवान दास कबीरपंथी]

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पीड़ितों को बहुत जल्दी राहत दिलवाई। पिछली सरकार द्वारा पांचवीं व आठवीं की कक्षाओं की बोर्ड की परीक्षायें समाप्त कर दिये जाने के कारण प्रदेश में शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया था और जब कोई विद्यार्थी नौंवीं कक्षा से पास होकर दसवीं कक्षा में दाखिला लेता था तो उसको अपने हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे। आज बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ लिखकर उच्च कक्षाओं में जायेंगे तो वे अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मेरे हल्के नीलोखेड़ी में जो एक पॉलिटैक्निक थी उसको इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्ज़ा दिया इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं क्यांकि यह हमारे क्षेत्र की एक बहुत लम्बे अरसे से मांग थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बधाई भी देता हूं। पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और जिला परिषद् में पढ़े लिखे लोग आयें और गांव, तहसील वह जिला स्तर पर उनके द्वारा अपनी भूमिका अच्छी प्रकार से निभाई जाये इसके लिए हमारी सरकार ने जो कानून बनाया यह भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सराहनीय, प्रशंसनीय और एतिहासिक कदम है। इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में निकलकर आयेंगे और पंचायत समिति, ब्लॉक समिति और जिला परिषद् में पढ़े लिखे लोग अच्छे से अच्छा काम करेंगे। पिछली सरकारों ने व्यपारियों पर चोरी-छिपे अनावश्यक टैक्स लगाये हुये थे। ऐसा करके समस्त व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ने का काम पिछली सरकारों द्वारा किया गया था। हमारी सरकार ने सत्ता सम्भालने के बाद ऐसे कदम उठायें हैं जिनसे पीड़ित व्यापारियों को बहुत ज्यादा राहत मिली है। व्यापारी वर्ग को अनावश्यक टैक्सों के बोझ से भी मुक्ति दिलाई गई है। अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 28 सड़कें ऐसी थी जो पिछले बहुत लम्बे समय से बहुत ज्यादा जर्जर हालत में थी। आज की डेट में इन सभी सड़कों की मुरम्मत का काम शुरू हो चुका है। पिछली सरकारों के समय में केवल मात्र घोषणायें ही होती थी लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी कथनी और करनी को वास्तविक रूप में एक साबित कर दिया है। इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे हल्के के तरावड़ी शहर में जी.टी. रोड पर एक अण्डरपास या ओवरब्रिज की एक लम्बे समय से मांग थी जिसके अभाव में पूरा तरावड़ी शहर दो भागों में विभाजित था। हमारी इस मांग को भी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकार किया गया है और जिसके ऊपर जल्द ही कार्य शुरू होने वाला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मेरे हल्के में स्थित कन्या गुरूकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाली हमारी बेटियों के लिए दो करोड़ रूपये की राशि अनुदान के रूप में दी है, इससे हमारी बेटियों का भविष्य उज्ज्वल होगा। तरावड़ी, निगदू और नीलोखेड़ी में बड़े लम्बे समय से बस स्टैण्ड की मांग थी हमारी इस मांग को भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के के अंजनथली और डाक्कर के स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ-साथ जो नीलोखेड़ी में 50-60 पुरानी पाईप लाईन्स थी जिनके कारण नगरवासियों को मज़बूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा था। इन पाईप्स को भी लगभग आठ करोड़ रूपये की लागत से बदलवाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जो कि जल्दी ही पूरा हो जायेगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे हल्के में भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी द्वारा 17 वर्ष पूर्व एक कालेज की नींव का पत्थर रखा गया था लेकिन इतने समय के बावजूद भी वह पत्थर ही लगा हुआ है उसके ऊपर अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं

माननीय शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस कॉलेज का भी निर्माण करवाया जाये ताकि मेरे हल्के के छात्र और छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा के लिए दूसरे शहरों में धक्के खाने के लिए मज़बूर न होना पड़े। माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिन्द।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास स्वरचित कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं इसलिए उनको 2 मिनट का समय अपनी कविता पढ़ने के लिए दे दिया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : ठीक है। अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : हाँ जी, हाँ जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा(पुनरारम्भ)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रेवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ वह महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर ही आधारित है और उसकी रचना मैंने इसी सदन में इसी टेबल पर की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ और इस गौरवमयी महान् सदन को अपना शीश झुकाता हूँ।

कानून-व्यवस्था बहाल हुई अब, भाईचारा बढ़ना चाहिए,

हरियाणा-एक, हरियाणवी-एक यह भाव जगाना चाहिए,

शांति पुन: स्थापित हो, अब प्रेम बढ़ाना चाहिए।

आरक्षण की आग बुझेगी, जब ये भाव आ जायेगा,

श्वेत-पत्र 36 बिरादरी का जब सामने आ जायेगा,

सदा-सदा के लिए आरक्षण का समाधान हो जायेगा,

फिर आर्थिक आरक्षण का रास्ता स्वयं खुल जायेगा।

रावी-व्यास के पानी पर, पंजाब ने पाप कमाया है,

छोटे भाई का गला दबा काला कानून बनाया है।

अब धर्म हमारा बनता है, केन्द्र को जा कर बतायेंगे,

कानूनी सहायता पाने को कोर्ट में हम भी जायेंगे।

[श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास]

"बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ" नारी सम्मान कराया है,

लिंगानुपात की खाई भर, मोदी जी ने मान बढ़ाया है।

गौसंवर्धन, गौसंरक्षण दे, फसल मुआवजा दे किया बड़ा काम,

किसान की आमदनी दोगुनी होगी, फिर बढ़ेगी हरियाणा की शान।

ग्राम पंचायतें शिक्षित हो गई, युवा प्रतिनिधि करें कमाल,

सड़क सुधर रही हरियाणा की, हाईवे का बिछ रहा जाल।

देश-विदेश से आये निवेशक, उद्योग क्रान्ति का अलख जगा,

बिजली मिलेगी 24 घंटे, जगमग-जगमग गांव जगा।

कुरूक्षेत्र में महाभारत युद्ध के महानायक थे योगेश्वर कृष्ण भगवान,

अब सभी सरोवरों का विकास होगा, थीम पार्क कम्पलैक्स का होगा काम।

सिंधु दर्शन कैलाश मानसरोवर की यात्रा की विभूतियाँ सहायता बढ़ा दी हैं,

सरस्वती के उदगम स्थल की विकास योजना चला दी है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी कविता पढ़ने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी साथियों का सुनने के लिए भी धन्यवाद।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने अपनी कविता में कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का रास्ता साफ हो जायेगा। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष क्लीयर करे कि वह जातिय आरक्षण के पक्ष में है या आर्थिक आधार पर आरक्षण के हक में है।

श्री अध्यक्ष : रविन्द्र जी, यह बात तो इनकी कविता तक ही सीमित है।

श्री हरिचन्द मिढ़ढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी लिखित स्पीच सदन के पटल पर रख देता हूं। आप इसे सदन की कार्यवाही में एड करवा लें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप अपनी लिखित स्पीच दे दें।

(इस समय लिखित स्पीच सदन के पटल पर रखी गई।)

***श्री हरिचन्द मिढ़ढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे महामहिम के अभिभाषण पर चर्चा करने का वक्त दिया, महोदय, महामहिम के अभिभाषण के पैरा न० 5 में जैसा कि दर्शाया गया है कि प्रदेश में अंशान्ति के दौरान प्रदेश के व्यापारियों को भारी नुक्सान हुआ है।

---

* चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को सदन की कार्यवाही में ऐड किया गया।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या कारण था कि पंजाबी समुदाय के लोगों की दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1947 का भारत-पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ उस वक्त अपने धर्म और देश के लिए गर्व से अपने सभी कारोबार, जमीन, गहने, मकान आदि छोड़कर अपने वतन लौटे थे।

अध्यक्ष महोदय, एक तरह वहां से उजड़ कर अपने तन पर एक कपड़ा लेकर वतन लौटे थे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाये और अपनी मेहनत के बल पर प्रदेश में एक मुकाम पाया, मगर आज कलेजा भर आता है कि किस तरह से उनके आशीयानों को जलाया गया।

अध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिए कि एक कलम से उन व्यापारियों को जल्द से जल्द राहत नहीं अपितु तमाम हुए नुकसान की भरपाई करें।

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा हैपनिंग की बात कही गई, मगर जीन्द उद्योग की दृष्टि में काफी पिछड़ा हुआ है। अत: इस बजट सत्र में जीन्द में उद्योग स्थापित करने का विशेष पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आदर्श ग्राम योजना की बात महामहिम के अभिभाषण में की गई। वर्ष 2015 दिनांक 30-07-2015 को मैंने आपके विधानसभा क्षेत्र का गांव जाजवान गोद लिया, मगर आज तक उस गांव में एक भी अधिकारी नहीं गया जबकि मैंने बार-बार संबंधित अधिकारियों से मीटिंग करने की बात कही है। ऐसे में सरकार आदर्श गांव बनाने की बात करती है।

अध्यक्ष महोदय, पैरा न० 43 में जैसा कि महामहिम के अभिभाषण में दर्शाया गया है कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को सस्ती, सुलभ, उचित और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है, मगर जीन्द के एकमात्र सिविल अस्पताल में आज भी 40 प्रतिशत डॉक्टरों की कमी है एक भी एम.आर.आई. तथा सी.टी. स्कैन मशीन नहीं है, एक्सरे की एक मशीन डिजीटल है उसको भी चलाने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, जीन्द का सामान्य अस्पताल एक रफैरल केन्द्र बनकर रह गया है जिसको प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वीकारा है।

अध्यक्ष महोदय, सड़कों के जाल का जिक्र महामहिम के अभिभाषण में किया गया, मगर जीन्द शहर का बाईपास वर्ष 2008 से निर्माणधीन है, जिसमें करोड़ों रुपये की मिट्टी धूल बन कर उड़ गई उस बाईपास का निर्माण कार्य भी जल्दी से करवाया जाए तथा क्षेत्र की बदहाल सड़कों की भी सुध ली जावे।

अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की बात कही गई, मगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गांव बडौदी, ढांढ खेडी, जाजवान, झांझकलां-खुर्द, बरसोला तथा रायचन्दवाला कई ऐसे गांव हैं जो पेयजल के लिए तरस रहे हैं। क्या इन गांव के लिए स्वच्छ पेयजल के लिए वित वर्ष 2016-17 में कोई प्रावधान किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय, जीन्द शहर की सीवरेज व्यवस्था ठप्प है जहां पब्लिक हैल्थ विभाग में कर्मचारियों का भी अभाव है कई कालोनियाँ तो नियमित कोलोनियां हैं, उनमें प्रमुख रूप से जैन

[श्री हरिचन्द मिढ्ढा]

नगर, दुर्गा कॉलोनी, राम कॉलोनी, विजय नगर, न्यू एम्पलाईज कॉलोनी, न्यू कृष्णा कॉलोनी आदि प्रमुख हैं।

अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार जीन्द की सीवरेज व्यवस्था को दुरूस्त करने का काम करेगी ? जब नेता सदन में जवाब दें, मुझे जरूर भरोसा दे कि इस विषय पर सरकार की मंशा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, 'थारी पेंशन-थारे पास' सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसका जिक्र महामहिम के अभिभाषण में भी किया गया है, मगर इस योजना के बाद भी बुढ़ापे में बुजुर्गों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। यह चौ0 देवीलाल जी की सम्मान पेंशन ना रह कर बुजुर्गों के गले का फांस बन गई है।

अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार हर गांव में बैंक खोलकर बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेगी या फिर बुजुर्गों के घरों में पहुंचाने का काम करेगी ?

अध्यक्ष महोदय आप ने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश बड़वा : अध्यक्ष महोदय, कापड़ीवास जी ने इतनी बढ़िया कविता सुनाई है हम उनका धन्यवाद करते हैं। उस कविता में उन्होंने आरक्षण का जिक्र किया है इसलिए मुझे भी दो लाईनें याद आ गई हैं इसलिए मैं भी सुनाना चाहता हूँ :-

मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी,

समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी।

आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी,

लूट कर घर भर रहा है आदमी।

दुश्मनों से दोस्ती तो दूर,

दोस्तों से दुश्मनी करने लगा है आदमी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब यह सदन दिनांक 17 मार्च, 2016, प्रात : 10 :00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

*14:20 बजे (तत्पश्चात सदन की बैठक वीरवार 17 मार्च, 2016, प्रात: 10:00 बजे तक स्थगित हुई।)

54377—H.V.S.—H.G.P.,Chd.

© 2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.